कांग्रेस नेता राहुल गांधी राष्ट्रीय विरोधी... 12

राष्ट्रीय शिखर

खबरों की स्वतंत्रता

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, नई दिल्ली, देहरादून और लखनऊ से एक साथ प्रसारित

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

फिल्म बनाने के लिए प्रियंका ने किया... 11

वर्ष - 01, अंक - 324 | गाजियाबाद / बुधवार 25 फरवरी 2026 | PRGI No. - UPHIN/25/A0086 | पृष्ठ-12, मूल्य - 04 रूपए

पश्चिम बंगाल का नाम भी बदले केंद्रः ममता

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केरल का आधिकारिक नाम केरलम करने के केंद्र सरकार के फैसले पर खुशी जताई है, लेकिन साथ ही पश्चिम बंगाल के नाम बदलकर बांग्ला करने की लंबित मांग पर नाराजगी भी व्यक्त की है। ममता बनर्जी ने कहा कि वे केरल के भाइयों-बहनों को इस फैसले पर हार्दिक बधाई देती हैं, क्योंकि यह राज्य की भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने वाला कदम है। ममता बनर्जी ने कहा, "कई राज्यों के नाम तब बदले जाते हैं, जब संबंधित राज्य सरकारें ऐसे प्रस्ताव मंजूर करती हैं।

कॉकपिट में आग लगने की कोई चेतावनी नहीं थी। हवाई अड्डे के सूत्रों के अनुसार, विमान के इंजन में संभावित खराबी थी, जो संभवतः दूसरे इंजन से संबंधित थी। पिछले साल नवंबर में मुंबई से कोलकाता जा रही स्पाइसजेट की एक उड़ान को इंजन में खराबी आने के कारण इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। विमान के सभी यात्री और चालक दल सुरक्षित थे। स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने बयान में बताया था कि 9 नवंबर को, मुंबई से कोलकाता जा रही स्पाइसजेट की उड़ान एसजी670 में कोलकाता हवाई अड्डे पर उतरते समय तकनीकी खराबी आ गई। विमान सुरक्षित रूप से उतर गया। सभी यात्री और चालक दल के सदस्य सामान्य रूप से प्लेन से उतर गए।

निधि छिब्बर बनी नीति आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी

नई दिल्ली (एजेंसी)। बीवीआर सुब्रह्मण्यम का तीन साल का कार्यकाल मंगलवार को पूरा होने के बाद सरकार ने निधि छिब्बर को नीति आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) का अतिरिक्त प्रभार दिया है। छिब्बर वर्तमान में नीति आयोग के विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) की महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं। मौजूदा समय में वह केंद्र सरकार की कई प्रमुख योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन करके उनके प्रदर्शन और प्रभाव का आकलन करने के लिए जिम्मेदार हैं। छत्तीसगढ़ कैडर की 1994 बैच की आईएएस अधिकारी छिब्बर ने अपने करियर में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। इससे पहले वे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की अध्यक्ष रह चुकी हैं, जहां उन्होंने प्रमुख सुधारों और परीक्षा प्रक्रियाओं की देखरेख की। उनके पास इतिहास में स्नातकोत्तर और विधि स्नातक (एलएलबी) की डिग्री है, और उनकी अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ है।

भारतीय सेना की 'अग्नि वर्षा', वास्तविक युद्ध जैसी परिस्थितियों में युद्धाभ्यास

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय सेना 24 फरवरी से अग्नि वर्षा शुरू कर रही है। इस 'अग्नि वर्षा' में आधुनिक टैंक, तोप, ड्रोन, रोबोट, मिसाइल, हेलिकॉप्टर व हवाई शक्ति शामिल है। दरअसल 'अग्नि वर्षा' भारतीय सेना का एक बड़ा युद्धाभ्यास है। भारतीय सेना के मुताबिक 'अग्नि वर्षा' अभ्यास वास्तविक युद्ध जैसी परिस्थितियों में किया जा रहा है। 24 फरवरी को भारतीय सेना की दक्षिणी कमान के तत्वावधान में रेगिस्तानी क्षेत्र में यह महत्त्वपूर्ण सैन्य युद्धाभ्यास 'अग्नि वर्षा' आयोजित किया जा रहा है। इस व्यापक युद्धाभ्यास का उद्देश्य सेना की ऑपरेशनल तैयारी, संयुक्त युद्धक क्षमता और आधुनिक युद्ध प्रणाली की प्रभावशीलता का परीक्षण करना है। रेगिस्तान की कठिन परिस्थितियों में सेना की विभिन्न शाखाएं इस युद्धाभ्यास का हिस्सा बनी हैं। इनमें पैदल सेना, सेना की बख्तरबंद कोर, तोपखाना, वायु रक्षा और संचार इकाइयां शामिल हैं। सेना की यह विभिन्न इकाइयां इस युद्धाभ्यास में एकीकृत रूप से भाग लेंगी। इसका मुख्य फोकस सभी हथियारों का समन्वित उपयोग करना है। यहां लंबी दूरी की सटीक मारक क्षमता का युद्धक अभ्यास व परीक्षण किया जाएगा। नेटवर्क आधारित कमांड एवं कंट्रोल सिस्टम को परखा जाएगा।

श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 1,677 करोड़ रुपए में बनेगा सिविल एन्क्लेव

नई दिल्ली (एजेंसी)। कश्मीर घाटी में विमानन बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में केंद्र सरकार ने मंगलवार को एक बड़ा कदम उठाया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 1,677 करोड़ रुपए की लागत से सिविल एन्क्लेव के विकास को मंजूरी दी। परियोजना के दायरे में सुरक्षा कर्मियों के लिए बैरकों (आवास) का निर्माण भी शामिल है। करीब 73.18 एकड़ क्षेत्र में बनने वाला नया सिविल एन्क्लेव एक अत्याधुनिक टर्मिनल भवन से लैस होगा, जिसका कुल क्षेत्रफल 71,500 वर्ग मीटर होगा, जिसमें 20,659 वर्ग मीटर मौजूदा ढांचा शामिल है।

ग्रामीण वेग वृद्धि परियोजना को 677.75 करोड़ की मंजूरी

महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष जोर, 2.5 लाख 'लखपति दीदी' बनाने का लक्ष्य

- सचिव डीएस गब्रियल ने वर्ष 2025-26 की प्रगति एवं अनुपालन रिपोर्ट की प्रस्तुत
- कृषि तथा सहायक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर दिया जोर

देहरादून (एजेंसी)। मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में ग्रामीण वेग वृद्धि परियोजना (रीप) की उच्चाधिकार एवं मार्गदर्शन समिति की बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 677.75 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट को मंजूरी दे दी गई।

मंगलवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में सचिव डीएस गब्रियल ने वर्ष 2025-26 की प्रगति एवं अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए आगामी वित्तीय वर्ष की प्रस्तावित कार्ययोजना का विस्तृत विवरण रखा। स्वीकृत कार्ययोजना में स्वरोजगार, आजीविका संवर्धन, आय सृजन गतिविधियों, स्थानीय संसाधन विकास, कृषि तथा सहायक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है। समिति ने संबंधित कार्यक्रमों को वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए इनके प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने निर्देश देते हुए कहा कि परियोजना से लाभान्वित महिलाओं को केंद्र एवं राज्य सरकार की अन्य योजनाओं से जोड़ा जाए और योजनाओं के बीच प्रभावी कन्वर्जेंस सुनिश्चित किया जाए। लाभार्थियों के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण के लिए समेकित कार्ययोजना तैयार करने और ठोस मॉनिटरिंग व्यवस्था विकसित करने पर बल दिया गया।

मुख्य सचिव ने समान प्रकृति के महिला स्वयं सहायता समूहों की पहचान कर उन्हें स्वरोजगार एवं आय सृजन के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की रणनीति तैयार करने के निर्देश भी दिए। वर्ष 2026 को अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में ध्यान में रखते हुए महिलाओं को वित्तीय, तकनीकी, पूंजीगत एवं संस्थागत सहयोग उपलब्ध कराने की विस्तृत योजना बनाने को कहा गया। ग्रामीण क्षेत्रों में अनुपयोगी पड़े ग्रोथ सेंटरों को सक्रिय करने पर भी बैठक में चर्चा हुई।

मुख्य सचिव ने ऐसे ग्रोथ सेंटरों की पहचान कर उन्हें हाउस ऑफ हिमालय के माध्यम से प्रभावी उपयोग में लाने की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।

लघु उद्यमों को वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण किया जाता है प्रदान

उल्लेखनीय है कि ग्रामीण उद्यम त्वरण परियोजना (ग्रामोत्थान) राज्य के सभी जनपदों में ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुदृढ़ करने और पलायन रोकने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। परियोजना के तहत कृषि, गैर-कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े लघु उद्यमों को वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। बैठक में अपर सचिव गिरधारी सिंह रावत, नवनीत पांडेय, झरना कमठान सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

केंद्रीय कैबिनेट में मंगलवार को लिए बड़े फैसले, विकास कार्यों को मंजूरी

केरल का नाम अब होगा केरलम

नई दिल्ली (एजेंसी)।

केंद्र सरकार ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए केरल का नाम बदलकर 'केरलम' करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने इस फैसले को लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने वाला कदम बताया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने संबोधन में कहा कि कैबिनेट में लिए गए अहम फैसलों में सबसे प्रमुख निर्णय केरल का नाम बदलकर 'केरलम' करना है। उन्होंने बताया कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के बाद से ही यह मांग उठती रही है कि राज्य का आधिकारिक नाम उसकी स्थानीय भाषा के अनुरूप होना चाहिए। मलयालम भाषा में राज्य को 'केरलम' कहा जाता है, इसलिए लंबे समय से यह मांग की जा रही थी कि आधिकारिक रूप से भी राज्य का नाम 'केरलम' किया जाए।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह केवल केंद्र का एकतरफा निर्णय नहीं है, बल्कि इसके लिए एक निर्धारित संवैधानिक और प्रशासनिक प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

केरल का नाम 'केरलम' करने के प्रस्ताव सीपीआई ने जताई खुशी

केंद्रीय कैबिनेट ने राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर 'केरलम' करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसको लेकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीआई) ने केरल के लोगों को हार्दिक बधाई दी है। 'केरलम' नाम मलयालम भाषा में राज्य का मूल और प्राकृतिक रूप है, जिससे राज्य की सभ्यता की निरंतरता और सामूहिक आत्म-सम्मान जुड़ा हुआ है। सीपीआई ने बताया कि यह बदलाव केरल के लोगों की लंबे समय से चली आ रही लोकतांत्रिक मांग का परिणाम है। यह कॉलोनियल काल के अंग्रेजीकरण को सुधारने वाला कदम है, जो भारत की बहुभाषी और संघीय संरचना की पुष्टि करता है। केरल विधानसभा ने जून 2024 में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के प्रस्ताव पर एकमत से केंद्र सरकार से नाम बदलने की अपील की थी। यह प्रस्ताव राज्य में सभी वर्गों और राजनीतिक दलों के बीच व्यापक सहमति का प्रतीक था, जो लोगों की लोकप्रिय इच्छा को दर्शाता है।

कच्चे जूट के लिए प्रति क्विंटल 275 रुपए का एमएसपी में इजाफा

केंद्र सरकार ने मंगलवार को कच्चे जूट के लिए एमएसपी बढ़ाने का ऐलान किया। इससे जूट से जुड़े किसानों को अपनी फसल पर पहले के मुकाबले अधिक मुनाफा कमाने में मदद मिलेगी। विपणन सत्र 2026-27 के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गठित आर्थिक कार्य मंत्रिमंडलीय समिति में दी गई। आधिकारिक बयान में कहा गया कि 2026-27 सीजन के लिए कच्चे जूट (टीडी-3 ग्रेड) का एमएसपी 5,925 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।

9,072 करोड़ रुपए की मल्टी-ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को दी मंजूरी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने मंगलवार को चार राज्यों में तीन मल्टी-ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं पर कुल 9,072 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इन परियोजनाओं में गोंदिया-जबलपुर रेल लाइन का दोहरीकरण, पुनारख-किउल तीसरी और चौथी लाइन तथा गम्हरिया-चांडिल तीसरी और चौथी लाइन शामिल हैं। ये तीनों परियोजनाएं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड के आठ जिलों को कवर करेंगी, जिससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 307 किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी, और इन परियोजनाओं को 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

पायलट की सूझ-बूझ से टला बड़ा हादसा, सभी यात्री सुरक्षित

लेह (एजेंसी)। स्पाइसजेट की मंगलवार को लेह जा रही फ्लाइट को तकनीकी खराबी के बाद वापस दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड कराया गया। सभी यात्रियों को विमान से सुरक्षित उतार लिया गया है। स्पाइसजेट की बोइंग 737 विमान की उड़ान एसजी121 के चालक दल को खराबी का पता चला, जिसके बाद फ्लाइट को वापस लौटना पड़ा। स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने बताया कि मंगलवार को दिल्ली से लेह जा रही स्पाइसजेट की एक उड़ान तकनीकी खराबी के कारण वापस लौट आई। विमान दिल्ली में सुरक्षित उतर गया और सभी यात्रियों को सामान्य रूप से उतार लिया गया।

- स्पाइसजेट की लेह जा रही फ्लाइट में तकनीकी खराबी, दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग

कॉकपिट में आग लगने की कोई चेतावनी नहीं थी। हवाई अड्डे के सूत्रों के अनुसार, विमान के इंजन में संभावित खराबी थी, जो संभवतः दूसरे इंजन से संबंधित थी। पिछले साल नवंबर में मुंबई से कोलकाता जा रही स्पाइसजेट की एक उड़ान को इंजन में खराबी आने के कारण इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। विमान के सभी यात्री और चालक दल सुरक्षित थे। स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने बयान में बताया था कि 9 नवंबर को, मुंबई से कोलकाता जा रही स्पाइसजेट की उड़ान एसजी670 में कोलकाता हवाई अड्डे पर उतरते समय तकनीकी खराबी आ गई। विमान सुरक्षित रूप से उतर गया। सभी यात्री और चालक दल के सदस्य सामान्य रूप से प्लेन से उतर गए।

पीएम मोदी आज पहुंचेंगे इजरायल

डिफेंस, एआई समेत कई वैश्विक मुद्दों पर होगी अहम चर्चा

नई दिल्ली (एजेंसी)। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय राजकीय दौरे पर बुधवार को इजरायल पहुंचेंगे। इस यात्रा के दौरान देश-विदेश के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसकी जानकारी दी है। प्रधानमंत्री मोदी 25 और 26 फरवरी को इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग से भी मुलाकात करेंगे। यह प्रधानमंत्री का दूसरा इजरायल दौरा है। इस दौरे के दौरान, पीएम मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू भारत-इजरायल के बीच हुई रणनीतिक साझेदारी में हुई अहम तरक्की की समीक्षा करेंगे। दोनों नेता विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, कृषि, जल प्रबंधन, व्यापार और अर्थव्यवस्था समेत पीपुल-टू-पीपुल सहयोग के अवसरों पर चर्चा करेंगे। दोनों

नेताओं के बीच पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा दोनों देशों के बीच गहरी और लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि करेगी और साझा चुनौतियों की समीक्षा करने के साथ-साथ दो सशक्त लोकतंत्रों के बीच एक मजबूत साझेदारी के साझा विजन को पूरा करने की दिशा में प्रयासों को पुनः व्यवस्थित करने का अवसर प्रदान करेगी। इजरायल भी प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत को तैयार है। पीएम नेतन्याहू पहले ही इस यात्रा को ऐतिहासिक करार दे चुके हैं। रविवार को साप्ताहिक कैबिनेट बैठक के दौरान दिए गए अपने वक्तव्य और आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा संदेशों में नेतन्याहू ने इस यात्रा को विशेष बताया। नेतन्याहू ने कहा, "बुधवार को मेरे दोस्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इजरायल पहुंचेंगे। मैं अपनी आंखों के सामने जो विजन देख रहा हूं, उसके हिसाब से हम मिडिल ईस्ट के आसपास या उसके अंदर गठबंधनों का एक पूरा सिस्टम बनाएंगे। ऐसे देशों का एक धुरी समूह, जो वास्तविकता, चुनौतियों और लक्ष्यों को एक नजरिए से देखते हैं और कट्टरपंथी धुरी का सामना करते हैं।"

राजस्थान में 21 आईपीएस अधिकारियों का तबादला

जयपुर के विशेष पुलिस आयुक्त भी बदले

जयपुर (एजेंसी)। राजस्थान सरकार ने 21 आईपीएस अधिकारियों के तबादलों और पदोन्नति के आदेश जारी किए हैं, जिससे राजस्थान भर में महत्वपूर्ण पदों पर बड़े बदलाव हुए हैं। अधिकांश फेरबदल हाल ही में आईपीएस अधिकारियों की पदोन्नति के बाद हुए हैं। सोमवार देर रात जारी एक आदेश में जोधपुर के पुलिस आयुक्त और जयपुर के विशेष पुलिस आयुक्त को बदल दिया गया है। महानिरीक्षक (आईजी) एसओजी शरत कविराज को जोधपुर का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। जोधपुर के पुलिस आयुक्त ओम प्रकाश का तबादला जयपुर के विशेष आयुक्त के रूप में कर दिया गया है। जयपुर के विशेष पुलिस आयुक्त राहुल प्रकाश को जयपुर रेंज का आईजी नियुक्त किया गया है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और कोटा के रेंज आईजी का तबादला कर दिया गया है। सत्येंद्र सिंह को आईजी (सीआईडी-सीबी) से स्थानांतरित करके जोधपुर रेंज का आईजी बनाया गया है। ओम प्रकाश का तबादला पुलिस सशस्त्र बटालियन से बीकानेर रेंज के आईजी के पद पर कर दिया गया है।

इस प्रकार हुए अधिकारियों के तबादले

बीकानेर रेंज के आईजी हेमंत कुमार शर्मा को जयपुर में एससीआरबी के आईजी के रूप में तैनात किया गया है। अजय पाल लांबा का तबादला आईजी, एससीआरबी जयपुर से आईजी, एसओजी जयपुर के पद पर कर दिया गया है। इसके साथ ही कई वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को पदोन्नत किया गया है और उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। एडीजी क्राइम ब्रांच, हवा सिंह घुमारिया को एडीजी मुख्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया है। विपिन कुमार पांडे को पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड (मुख्यालय) के एडीजी पद से पदोन्नत करके राजस्थान क्राइम ब्रांच का एडीजी बनाया गया है।

आईआईटी रुड़की में वाटर कॉन्क्लेव का आगाज

दुनियाभर से पहुंचेंगे शोधकर्ता, कई विषयों पर रहेगा फोकस

रुड़की (एजेंसी)। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) रुड़की में 23 फरवरी से 25 फरवरी 2026 तक चौथे रुड़की वाटर कॉन्क्लेव यानी आरडब्ल्यूसी 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का विषय ट्रांसबाउंड्री वाटर कोऑपरेशन थ्रू नेक्सस अप्रोच है। जिसमें जल प्रबंधन, सहयोग और टिकाऊ विकास पर विशेषज्ञ चर्चा करेंगे।

वाटर कॉन्क्लेव के शुभारंभ मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में नीति आयोग के सदस्य विनोद के पॉल ने वर्चुअली संबोधित किया।

सम्मेलन में देश-विदेश के वैज्ञानिक, नीति विशेषज्ञ और शोधकर्ता जल संसाधनों के बेहतर उपयोग व अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर अपने विचार साझा करेंगे। जबकि, वैज्ञानिक अपने शोधपत्र पेश करेंगे। जिसमें खासकर सीमापार नदी बेसिन प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन एवं सहनशीलता, हाइड्रो-मौसमीय चरम घटनाएं, भूजल स्थिरता, जल गुणवत्ता और जल-ऊर्जा-खाद्य नेक्सस शामिल है।

पहले दिन सत्र का शुभारंभ पारंपरिक दीप प्रज्वलन और कुलगीत की प्रस्तुति से हुआ। जिसके बाद प्रो। आशीष पांडे ने स्वागत उद्बोधन दिया। आईआईटी रुड़की के निदेशक प्रो। कमल किशोर पंत, डॉ. वाईआरएसराव और डॉ. मार्क स्मिथ महानिदेशक अंतरराष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान (आईडब्ल्यूएमआई) ने भी अपने संबोधन दिए।

विभिन्न देशों से कुल 42 मुख्य वक्ता अपने मुख्य व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे और तकनीकी सत्रों में हिस्सा लेंगे। ये वक्ता संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल, नीदरलैंड, कनाडा, जापान, नॉर्वे, श्रीलंका, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान और नेपाल समेत अंतरराष्ट्रीय संगठनों के विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व करेंगे। इन विशिष्ट वक्ताओं की उपस्थिति वैश्विक दृष्टिकोण और वर्तमान जल प्रबंधन चुनौतियों के साथ नवाचारी समाधानों पर अहम अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी।

दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर पर रिकॉर्ड राइडरशिप

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के शेष खंडों तथा मेरठ मेट्रो के उद्घाटन के बाद पहले पूर्ण संचालन दिवस पर अभूतपूर्व राइडरशिप दर्ज की गई। पूरे कॉरिडोर पर सोमवार को एक ही दिन में 1 लाख से अधिक यात्रियों ने सफर किया, जो अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। इससे पहले इस कॉरिडोर पर औसतन प्रतिदिन लगभग 60,000 यात्री यात्रा कर रहे थे। नए रिकॉर्ड के साथ राइडरशिप में करीब 70 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। कॉरिडोर का सबसे व्यस्त स्टेशन मेरठ शहर के मध्य स्थित बेगमपुल रहा, जहां सबसे अधिक यात्री संख्या दर्ज की गई।

दिल्ली-एनसीआर में सवा सौ स्थानों पर प्रदूषण नियमों का उल्लंघन मिला

नई दिल्ली (एजेंसी)। वायु गुणवत्ता प्रबंधन की इंफोर्समेंट टास्क फोर्स 126वीं बैठक का मंगलवार को आयोजन किया गया। बैठक में चार फरवरी से 18 फरवरी के बीच दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण नियमों को लेकर किए गए निरीक्षण कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि चौदह दिनों की इस अवधि के दौरान कुल मिलाकर 318 जगहों का निरीक्षण किया गया और इनमें से 131 स्थानों पर प्रदूषण नियमों का उल्लंघन पाया गया है। आयोग के मुताबिक टास्क फोर्स ने वायु प्रदूषण में मुख्य भूमिका निभाने वाले प्रमुख क्षेत्रों जैसे आद्योगिक इकाइयों, निर्माण एवं ध्वस्तीकरण गतिविधियों, सड़क पर उड़ने वाली धूल, डीजल जेनरेटर सेट, ठोस कचरा निस्तारण और जैव ईंधन जलाने जैसी घटनाओं का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान 318 निरीक्षणों में कुल 131 जगहों पर नियमों का उल्लंघन पाया गया है। इनमें निर्माण व ध्वस्तीकरण स्थलों पर चार उल्लंघन, औद्योगिक क्षेत्रों में 123 उल्लंघन और डीजल सेट नियमों के चार उल्लंघन शामिल हैं। इसे देखते हुए 39 इकाइयों को बंद करने, 10 इकाइयों के डीजी सेटों को सील करने का प्रस्ताव किया गया है। जबकि, 15 इकाइयों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। वहीं, 28 मामलों में अभी आगे की जांच की जा रही है। बैठक में धूल नियंत्रण के उपायों पर विशेष जोर दिया गया। खासतौर पर सड़क की मशीनी सफाई, पानी का छिड़काव आदि पर पर ध्यान केन्द्रित करने को कहा गया।

राजस्व विभाग में 272 अतिरिक्त पदों को एलजी ने मंजूरी दी

नई दिल्ली (एजेंसी)। उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली में राजस्व विभाग में 272 अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। दिल्ली में जिलों और सब-डिवीजनों की संख्या बढ़ने के चलते अतिरिक्त पदों का सृजन किया जा रहा है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने दो नए जिलों के गठन को स्वीकृति दी थी। लोक निवास के मुताबिक उप राज्यपाल ने दिल्ली में नए जिले और सब डिवीजनों को बनाए जाने के मद्देनजर राजस्व विभाग में इन पदों के सृजन को मंजूरी दी है। नए स्वीकृत पदों में दो जिला मजिस्ट्रेट (डीएम), दो अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम), आठ उप विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम), छह सब-रजिस्ट्रार, 16 तहसीलदार-एसओ, 22 नायब तहसीलदार, 42-42 सीनियर असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट, 52 एमटीएस तथा लेखा, योजना, डीएसएस और स्टेनो कैडर के कई पद शामिल हैं। दो नए जिलों के गठन से पहले राजस्व विभाग में 11 जिलों में 1553 स्वीकृत पद थे। 272 नए पदों के सृजन के बाद 13 जिलों में कुल स्वीकृत पदों की संख्या बढ़कर 1825 हो गई है। पता हो कि दिल्ली सरकार की पिछले साल दिसंबर महीने हुई कैबिनेट बैठक में राजस्व जिलों को पुनर्गठित करते हुए इनकी संख्या 11 से बढ़ाकर 13 करने की स्वीकृति दी थी। इसके साथ ही सब-डिवीजनों की संख्या 33 से बढ़ाकर 39 की गई तथा 39 सब-रजिस्ट्रार ऑफिसों की स्थापना का निर्णय लिया गया था। राजस्व विभाग में अतिरिक्त पदों को मंजूरी दिए जाने से फील्ड स्तर के प्रशासन में मजबूती मिलेगी, कर्मचारियों की कमी दूर होगी और नागरिकों को सेवाएं अधिक प्रभावी ढंग से उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

क्रिकेट खेलने को लेकर हुए झगड़े में 15 साल के लड़के की मौत

नई दिल्ली (एजेंसी)। पश्चिम दिल्ली के तिलक नगर इलाके में क्रिकेट खेलने को लेकर तीन नाबालिगों में हुए झगड़े में 15 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि स्थानीय पार्क में क्रिकेट खेलने को लेकर 12 वर्षीय लड़के और 15 वर्षीय पीड़ित के बीच बहस हुई। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया, ''दोनों के बीच बहस के चलते हाथापाई होने लगी। इसके बाद 12 वर्षीय लड़का अपने घर चला गया जहां उसने अपने 17 और 12 वर्षीय रिश्ते के भाइयों को घटना के बारे में जानकारी दी। इसके बाद तीनों किशोर पीड़ित की तलाश में निकल पड़े।' उन्होंने बताया कि शाम सात बजकर करीब 22 मिनट पर उन्हें 15 वर्षीय लड़का मिल गया और उनके बीच मारपीट हुई जिसमें पीड़ित के गले और सिर पर चोटें आईं और वह बेहोश हो गया। पुलिस के मुताबिक, स्थानीय लोग और परिवार के सदस्य उसे दीन दयाल उपाध्याय (डीडीयू) अस्पताल लेकर गए जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। अधिकारी ने बताया, ''हमने इस बाबत तिलक नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की है और सभी तीनों नाबालिगों को पकड़ लिया है। मामले में किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के तहत आगे की कानूनी कार्यवाही जारी है ।' पीड़ित के तीन भाई हैं। उसके पिता की इलाके में ही चाय की दुकान है। अधिकारी ने बताया कि लड़के के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है जिसकी रिपोर्ट आने पर मौत के सटीक कारण का पता चलेगा।

दिल्ली : मेट्रो के आगे कूद कर राजस्थान के 45 वर्षीय व्यक्ति ने दी जान

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली मेट्रो के उत्तम नगर पूर्व स्टेशन पर 45 वर्षीय व्यक्ति ने मंगलवार को ट्रेन के आगे कथित रूप से कूद कर अपनी जान दे दी। पुलिस ने यह जानकारी दी। स्टेशन नियंत्रक से पूर्वाह्न 10 बजकर 12 मिनट पर सूचना मिली की एक व्यक्ति मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन के आगे कूद गया। मेट्रो के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) कुशल पाल सिंह ने बताया, 'यह घटना सुबह नौ बजकर 50 मिनट पर उस समय हुई, जब शख्स प्लेटफॉर्म से पटरियों पर कूद गया और ट्रेन की चपेट में आ गया।' पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान राजस्थान के महाराज के तौर पर हुई है, जो घरों में रंगाई-पुताई का काम करता था और अपनी रिश्तेदार की शादी में शिरकत करने के लिए दिल्ली आया था। शुरुआती जांच में पता चला है कि सिंह कई साल से अवसाद से पीड़ित था और उसका यहां राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इलाज जारी था। डीसीपी ने कहा कि सिंह सोमवार को अस्पताल भी गया था। अधिकारी ने बताया, ''सिंह के परिवार में पत्नी, 18 वर्षीय बेटी और 17 और 20 साल के दो बेटे हैं। शव पोस्टमार्टम के लिए दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल भेजा गया है।'

बाहरी दिल्ली के एमडीसी स्कूल परिसर से चौकीदार का जला हुआ शव मिला

नई दिल्ली (एजेंसी)। नई दिल्ली, 24 फरवरी (वेब वार्ता)। बाहरी दिल्ली के रणहौला इलाके में स्थित एक एमसीडी प्राथमिक विद्यालय के गार्ड कक्ष से 58 वर्षीय चौकीदार का जला हुआ शव मंगलवार को बरामद हुआ। पुलिस ने यह जानकारी दी। मृतक की पहचान नरेश कुमार के रूप में हुई है, जो हरियाणा के रोहतक का निवासी था। पुलिस ने एक बयान में कहा कि वह दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में कार्यरत था और स्कूल में चौकीदार के पद पर तैनात था। बाहरी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) सचिन शर्मा ने बताया कि उसकी सेवानिवृत्ति 2027 में होनी थी। अधिकारी ने कहा, 'स्कूल कर्मचारियों को सुबह करीब 7.45 बजे घटना का पता चला और उन्होंने अधिकारियों को सूचना दी। कुमार की ड्यूटी दोपहर एक बजे से शुरू होती थी और वह गार्ड रूम में रहते थे।' पुलिस ने बताया कि शव पूरी तरह से जला हुआ मिला। पुलिस ने साथ ही यह भी कहा कि आग केवल गार्ड कक्ष में लगी थी और आग लगने का सटीक कारण अब तक पता नहीं चल पाया है। दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) के अनुसार, स्कूल परिसर में आग लगने की सूचना सुबह करीब आठ बजे मिली, जिसके बाद एक टीम को तुरंत मौके पर भेजा गया। डीएफएस के एक अधिकारी ने कहा, 'जब तक हम पहुंचे, आग बुझाई जा चुकी थी। परिसर के निरीक्षण के दौरान, गार्ड कक्ष के अंदर एक जला हुआ शव मिला।' अधिकारी ने बताया कि एक पुलिस दल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है ताकि घटना से पहले की घटनाओं के क्रम का पता लगाया जा सके। पुलिस ने कहा कि मामले में जांच की जा रही है।

दिल्ली में खाली प्लॉट बेचने के बहाने ठगी करने वाला शख्स गिरफ्तार

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली में खाली प्लॉट बेचने के बहाने दो लोगों से करीब 35 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि बेगमपुर एक्सटेंशन निवासी आरोपी दीपक उर्फ टूड़ा, 2025 में विजय विहार थाने में दर्ज एक मामले में वांछित था। मामले की कार्यवाही में पेश न होने के बाद जनवरी में रोहिणी की एक अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, 'दीपक और उसके साथियों ने बेगमपुर में एक खाली प्लॉट बेचने के बहाने दो व्यक्तियों से लगभग 35 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने की साजिश रची। आरोपियों ने कथित तौर पर संपत्ति के जाली दस्तावेज तैयार किए और संभावित खरीदारों के सामने एक व्यक्ति को फर्जी तरीके से मालिक के रूप में पेश किया।' शिकायतकर्ताओं को बाद में पता चला कि संपत्ति के दस्तावेज जाली थे और उनके साथ धोखाधड़ी हुई थी। पुलिस ने बताया कि दो जनवरी, 2025 को मामला दर्ज किया गया था।

मार्च के तीसरे हफ्ते में बजट सत्र, राजनीति पर डिप्लोमा कोर्स शुरू करेगी दिल्ली विधानसभा

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली की आठवीं विधानसभा का बजट सत्र मार्च के तीसरे हफ्ते में आयोजित किया जाएगा। इसकी जानकारी मंगलवार को दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने एक साल पूरे होने पर आयोजित प्रेस कांफ्रेंस के दौरान दी। उन्होंने कहा कि पिछले दो सत्रों की तरह इस बार भी सत्र कागज-रहित होगा।

विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि दिल्ली विधानसभा राजनीति डिप्लोमा कोर्स शुरू करने जा रही है। इस कोर्स का उद्देश्य युवाओं को राजनीति, चुनावी प्रबंधन, नीति निर्माण और संवैधानिक अध्ययनों में प्रशिक्षित करना है। इस तरह की पहल का उद्देश्य लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत भी करना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए युवाओं को राजनीति और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से शामिल होने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का लक्ष्य बिना राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले एक लाख युवाओं को राजनीति में लाना और उन्हें नीति-निर्माण के लिए तैयार करना है। इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली विधानसभा राजनीति डिप्लोमा कोर्स शुरू कर रही है। इसकी रूप-रेखा तैयार की जा रही है।

विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि एक वर्ष में विधानसभा की कार्यसंस्कृति को सुदृढ़ किया है और विधायी परंपराओं को नई मजबूती प्रदान की है। सदन ने मर्यादा, अनुशासन और जनहित से जुड़े विषयों पर सार्थक एवं व्यवस्थित विमर्श को मजबूती दी है। उन्होंने कहा कि इस एक वर्ष में नियमों के अनुपालन, सदस्यों को समान अवसर, जनहित से जुड़े विषयों पर प्रभावी चर्चा तथा विधायी प्रक्रियाओं को अधिक सशक्त बनाने की दिशा में कई उल्लेखनीय पहल की गईं। दिल्ली विधानसभा ने कार्यकुशलता, जवाबदेही और संवैधानिक मूल्यों के पालन में नई ऊंचाइयों को छुआ है।

विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की जनता की अपेक्षाओं और विश्वास को केंद्र में रखते हुए सदन को सुचारु, गरिमामय और परिणामोन्मुखी बनाया गया। उन्होंने कहा कि विधानसभा को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके हरित क्षेत्र को 20 फीसद से बढ़ाकर 50 किया जा रहा है। विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि दिल्ली विधानसभा के अंदर केंद्र सरकार के जो दफ्तर थे, उसे खाली करा दिया गया है। विधानसभा अब उन खाली स्थानों का उपयोग अपने मुताबिक करेगी।

टॉप 25 चेंजमेकर्स ऑफ 2025 में शामिल हुईं आईडीईएस शोभा गुप्ता

नई दिल्ली (शिखर समाचार) देश के प्रशासनिक तंत्र में उत्कृष्ट नेतृत्व, नवाचार और जनसेवा के प्रति समर्पण के लिए आईडीईएस शोभा गुप्ता का टॉप 25 चेंजमेकर्स ऑफ 2025 ब्यूरोक्रेट्स ऑफ इंडिया सूची में किया गया है। यह उपलब्धि प्रशासनिक सेवा में उनके उत्कृष्ट कार्यों और जनहित के प्रति समर्पण का महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सम्मान मानी जा रही है। यह प्रतिष्ठित सूची उन 25 अधिकारियों को सम्मानित करती है जिन्होंने अपने कार्यों के माध्यम से जनकेंद्रित प्रशासन, संस्थागत सुदृढ़ीकरण तथा प्रभावी नीति क्रियान्वयन में उल्लेखनीय योगदान दिया है। शोभा गुप्ता ने अपने कार्यकाल में प्रशासनिक दक्षता, प्रभावी नेतृत्व और जनकल्याणकारी

सोच का परिचय देते हुए शासन व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उनके प्रयासों से प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और नवाचार को बढ़ावा मिला है तथा नागरिकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के प्रयास सफल रहे हैं। उनकी कार्यशैली में सुशासन और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जिसके कारण वे एक प्रेरणादायक अधिकारी के रूप में स्थापित हुई हैं।

देशभर में रक्षा भूमि के बेहतर प्रबंधन, छावनियों के नागरिक प्रशासन तथा पारदर्शी शासन व्यवस्था को मजबूत करने में उनके योगदान को विशेष रूप से सराहा गया है। उत्कृष्ट ब्यूरोक्रेट के रूप में मिली यह उपलब्धि उनके समर्पण और कार्यकुशलता का प्रमाण है।

उन्हें इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए उनके उज्वल भविष्य की कामना की गई है। विश्वास व्यक्त किया गया है कि वे आगे भी अपने नेतृत्व और सेवा भावना से राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देती रहेंगी।

भाजपा ने उदयभानु चिब मामले में न्यायालय के फैसले का किया स्वागत

नई दिल्ली (एजेंसी)। भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मंगलवार को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के एआई शिखर सम्मेलन में कांग्रेस के प्रदर्शन मामले में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभानु चिब को चार दिन की पुलिस कस्टडी में भेजे जाने के फैसले का स्वागत किया। वीरेंद्र सचदेवा ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि उदयभानु राहुल गांधी के इशारे पर एआई शिखर सम्मेलन में जिस प्रकार का कुकृत्य किया है, वह भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास है। इस पर न्यायलय ने उदयभानु की चार दिन की पुलिस कस्टडी स्वीकार कर ली है। विश्व पटल पर भारत को बदनाम करने का प्रयास करने वाले आज खुद राजनीतिक रूप से नगण्य हो चुके हैं। सचदेवा ने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस के भस्मासुर हैं जिनके इशारे पर उनके किराये के कार्यकर्ता खुद कांग्रेस को डूबाने पर उतारू हैं। उन्होंने कहा कि एआई शिखर सम्मेलन किसी राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम नहीं था और न ही किसी व्यक्ति विशेष का कार्यक्रम था बल्कि विश्वभर में भारत की गौरवगाथा का कार्यक्रम था। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि भारत के वे युवा जो एआई के माध्यम से नए-नए इनोवेशन देश-विदेश में ला रहे हैं, उसके प्रदर्शन का मामला था कि कैसे भारत विश्व गुरु बनने की ओर जा रहा है लेकिन राहुल गांधी के गुंडों ने जो हरकत की है, वह शर्मसार करने वाली है। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि कांग्रेस का बड़े नेता भी इस साजिश में शामिल है। उन्होंने कहा कि यह महज संयोग नहीं है बल्कि जब-जब देश की छवि और प्रतिष्ठा बढ़ रही होती है, तब कांग्रेस और उसके समर्थक दल इस तरह के कुकृत्य करते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब अपनी पिछली विजिट के वक्त भारत आए थे तो उस वक्त उमर खालिद द्वारा प्रदर्शन किया गया था और आज जब 22 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आये थे तो उस वक्त भी कांग्रेस का इस तरह का कुकृत्य अशोभनीय है और अक्षम्य है।

दिल्ली में पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट हुआ शुरू

-लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने पहले ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट का किया उद्घाटन

नई दिल्ली (एजेंसी)। वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन और सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ बनाने की दिशा में दिल्ली सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने मंगलवार को राजधानी के पहले ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट (हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र) का उद्घाटन किया। पीडब्ल्यूडी द्वारा दिल्ली में विकसित किए गये इस प्लांट में सड़कों के किनारे उत्पन्न होने वाले बागवानी (हॉर्टिकल्चर) कचरे को प्रोसेस कर खाद में बदला जाएगा और उसे दोबारा हरित कार्यों में उपयोग किया जाएगा। इस अवसर पर मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली में विभिन्न आरडब्ल्यूए, स्कूलों और स्थानीय निवासियों द्वारा लंबे समय से उठाई जा रही चिंता का यह समाधान है। पहले जब भी तूफान, छंटाई या रखरखाव के कारण पेड़ों की टहनियाँ, झाड़ियाँ या हरित कचरा गिरता था, तो वह कई दिनों तक सड़कों के किनारे या खाली जगहों पर पड़ा रहता था। इससे सड़ांध, दुर्गंध और आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी होती थी। इसके अलावा कई बार इनकी वजह से यातायात प्रभावित होने एवं हादसे होने की शिकायतें भी आती थी। इसे लेकर आरडब्ल्यूए और स्कूल लगातार एक व्यवस्थित तंत्र की मांग कर रहे थे। इसलिए अब पीडब्ल्यूडी ने इसका स्थायी समाधान तैयार किया है। उन्होंने बताया कि हजारों किलोमीटर सड़कों पर बड़े स्तर पर बागवानी कार्य होने के बावजूद विभाग के पास वर्षों तक ऐसा एक भी प्लांट नहीं था। पहली बार हमारी सरकार ने यह व्यवस्था बनाई है। अब कचरे को फेंका नहीं जाएगा, बल्कि वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेस कर खाद बनाई जाएगी, जिसका उपयोग फिर हरित कार्यों में होगा। इस पहल के तहत अभी छह ग्रीन वेस्ट प्लांट तैयार किए गए हैं, जबकि अगले चरण में छह और बनाए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि भविष्य में हर जिले में कम से कम एक ऐसा प्लांट स्थापित किया जाए, ताकि कचरे का स्थानीय स्तर पर ही कुशल प्रबंधन हो सके। इन प्लांटों में तैयार होने वाली खाद का उपयोग केंद्रीय वर्ज, सड़क किनारे पौधारोपण और पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आने वाले उद्यानों के रखरखाव में किया जाएगा।

सीपीसीबी के नेटवर्क से जुड़ेंगे नए वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र : सिरसा

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को बताया कि दिल्ली में छह नए वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र शुरू कर दिए गए हैं। एक सप्ताह में सीपीसीबी के नेटवर्क के साथ इन्हीं पूरी तरह से जोड़ दिया जाएगा। सिरसा ने कहा कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की वेबसाइट पर इन केंद्रों पर प्रदूषण के स्तर की लाइव स्थिति या रियल टाइम टाइम डाटा देखा जा सकेगा। सिरसा ने बताया कि अधिकारी इन निगरानी केन्द्रों के प्रदर्शन पर लगातार नजर रखे हुए हैं और एक सप्ताह के भीतर इनका पूरा डाटा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा। सिरसा ने कहा कि नए स्टेशन डाटा आधारित कार्रवाई की दिशा में बड़ा कदम हैं। सीपीसीबी के साथ जुड़ने के बाद दिल्ली में प्रदूषण के कारकों की सही जानकारी मिलेगी। अलग-अलग इलाकों में प्रदूषण के स्तर की सटीक जानकारी से पर्यावरण की बेहतर योजनाएं बनाने में मदद होगी। 14 नए स्टेशन लगाने की भी योजना है ताकि पूरे साल प्रदूषण पर नजर रखी जा सके।

सड़क हादसों की जांच में लापरवाही बरतते हैं पुलिसकर्मी : हाईकोर्ट

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सड़क दुर्घटना के मामलों में दिल्ली पुलिस की जांच प्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। उच्च न्यायालय ने कहा है कि सड़क हादसों के मामलों की जांच में पुलिसकर्मी लापरवाही बरतते हैं। पुलिस के इस रवैये से पीड़ित परिवारों के दोहरे सदमे से गुजरना पड़ता है। पहले अपनों को खोने का गम और फिर मुआवजे के लिए सालों लम्बी कानूनी लड़ाई। मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने राजधानी में बढ़ते सड़क हादसों पर चिंता जताते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया है कि वह मोटर दुर्घटना मामलों की निगरानी व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करें। पीठ ने कहा कि पुलिस आयुक्त सुनिश्चित करें कि पुलिस की रिपोर्टिंग में किसी तरह की लापरवाही न हो। पीठ ने यह आदेश अनूप कुमार रामपाल द्वारा दायर एक जनहित याचिका का निपटारा करते हुए पारित किया है। दरअसल, सुनवाई के दौरान मुद्दा उठा कि सड़क हादसे के पीड़ितों को पुलिस की लापरवाही की वजह से मुआवजा मिलने में तीन से आठ साल तक का समय लग जाता है। रिपोर्ट देरी से दाखिल करने पर दायर की गई याचिका याचिकाकर्ता ने सड़क दुर्घटनाओं की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों द्वारा की जा रही चूकों व देरी को लेकर चिंता जताते हुए यह याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता का कहना था कि दुर्घटना मामलों में जांच अधिकारी समय पर प्रथम दुर्घटना रिपोर्ट (एफएआर), अंतरिम दुर्घटना रिपोर्ट (अईएआर) व विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (डीएआर) दाखिल नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा इन रिपोर्टों की प्रतियां संबंधित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बीमा कंपनियों, पीड़ितों व यहां तक कि दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। पुलिस की वेबसाइट पर नहीं हो रही अपलोड याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि इन रिपोर्टों को दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया जा रहा है। इससे पीड़ितों को समय पर मुआवजे व अन्य कानूनी राहत पाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने इन तथ्यों पर संज्ञान लिया। पीठ ने पाया कि मोटर दुर्घटनाओं से संबंधित रिपोर्टिंग की योजना दिल्ली पुलिस द्वारा लागू की जाती है। पीठ ने कहा कि पुलिस आयुक्त इस याचिका में उठाई गई चिंताओं के संबंध में कानून द्वारा अनिवार्य सभी कदम शीघ्रता से उठाएं। पीठ ने ने स्पष्ट किया कि सड़क दुर्घटना मामलों में रिपोर्टिंग की प्रक्रिया न केवल औपचारिकता है बल्कि इससे पीड़ितों के अधिकार व न्याय से सीधा संबंध जुड़ा है।

पुलिस जांच के मुख्य बिंदु - दुर्घटना की तुरंत व सटीक प्राथमिकी दर्ज करें, जिसमें वाहन का नंबर हो। - घटनास्थल का नक्शा/पंचनामा = पुलिस दुर्घटनास्थल का स्केच और पंचनामा तैयार करती है, जो यह साबित करता है कि दुर्घटना कैसे हुई। - अस्पताल से मेडिकल रिपोर्ट (एमएलसी) या पोस्टमार्टम रिपोर्ट (मौत के मामले में) पुलिस को लेना अनिवार्य है। इसके अलावा गवाहों के बयान, वाहन की यांत्रिकी जांच व चालक के ड्राइविंग लाइसेंस की जांच तफ्तीश का का हिस्सा होती है। समय सीमा है निर्धारित - पुलिस को 48 घंटे के भीतर क्लेम ट्रिब्यूनल को सूचना देनी होती है। - हादसे के 30 दिनों के भीतर ड्राइवर/गाड़ी मालिक की जानकारी देनी होती है। - 50 दिनों के भीतर अंतरिम जांच रिपोर्ट और 90 दिनों के भीतर पूरी फाइनल रिपोर्ट जमा करनी होती है।

एनजीटी ने निधि अंतरण में देरी पर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया

नई दिल्ली (एजेंसी)। नई दिल्ली, 24 फरवरी (वेब वार्ता)। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली सरकार के वन एवं वन्यजीव विभाग को धनराशि अंतरित करने में अत्यधिक देरी को लेकर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। आदेशों का पालन न करने के लिए 'निराधार बहाने बनाने' की 'व्यापक प्रवृति' की निंदा करते हुए एनजीटी ने कहा कि राशि के अंतरण में देरी के कारण 'अस्वीकार्य' हैं। नवंबर 2023 में, अधिकरण ने डीपीसीसी को निर्देश दिया कि वह यहां निलोठी गांव की चार अवैध पत्थर पेराई इकाइयों से पर्यावरण मुआवजे के रूप में एकत्र किए गए आठ लाख रुपये वन और वन्यजीव विभाग को जारी करे। दिल्ली सरकार के इस विभाग को निर्देश दिया गया था कि वह इस धनराशि का उपयोग गांव में वृक्षारोपण के लिए करे। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य अफरोज अहमद की पीठ ने आठ जनवरी के एक आदेश में डीपीसीसी के इस कथन पर ध्यान दिया कि देरी उसके कार्यालय के स्थानांतरण के कारण हुई थी। पीठ ने कहा, ''डीपीसीसी द्वारा वन एवं वन्यजीव विभाग, जीएनसीटीडी को राशि हस्तांतरण में एक वर्ष से अधिक की देरी के लिए दिए गए कारण पूरी तरह से अतार्किक और अस्वीकार्य हैं।'' एनजीटी ने कहा कि उसके आदेश का पालन न करना एक अपराध है जिसके लिए डीपीसीसी अध्यक्ष और सदस्य सचिव पर भी मुकदमा चलाया जा सकता है। उसने कहा, ''लेकिन हम नरम रुख अपनाते हुए इस तरह के मुकदमे का निर्देश देना उचित नहीं समझते। फिर भी, इस अधिकरण द्वारा पारित आदेशों का पालन न करने और इसके लिए निराधार बहाने बनाने की व्यापक प्रवृत्ति को रोकने के लिए, हम डीपीसीसी पर उचित जुर्माना लगाना आवश्यक समझते हैं।'' उसने डीपीसीसी को उसके आदेश का पालन नहीं करने को लेकर 50000 रुपये का जुर्माना भरने को कहा। यह आदेश मंगलवार को सार्वजनिक किया गया।

ग्रामीण दिल्ली को मिलेंगी शहर जैसी सुविधाएं : रेखा गुप्ता

-मुंडका में सड़क-यातायात को बेहतर बनाएंगे कई विकास परियोजनाएं

-मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुंडका में 264 करोड़ रुपये की लागत वाली 49 परियोजनाओं का किया शिलान्यास

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को मुंडका विधानसभा क्षेत्र में लगभग 264 करोड़ रुपए की 49 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन कामों के पूरा होने से इलाके में सडकों और यातायात की सुविधा बेहतर होगी। लोगों को साफ पीने का पानी मिलेगा और सीवर व्यवस्था भी सुधरेगी। साथ ही, स्कूल और स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी, जिससे आम लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि ये सभी योजनाएं ग्रामीण दिल्ली को शहर जैसी सुविधाएं देने की दिशा में बड़ा कदम हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि ग्रामीण क्षेत्र में पिछले एक वर्ष में लगभग 1600 करोड़ के विकास कार्य प्रारंभ किए गए हैं। इस अवसर पर उत्तर पश्चिमी दिल्ली के सांसद योगेंद्र चंदोलिया, दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा, मुंडका के विधायक गजेंद्र सिंह दराल, दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड के अध्यक्ष राजकुमार चौहान सहित अनेक जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि ये सभी परियोजनाएं दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड (डीवीडीबी), मुख्यमंत्री विकास कोष (सीएमडीएफ), विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (एमएलएएडी) और अन्य मदों के अंतर्गत स्वीकृत की गई हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि मात्र 365 दिनों में ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 1600 करोड़ रुपए के विकास कार्य प्रारंभ किए जा चुके हैं। पूर्ववर्ती सरकारों ने गांव-देहात की उपेक्षा की, जिसके कारण राजधानी के ग्रामीण क्षेत्रों में टूटी सडकों, जर्जर नालों, स्कूलों, अस्पतालों और कॉलेजों की कमी जैसी बुनियादी समस्याएं वर्षों तक बनी रहीं, लेकिन अब ग्रामीण दिल्ली भी विकास की मुख्यधारा में आगे बढ़ रही है।

उन्होंने कहा कि बीते एक वर्ष में सरकार ने अंत्योदय के संकल्प को आत्मसात करते हुए ग्रामीण दिल्ली में सडक, पेयजल, सीवरेज, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत सुविधाओं का व्यापक विस्तार किया है। सरकार ने गांवों के विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाबद्ध और तेज विकास सुनिश्चित किया जा सके।

900 बीघा भूमि पर प्रस्तावित ग्रोथ सेंटर को विकसित किया जाएगा: रेखा गुप्ता

रेखा गुप्ता ने कहा कि गांवों में सडकों का निर्माण, बड़े नालों का निर्माण, बॉर्डर क्षेत्रों का विकास, नए स्कूल, अस्पताल और डिस्पेंसरी स्थापित करने पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। लगभग 500-600 करोड़ रुपए की लागत से पेरिफेरल सडकों और नालों के निर्माण के कार्य भी पूरे ग्रामीण क्षेत्र में कराए जा रहे हैं। इसके अलावा, नए मास्टर प्लान के माध्यम से किसानों को भी सीधा लाभ मिलेगा, चकबंदी से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाएगा और 900 बीघा भूमि पर प्रस्तावित ग्रोथ सेंटर को विकसित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से मुंडका विधानसभा क्षेत्र में आवागमन सुगम होगा, स्वच्छ पेयजल और बेहतर सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध होगी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत होंगी और स्थानीय नागरिकों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार आएगा। ये सभी कार्य ग्रामीण दिल्ली को शहरी सुविधाओं के समकक्ष लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

हनंदीपुरम आवासीय योजना का काउंटडाउन शुरू: 76 हेक्टेयर जमीन पर जीडीए का कब्जा, 128 हेक्टेयर की खरीद प्रक्रिया तेज

आरव शर्मा

गाजियाबाद (शिखर समाचार) गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) की सबसे महत्वाकांक्षी हनंदीपुरम आवासीय योजना अब धरातल पर उतरने के बेहद करीब है। किसानों के साथ आपसी सहमति के आधार पर जमीन खरीदने के मॉडल ने इस प्रोजेक्ट को बड़ी कामयाबी दिलाई है। प्राधिकरण अब तक 76 हेक्टेयर जमीन का बैनामा कराकर अपने नाम दर्ज करा चुका है, जबकि 128 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि के लिए किसानों की लिखित सहमति प्राप्त हो चुकी है, जिसकी रजिस्ट्री प्रक्रिया युद्धस्तर पर जारी है।

वीसी नंदकिशोर कलाल का विजन : पारदर्शिता और रफ्तार ही मूलमंत्र

योजना की प्रगति पर पैनी नजर रखते हुए जीडीए उपाध्यक्ष (वीसी) और आईएएस अधिकारी नंदकिशोर कलाल ने स्पष्ट किया है कि यह प्रोजेक्ट गाजियाबाद के भविष्य की तस्वीर बदलेगा। उन्होंने अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि हनंदीपुरम योजना प्राधिकरण का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। किसानों का भरोसा और पारदर्शिता हमारी प्राथमिकता है। जिन 128 हेक्टेयर भूखंडों पर सहमति मिल चुकी है, उनकी रजिस्ट्री प्रक्रिया में एक दिन की भी देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारा लक्ष्य किसानों को समय पर भुगतान कर प्रथम फेज को रिकॉर्ड समय में लॉन्च करना है।

सचिव की समीक्षा: ग्राउंड जीरो पर तैनात रहेंगे अधिकारी

भूमि क्रय की जटिलताओं को दूर करने के लिए जीडीए सचिव ने आज संयुक्त सचिव, तहसीलदार, लेखपाल और अमीनों के साथ गहन समीक्षा बैठक की। सचिव ने जमीनी स्तर पर काम कर रही टीम को सीधे आदेश दिए है कि सहमति प्राप्त प्रकरणों को तत्काल निस्तारित करें।

फील्ड ऑफिसर किसानों से सीधा संवाद रखें ताकि कागजी कार्रवाई में कोई अड़चन न आए। प्रथम चरण के लिए आवश्यक भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

क्यों खास है हनंदीपुरम योजना?

यह योजना गाजियाबाद के नियोजित और संतुलित शहरी विस्तार की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। इसके मास्टर प्लान में निम्नलिखित विशेषताएं शामिल हैं। स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर: अत्याधुनिक चौड़ी सड़कें और उन्नत ड्रेनेज सिस्टम। ग्रीन सिटी कॉन्सेप्ट: विशाल हरित पट्टियां (ग्रीन बेल्ट) और पार्कों का जाल। पब्लिक एमेनिटीज: स्कूल, अस्पताल, सामुदायिक केंद्र और सुव्यवस्थित आवासीय ब्लॉक।

सहमति मॉडल: विवाद खत्म, विकास शुरू

हनंदीपुरम में अपनाया गया म्युचुअल एग्रीमेंट मॉडल किसानों और प्राधिकरण के बीच विश्वास की नई मिसाल बन रहा है। इससे न केवल कानूनी अड़चनें खत्म हुई हैं, बल्कि किसानों को भी उनकी जमीन का उचित और सम्मानजनक प्रतिफल मिल रहा है। प्रशासन का पूरा जोर अब उन फाइलों को क्लीयर करने पर है जो 128 हेक्टेयर भूमि की रजिस्ट्री से जुड़ी हैं।

जाम स्थल पर मारपीट मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर भाकियू टिकैत का थाना परिसर में धरना

बिजनौर (शिखर समाचार)। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ता के साथ जाम स्थल पर हुई मारपीट के मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने से नाराज किसानों ने बढ़ापुर थाना परिसर में धरना दिया। किसानों ने आरोपियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। जानकारी के अनुसार रविवार को ग्राम टांडा साहूवाला निवासी पुष्पेंद्र की ट्रक से कुचलकर मौत हो गई थी। हादसे से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने सोमवार को थाने के सामने जाम लगा दिया था। जाम की सूचना मिलने पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ता योगेंद्र सिंह लोगों को समझाने और स्थिति शांत कराने के लिए मौके पर पहुंचे थे। आरोप है कि मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया तथा मारपीट करते हुए उन्हें जाम स्थल से बाहर निकाल दिया। इसके बाद उन्होंने अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस को तहरीर दी थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से कार्यकताओं में नाराजगी है। पुलिस कार्रवाई न होने से आक्रोशित किसान मंगलवार को बढ़ापुर थाना परिसर में धरने पर बैठ गए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। समाचार लिखे जाने तक किसान थाना परिसर में धरने पर डटे रहे।

एमएलसी डॉ. सुरेन्द्र चौधरी के नेतृत्व में लखनऊ में धूमधाम से मनी संत गाडगे महाराज की 150वीं जयंती

आरव शर्मा

लखनऊ/गाजियाबाद (शिखर समाचार)। स्वच्छता के जनक और समाज सुधार के प्रतीक संत गाडगे महाराज की 150वीं जयंती राजधानी लखनऊ स्थित विश्वेश्वरैया सभागार में अत्यंत भव्य और गरिमामय वातावरण में मनाई गई। राजभवन के सामने पीडब्ल्यूडी मुख्यालय, हजरतगंज में आयोजित इस समारोह में प्रदेश सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री एवं जनप्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम का नेतृत्व एमएलसी डॉ. सुरेन्द्र चौधरी ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि संत गाडगे महाराज का संपूर्ण जीवन समाज सुधार और स्वच्छता के लिए समर्पित रहा। उन्होंने कहा कि ऐसे महान संतों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज जरूरत है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति उनके बताए मार्ग पर चलते हुए सामाजिक कुरीतियों से दूर रहे और अपने राज्य व देश को स्वच्छ एवं सुसंस्कृत बनाने का संकल्प ले। समारोह में ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक की धर्मपत्नी नम्रता पाठक, विधायक उमेश द्विवेदी व अंगद सिंह, पूर्व मंत्री सुनील भराला सहित अनेक गणमान्य अतिथियों ने संत गाडगे महाराज को नमन किया। कार्यक्रम के संयोजक एमएलसी डॉ. सुरेन्द्र चौधरी ने मंचासीन सभी अतिथियों को संत गाडगे महाराज की प्रतिमा भेंट कर सम्मानित किया। वक्ताओं ने संत गाडगे महाराज के समाज सुधार, स्वच्छता अभियान और जनजागरण से जुड़े कार्यों को स्मरण करते हुए आमजन से उनके आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया। समारोह में प्रदेश के सभी 75 जनपदों से बड़ी संख्या में संत गाडगे महाराज के अनुयायी उपस्थित रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी अनेक प्रतिनिधियों और कार्यकताओं ने भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया। आयोजन के दौरान पूरे सभागार में संत गाडगे महाराज के विचारों और स्वच्छता संदेश की गूंज सुनाई दी, जिससे वातावरण पूर्णतः श्रद्धा और प्रेरणा से ओत प्रोत रहा।

20 बीघा में बस रही अवैध कॉलोनी पर जीडीए का बुलडोजर, दुहाई सैतली में बड़ी कार्रवाई

आरव शर्मा

गाजियाबाद (शिखर समाचार)। अवैध निर्माण और बिना स्वीकृत मानचित्र के विकसित की जा रही कॉलोनियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की। मुरादनगर क्षेत्र के ग्राम दुहाई और सैतली में लगभग 20 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी को प्रवर्तन जोन 02 की टीम ने ध्वस्त कर दिया।

जीडीए की टीम जब मौके पर पहुंची तो पाया गया कि संबंधित कॉलोनी का विकास बिना वैध अनुमति और स्वीकृत मानचित्र के किया जा रहा था। पूर्व में नोटिस और चेतावनी दिए जाने के बावजूद निर्माण कार्य जारी रखा गया। इसके बाद प्राधिकरण ने कठोर रुख अपनाते हुए बुलडोजर कार्रवाई अमल में लाई।

कार्रवाई के दौरान साइट कार्यालय, अस्थायी निर्माण, प्लॉटिंग से संबंधित ढांचे और अन्य अवैध संरचनाओं को जेसीबी मशीनों की मदद से गिरा दिया गया। पूरी कार्रवाई सहायक अभियंता, अवर अभियंता, प्रवर्तन जोन 02 के स्टाफ और पर्याप्त पुलिस बल की मौजूदगी में शांतिपूर्वक संपन्न कराई गई। जीडीए अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि प्राधिकरण क्षेत्र में किसी भी सूरत में अवैध कॉलोनियों को विकसित नहीं होने दिया जाएगा। आमजन से अपील की गई है कि किसी भी भूखंड या संपत्ति की खरीद से पहले उसकी वैधता की जांच अवश्य करें, अन्यथा भविष्य में आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। प्रवर्तन जोन 02 की यह कार्रवाई साफ संदेश देती है कि अवैध निर्माण करने वालों पर आगे भी इसी तरह सख्त अभियान जारी

हरिपुर आवासीय योजना को लेकर एचपीडीए में तकनीकी प्रस्तुतियाँ आयोजित

हापुड़ (शिखर समाचार)। हापुड पिलखुवा विकास प्राधिकरण (एचपीडीए) द्वारा निविदा प्रक्रिया के अंतर्गत हरिपुर आवासीय योजना (चक्रसेनपुर, बाबूगढ़) के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) एवं अवसंरचना सेवाओं के विस्तृत लेआउट, डिजाइन और ड्रॉइंग तैयार करने हेतु परामर्शदाता फर्मों की तकनीकी प्रस्तुतियाँ आयोजित की गईं। प्रस्तुति चरण में तीन प्रतिष्ठित परामर्शदाता फर्मों ने भाग लेते हुए मूल्यांकन समिति के समक्ष अपनी तकनीकी प्रस्तुतियाँ दीं। कार्यक्रम में एचपीडीए के उपाध्यक्ष नितिन गौड़, सचिव, कार्यकारी अभियंता, सहायक अभियंता तथा परियोजना के मॉनिटरिंग एवं परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट सपोर्ट यूनिट से जुड़े परामर्शदाता उपस्थित रहे। फर्मों ने अपनी प्रस्तुतियों में प्रस्तावित कार्य पद्धति, योजना दृष्टिकोण, डिजाइन क्षमता तथा हरिपुर आवासीय योजना के लिए डीपीआर तैयार करने की समय सीमा पर विस्तार से प्रकाश डाला। यह परियोजना क्षेत्र में सुनियोजित शहरी विकास को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। तकनीकी प्रस्तावों का मूल्यांकन निर्धारित निविदा प्रक्रिया के अनुरूप किया जाएगा। एचपीडीए द्वारा चयन प्रक्रिया के आगामी चरणों को तय दिशा निर्देशों के अनुसार आगे बढ़ाया जाएगा।

डंपर और पिकअप की भिड़ंत में दो मजदूरों की मौत, 21 घायल, कई की हालत गंभीर

खतौली/मुजफ्फरनगर (शिखर समाचार)। मंगलवार सुबह गंग नहर पटरी मार्ग पर हुए भीषण सड़क हादसे में डंपर और पिकअप वाहन की आमने सामने की टक्कर में दो मजदूरों की मौत हो गई, जबकि पिकअप चालक सहित 21 लोग घायल हो गए। घायलों में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल हैं, जिनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा खतौली थाना क्षेत्र की सीमा के पास बुढ़ाना सर्किल के रतनपुरी थाना क्षेत्र में हुआ। क्षेत्राधिकारी बुढ़ाना गजेंद्रपाल सिंह ने बताया कि पिकअप वाहन संख्या UP 12 ST 2545 जनपद के जानसठ थाना क्षेत्र के गांव गुजरेहड़ी से मजदूरों को लेकर मेरठ जनपद के सरधना थाना क्षेत्र के गांव पावली जा रहा था। रास्ते में रतनपुरी थाना क्षेत्र के गांव सठेड़ी से भी मजदूरों को बैठाया गया। सभी मजदूर खेतों में मटर की फली तोड़ने के काम के लिए जा रहे थे। गंग नहर पटरी मार्ग पर पुल से आगे कुछ दूरी पर पहुंचते ही डंपर वाहन संख्या HR 58 F 8589 ने पिकअप में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे की सूचना मिलते ही थाना रतनपुरी पुलिस मौके पर पहुंची और एंबुलेंस की सहायता से घायलों को खतौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों को जिला अस्पताल सहित अन्य उच्च चिकित्सा केंद्रों के लिए रेफर किया गया।

चिकित्सकों ने गुजरेहड़ी निवासी ताराचंद (60) और रामचन्द्र (70) को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना की सूचना मिलते ही मृतकों और घायलों के परिजनों में कोहराम मच गया और बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंच गए। आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष दिनेश बावरा भी अस्पताल पहुंचे और अधिकारियों से वार्ता करते हुए फरार डंपर चालक की गिरफ्तारी तथा मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की मांग की। हादसे के बाद घटनास्थल पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। मौके पर उपजिलाधिकारी बुढ़ाना, क्षेत्राधिकारी बुढ़ाना, थाना रतनपुरी पुलिस, थाना खतौली पुलिस और डायल 112 की टीमें मौजूद रहीं। उपजिलाधिकारी निकिता शर्मा ने दो लोगों की मौत और लगभग 21 लोगों के घायल होने की पुष्टि करते हुए कहा कि प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता दिलाई जाएगी।

जिलाधिकारी ने घायलों का जाना हाल

जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने जिला अस्पताल पहुंचकर हादसे में घायल लोगों का हालचाल जाना। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक और चिकित्सकों को निर्देश दिए कि घायलों का उपचार बेहतर ढंग से किया जाए और किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। जिलाधिकारी ने परिजनों से बातचीत कर घटना की जानकारी भी ली।

घायलों के नाम

घायलों में मौसम पत्नी मनोज (45), खुशी पुत्री गोपी, संगीता पत्नी गोपी, बाला पत्नी किरणपाल, अन्नू पुत्री किरणपाल, शालू पुत्री लोकेंद्र, अर्पित पुत्र लोकेंद्र, कुमकुम पुत्री लोकेंद्र, मंगेश पुत्री टिल्लू, रिया पुत्री टिल्लू, सोनिया पत्नी भोरन सिंह, ओमवती पत्नी ताराचंद, नेहा पुत्री बाबूराम, अवनी पुत्री सुंदर, सपना पुत्री चोखेसिंह, पिंकी पुत्री धर्मेंद्र, कोमल पत्नी ललित, कुमकुम पुत्री भोरन सिंह, सोनम पुत्री सुभाष, राकेश पत्नी तेजपाल तथा पिकअप चालक राहुल शामिल हैं।

गढ़मुक्तेश्वर में अवैध प्लॉटिंग पर एचपीडीए की बड़ी कार्रवाई, 4 स्थानों पर चला ध्वस्तीकरण अभियान

हापुड़ (शिखर समाचार)। हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण (एचपीडीए) ने अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए गढ़मुक्तेश्वर विकास क्षेत्र में व्यापक अभियान चलाया। पुलिस बल की मौजूदगी में प्रवर्तन दल ने चार अलग अलग स्थानों पर अवैध रूप से की जा रही प्लॉटिंग को ध्वस्त किया। प्राधिकरण की इस कार्रवाई से अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मच गया। जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार स्याना रोड स्थित भूपेंद्र नर्सिंग होम के पीछे दो अलग अलग प्रकरणों में लगभग 16,16 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र में बिना मानचित्र स्वीकृति के अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी, जिस पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण किया गया। इसी क्रम में मोहल्ला इंद्रानगर, वार्ड संख्या 13, घोड़ा फार्म, पुरानी दिल्ली रोड, गढ़मुक्तेश्वर में लगभग 20 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र में विकसित की जा रही अवैध प्लॉटिंग को भी ध्वस्त किया गया। इसके अलावा बदरखा ओवरब्रिज के निकट करीब 2500 वर्ग मीटर क्षेत्र में की जा रही अवैध प्लॉटिंग पर भी कार्रवाई की गई। प्राधिकरण अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि बिना मानचित्र स्वीकृति के किसी भी प्रकार का निर्माण या प्लॉटिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आगे भी इसी तरह सख्त अभियान जारी रहेगा। आम नागरिकों से अपील की गई है कि नियमों के तहत मानचित्र स्वीकृत कराकर ही निर्माण कार्य करें, अन्यथा होने वाली किसी भी क्षति के लिए संबंधित व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होगा।

सड़क चौड़ीकरण शुरू, दुर्घटनाओं पर लगेगी रोक, लोगों में जगी सुविधा की उम्मीद

नगीना/बिजनौर (शिखर समाचार)। सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती घटनाओं पर नियंत्रण और यातायात व्यवस्था को सुरक्षित व सुगम बनाने के उद्देश्य से लोक निर्माण विभाग द्वारा नगीना बूंदकी मार्ग के तिराहे पर सड़क चौड़ीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। सड़क चौड़ीकरण कार्य शुरू होने से क्षेत्र के लोगों में आवागमन की बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद जगी है और स्थानीय नागरिकों ने इस पहल का स्वागत किया है। नगीना बूंदकी मार्ग पर सिद्धार्थ पेट्रोल पंप के पास सड़क के दोनों ओर मशीनों और मजदूरों की सहायता से चौड़ीकरण का कार्य युद्ध स्तर पर कराया जा रहा है। यह मार्ग क्षेत्र का प्रमुख संपर्क मार्ग होने के कारण यहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में छोटे-बड़े वाहन गुजरते हैं, जिससे अक्सर जाम और दुर्घटना की स्थिति बनी रहती थी। सड़क के संकरे होने के कारण इस स्थान पर लंबे समय से सड़क दुर्घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। कई बार वाहन चालकों और राहगीरों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। स्थानीय लोगों द्वारा लंबे समय से सड़क चौड़ीकरण की मांग की जा रही थी, जिसके बाद अब लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य शुरू कराया गया है। सड़क चौड़ीकरण पूरा होने के बाद इस मार्ग से गुजरने वाले वाहनों और राहगीरों को काफी सुविधा मिलेगी। साथ ही यातायात व्यवस्था सुचारु होने से दुर्घटनाओं में कमी आने की संभावना है। क्षेत्र के लोगों का मानना है कि सड़क चौड़ीकरण होने से आवागमन सुरक्षित होगा और समय की भी बचत होगी।

हापुड़ में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम रद्द, फर्म ब्लैकलिस्ट, डीएम अभिषेक पांडेय की बड़ी कार्रवाई

हापुड़ (शिखर समाचार) मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 26 फरवरी को प्रस्तावित 517 जोड़ों के सामूहिक विवाह कार्यक्रम को प्रशासन ने अनियमितताओं के चलते निरस्त कर दिया। पंडाल में फटे और गंदे कपड़ों के उपयोग, घटिया सजावट सामग्री तथा निम्न स्तर के भोजन की शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी अभिषेक पांडेय ने सख्त कार्रवाई करते हुए संबंधित फर्म को ब्लैकलिस्ट कर दिया। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के जोड़ों का विवाह कराया जाता है। प्रत्येक जोड़े पर लगभग एक लाख रुपये खर्च किए जाते हैं। 26 फरवरी को प्रस्तावित सामूहिक विवाह समारोह में 517 जोड़ों के विवाह की तैयारी की जा रही थी। समाज कल्याण विभाग की ओर से लगभग 75 लाख रुपये की लागत से आयोजन प्रस्तावित था। कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण करने पहुंचे मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु गौतम को मौके पर गंभीर अनियमितताएं मिलीं। निरीक्षण में पंडाल में फटे और गंदे कपड़ों का उपयोग, निम्न स्तर की सजावट सामग्री, भोजन की खराब गुणवत्ता, साफ सफाई की कमी तथा बैठने की अव्यवस्थित व्यवस्था सामने आई। मुख्य विकास अधिकारी ने मौके पर नाराजगी जताते हुए अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेज दी। इसके बाद जिलाधिकारी अभिषेक पांडेय ने स्वयं कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण में खामियां सही पाए जाने पर सरकारी धन की बबार्दी रोकने के उद्देश्य से कार्यक्रम निरस्त करने के आदेश दिए गए। साथ ही संबंधित फर्म मुकुल वेडिंग्स को तत्काल प्रभाव से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि उक्त फर्म को 75 लाख रुपये का ठेका दिया गया था और उसने प्रदेश के अन्य जिलों में भी इसी योजना के कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इस संबंध में निदेशालय को पत्र भेजकर निर्देश दिया गया है कि इस फर्म को अन्य जिलों में भी कार्य न दिया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन जोड़ों के विवाह प्रस्तावित थे, उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आगामी लगभग दस दिनों के भीतर योजना के अंतर्गत पुनः कार्यक्रम आयोजित कर विवाह संपन्न कराए जाएंगे। गौरतलब है कि कार्यक्रम की तैयारियों में समाज कल्याण विभाग की निगरानी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। समय रहते निरीक्षण होने से बड़े आयोजन में संभावित अव्यवस्था और सरकारी धन की बबार्दी को रोका जा सका।

अंबेडकर आवास योजना खंडहर में तब्दील, कई पर नियम विरुद्ध रह रहे किरायेदार

नगीना/बिजनौर (शिखर समाचार)। नगर पालिका परिषद की भूमि पर डूडा विभाग द्वारा निर्मित बाल्मीकि मलिन बस्ती स्थित अंबेडकर आवास योजना के अंतर्गत गरीब और बेसहारा परिवारों के लिए बनाए गए 52 आवासों की स्थिति बदहाल हो गई है। कई आवास अपात्र लोगों को आवंटित कर दिए जाने के आरोप हैं, जबकि कुछ आवास दुकानों में तब्दील हो चुके हैं। अनेक मकानों में नियमों के विरुद्ध किरायेदार रह रहे हैं और दो आवास लंबे समय से खाली पड़े खंडहर में बदल गए हैं, जिन पर भूमाफियाओं की नजर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार नगर के मोहल्ला कायस्थ सराय हरेवली बूढ़ावाला रोड चुंगी के पास नगर पालिका की खाली पड़ी भूमि पर वर्ष 2005 में डूडा विभाग द्वारा अंबेडकर आवास योजना के अंतर्गत 52 आवासों की कालोनी का निर्माण कराया गया था। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों को आवास उपलब्ध कराना था।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि आवासों का आवंटन करते समय अधिकारियों और दलालों की मिलीभगत से अपात्र लोगों को लाभ दे दिया गया। ऐसे कई लाभार्थियों के पास पहले से मकान, कृषि भूमि या अन्य संपत्ति मौजूद थी। आरोप है कि कुछ लोगों ने आवंटित आवासों को बेच दिया, जबकि कई ने किराये पर उठा दिए हैं।

सूत्रों के अनुसार आवास आवंटन के समय आवेदन पत्रों में स्पष्ट उल्लेख था कि लाभार्थी स्वयं ही आवास में निवास करेगा तथा उसे न तो किराये पर देगा और न ही किसी अन्य व्यक्ति को बेचेगा। इसके बावजूद नियमों की अनदेखी कर आवासों का हस्तांतरण और किराये पर देना जारी है।

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि संबंधित विभागों की लापरवाही के कारण स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। कुछ आवासों को तोड़कर दुकानों का रूप दे दिया गया है, जबकि दो आवास लंबे समय से खाली पड़े पड़े खंडहर बन गए हैं। बताया जाता है कि आसपास की जमीन रखने वाले दबंग कॉलोनाइजर इन खंडहर आवासों को तोड़कर रास्ता चौड़ा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आरोप है कि कालोनी के पास बनी सड़क के किनारे स्थित कुछ आवासों की दीवारें तक तोड़ दी गई हैं, लेकिन नगर पालिका, डूडा विभाग या जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। स्थानीय लोगों ने आवासों के वास्तविक लाभार्थियों की सूची की जांच कर अवैध कब्जों और बिक्री की जांच कराने की मांग की है।

संक्षिप्त समाचार

बच्चों को बोर्ड के बाद फिर मिलेगा प्रायोगिक परीक्षा देने का मौका

वाराणसी, एजेंसी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं कराई जा रही हैं। इसके पूर्व 2 से 9 फरवरी तक दोनों ही कक्षाओं की प्रायोगिक परीक्षाएं कराई जा चुकी हैं। 671 छात्रों ने प्रायोगिक परीक्षा छोड़ दी थी। अब इन विद्यार्थियों को प्रायोगिक परीक्षा देने का एक और मौका बोर्ड परीक्षा के बाद दिया जाएगा। यूपी बोर्ड के सहायक सचिव मनोज कुमार ने बताया कि इस बार प्रदेशभर में दो चरणों में हुए प्रायोगिक परीक्षाएं हुईं। वाराणसी में दूसरे चरण में परीक्षा हुई। इन सभी छात्रों के लिए बोर्ड ने 13 फरवरी तक एक मौका दिया था लेकिन इन छात्रों की उपस्थिति नहीं हो सकी। अब बोर्ड के बाद एक और मौका मिलेगा।

पीएम ने एआई को भारत को नई ऊंचाई तक ले जाने वाला विजन बताया

वाराणसी, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 131वें संस्करण को भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुना और इसे आत्मसात करने का संकल्प लिया। पीएम ने रमजान के पवित्र महीने और होली के पर्व के लिए देशवासियों को शुभकामनाएं दीं। परीक्षा दे रहे छात्रों को सफलता के लिए प्रोत्साहित किया। पीएम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डिजिटल तकनीक के माध्यम से भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का विजन प्रस्तुत किया। भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल ने कैंट विधानसभा के रामनगर मंडल के बूथ नंबर-262 पर मन की बात सुनी। भाजपा जिलाध्यक्ष और एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा ने रोहनिया विधानसभा के कंचनपुर बूथ संख्या 185 पर कार्यक्रम देखा। गुलाब बाग कार्यालय में महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी ने भी मन की बात सुनी। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र के उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में मौनी बाबा आश्रम, लक्सा में मन की बात सुनी गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा क्षेत्रीय महामंत्री अशोक चौरसिया और विशिष्ट अतिथि क्षेत्रीय कार्यालय प्रभारी श्रीप्रकाश शुक्ला रहे। इस अवसर पर नवरतन राठी, संतोष सोलापुरकर, नवीन कपूर, आलोक श्रीवास्तव मौजूद रहे।

फिटनेस का डोज, आधा घंटा रोज... साइकिल चलाकर दिया स्वस्थ रहने का मंत्र

वाराणसी, एजेंसी। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के स्थापना के 75वें वर्ष में प्रवेश के उपलक्ष्य में रविवार को पांडेयपुर स्थित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल परिसर में सन्डेज ऑन साइकल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (साई) के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ उप क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी प्रवीण कुमार सिंह और सीएमओ डॉ. राजेश प्रसाद ने साइकिल रैली को फ्लैग ऑफ करके किया। सीएमओ ने प्रधानमंत्री के फिट इंडिया अभियान को आगे बढ़ाते हुए फिटनेस का डोज, आधा घंटा रोज का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए हर व्यक्ति को प्रतिदिन व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। विशिष्ट अतिथि ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. सेल्वा कुमार चिल्लैया रहे। कार्यक्रम के दौरान केवल साइकिलिंग ही नहीं, बल्कि फिटनेस के अन्य पहलुओं पर भी जोर दिया गया। परिसर में आयोजित जुंबा डांस सत्र में ईएसआईसी के कर्मचारियों, साई के खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। इसके साथ ही योग प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में सामूहिक योगाभ्यास कराया गया। समारोह के समापन पर पूर्व साई वरिष्ठ कोच नन्हे सिंह, अशोक कुमार पांडेय, जगदीश द्विवेदी, साई वाराणसी सेंटर के प्रभारी जीतेंद्र कुमार और फिट इंडिया ब्रांड एंबेसडर अंकित कुमार पांडेय शामिल रहे।

वाराणसी में 42.33 फीसदी छात्रों की नहीं बनी अपार आईडी, प्रवेश में होगी दिक्कत

वाराणसी, एजेंसी। जिले के बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ रहे 42.33 फीसदी यानी 2.87 लाख बच्चों की ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री (अपार) आईडी अभी तक नहीं बन पाई है। इसे लेकर शासन ने नाराजगी व्यक्त की। बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने सभी बीएसए और डीआईओएस को पत्र भेजकर जल्द इसे 100 फीसदी करने को कहा है। बेसिक व माध्यमिक विद्यालयों में करीब 6.78 लाख बच्चे हैं। इनमें बेसिक के 1.78 लाख और करीब 5 लाख बच्चे माध्यमिक शिक्षा के हैं। इनमें से 2.87 लाख बच्चे अभी भी अपार आईडी से वंचित हैं। शनिवार को शासन स्तर पर इसकी बैठक हुई जिसमें 42.33 फीसदी बच्चों की अपार आईडी अब तक नहीं बन पाई है। इससे बच्चों का डेटा जुटाना मुश्किल होगा। नई शिक्षा नीति के तहत हर बच्चे की जानकारी अब यू डाइस में पूरी तरह से डिजिटल होगी। छात्र की एक ही आईडी रहेगी। जिसे लेकर छात्र-छात्रों की अपार आईडी (ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक एकाउंट) बनाई जा रही है।

निजी क्षेत्र को दी जाएंगी छह जल विद्युत परियोजनाएं

42 साल के लिए लीज पर देने का टेंडर हुआ जारी

लखनऊ, एजेंसी। यूपी में छह जल विद्युत परियोजनाएं निजी क्षेत्र को दी जाएंगी। 42 साल के लिए लीज पर देने का टेंडर जारी किया गया है। ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े संगठनों ने इसका विरोध शुरू किया है। मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है।

उत्तर प्रदेश सरकार छह लघु जल विद्युत परियोजनाओं को 42 वर्ष के लिए निजी क्षेत्र को लीज पर देने की तैयारी में है। इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने टेंडर जारी कर दिया है। टेंडर के अनुसार 1.5 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट के अग्रिम प्रीमियम पर निजी कंपनियों को परियोजनाएं सौंपी जाएंगी और वे 42 वर्षों तक उनका संचालन करेंगी।

प्रदेश में 300 मेगावाट की रिहंद, 99 मेगावाट की ओबरा, 72 मेगावाट की माताटीला (ललितपुर) और 72 मेगावाट की खारा जल विद्युत परियोजनाएं पहले से संचालित हैं। इसके अतिरिक्त छह लघु जल विद्युत परियोजनाएं भी हैं, जिनके पास करोड़ों रुपये मूल्य की जमीन और अन्य संपत्तियां हैं। लीज पर प्रस्तावित परियोजनाओं में भोला (2.7 मेगावाट), सलावा (3 मेगावाट), निर्गजनी (5 मेगावाट), चित्तौरा (3 मेगावाट), पलरा (0.6 मेगावाट) और सुमेरा (1.5 मेगावाट) शामिल हैं। ये सभी अपर गंगा नहर पर स्थित लगभग 90 से 97 वर्ष पुरानी परियोजनाएं हैं।

वहीं, टेंडर जारी होते ही ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि परियोजनाएं राज्य सरकार के अधीन ही रहनी चाहिए, क्योंकि निजी कंपनियों की नजर इनके साथ जुड़ी बेशकीमती जमीन और संपत्तियों पर भी है। संगठनों ने मुख्यमंत्री से मामले में हस्तक्षेप की मांग की है।

टेंडर निरस्त होने तक आंदोलन जारी रहेगा- एआईपीईएफ

ऑल इंडिया पॉवर इंजीनियर्स फेडरेशन के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे ने छह लघु जल विद्युत परियोजनाओं को 42 वर्षों के लिए निजी कंपनियों को लीज पर देने के निर्णय का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि अपर गंगा नहर में वर्षभर पानी उपलब्ध रहता है, जिससे इन परियोजनाओं में लगातार बिजली उत्पादन संभव है।

सीमित निवेश से इनके पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण का खर्च एक वर्ष में निकाला जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि टेंडर में स्थापित क्षमता 15.5 मेगावाट के बजाय 6.3 मेगावाट दर्शाई गई और संपत्तियों का मूल्य कम आंका गया है। उन्होंने टेंडर निरस्त होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है।

आरक्षण खत्म करने की साजिश- पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन

पॉवर ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आरपी केन और कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने आरोप लगाया कि लघु जल विद्युत परियोजनाओं को लीज पर देना निजीकरण की नई रणनीति है। उनका कहना है कि इससे कर्मचारियों की छंटनी होगी और आरक्षण व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। निजी कंपनियां अपनी शर्तों पर नियुक्तियां करेंगी तथा सरकारी संपत्तियों के दुरुपयोग की आशंका है। उन्होंने मुख्यमंत्री से टेंडर निरस्त कर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

असलहों-गाड़ियों के काफिले के शौक और भौकाल के चक्कर में आर्थक बन गया मनबढ़

गोरखपुर, एजेंसी। छात्रनेता के घर पर फायरिंग के मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी आर्थक सिंह असलहों-गाड़ियों के काफिले के जरिये सोशल मीडिया पर भौकाल जमाने का शौकीन है। यही भौकाल उसे अपराध के दलदल में ले गया। उसका संबंध बरही के प्रभावशाली परिवार से बताया जा रहा है। उसके पिता क्षेत्रीय राजनीति में सक्रिय हैं।

पुलिस सूत्रों का कहना है कि किशोरावस्था से ही आर्थक जन्मदिन, शादी-विवाह और अन्य आयोजनों में हथियारों और लग्जरी गाड़ियों के काफिले के साथ नजर आता था। सोशल मीडिया प्रोफाइल पर भी हथियारों के साथ तस्वीरें और गाड़ियों के काफिले का प्रदर्शन देखा जा सकता है। सूत्रों का दावा है कि कुछ समय पहले गोरखपुर में भी आर्थक कानूनी पचड़ों में फंसते-फंसते बचा था, जहां कथित तौर पर पिता ने हस्तक्षेप कर मामला शांत कराया।

आर्थक सिंह और उसके पिता के फेसबुक वॉल पर बड़े काफिले, लग्जरी एसयूवी और असलहाधारियों के साथ तस्वीरें पोस्ट की जाती रही हैं। राजनीतिक पहचान बनाने की कोशिश में आर्थक के नाम से कई पोस्ट साझा किए गए, जिनमें खुद को भावी नेता के रूप में प्रस्तुत किया गया। तस्वीरों में भीड़, गाड़ियों की लंबी कतार और हथियारों का खुला प्रदर्शन साफ दिखाई देता है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस तरह का सार्वजनिक प्रदर्शन युवाओं में गलत संदेश देता है और कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकता है।

लखनऊ में फार्मासिस्ट हितों पर महत्वपूर्ण बैठक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की समस्याओं पर विस्तृत चर्चा

लखनऊ (शिखर समाचार)। इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन फार्मासिस्ट वॉइस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं उत्तराखंड प्रभारी शुभम आशियान ने फामेर्सी काउंसिल ऑफ इंडिया के लखनऊ स्थित अध्यक्ष संदीप बडोला से शिष्टाचार भेंट कर फार्मासिस्टों से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के फार्मासिस्टों की समस्याओं, उनके व्यावसायिक अधिकारों, पंजीकरण संबंधी मुद्दों तथा कार्यक्षेत्र में आ रही कठिनाइयों पर गंभीरतापूर्वक विचार विमर्श किया गया। साथ ही संगठन को और अधिक सशक्त बनाने तथा फार्मासिस्टों की एकता को मजबूत करने के उपायों पर भी चर्चा हुई।

बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों ने कहा कि इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन लगातार फार्मासिस्टों के हितों की रक्षा, उनके अधिकारों के संरक्षण तथा पेशे की गरिमा बनाए रखने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि फार्मासिस्ट स्वास्थ्य व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं और उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान आवश्यक है।

इस अवसर पर मंडल महासचिव राजकुमार वर्मा, जिला संयोजक विनीत कॉर्नवाल तथा जिला अध्यक्ष शामली रजत नामदेव ने संगठन की गतिविधियों और क्षेत्रीय समस्याओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पदाधिकारियों ने आशा व्यक्त की कि इस सकारात्मक संवाद के माध्यम से प्रदेश के फार्मासिस्टों की लंबित समस्याओं के समाधान की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाएंगे और भविष्य में फार्मासिस्टों के हितों को और अधिक मजबूती दी जा सकें।

रात के हादसों में हर दूसरा चालक पीकर था टुन्न, हेलमेट और सीट बेल्ट न लगाने से गई जान

लखनऊ, एजेंसी। लखनऊ स्थित पीजीआई के एपेक्स ट्रॉमा सेंटर में छह वर्ष के दौरान आए घायलों के आधार पर रिपोर्ट जारी हुई है। इसमें बताया गया कि सिर्फ एक तिहाई ने हेलमेट लगाया था। चार पहिया में सीट बेल्ट लगाने वाले भी सिर्फ 41 फीसदी मिले। हर दूसरा चालक पीकर था टुन्न था।

शराब पीकर गाड़ी चलाना और हेलमेट इस्तेमाल न करना रात में दुर्घटना की बड़ी वजह हैं। राजधानी लखनऊ स्थित पीजीआई के एपेक्स ट्रॉमा सेंटर ने वर्ष 2018 से 2024 के बीच रात में आए घायलों के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की है। इसमें देखा गया कि रात के समय लाए गए घायलों में से लगभग हर दूसरे ने शराब पी रखी थी और सिर्फ एक तिहाई ने ही हेलमेट पहना था। वहीं, चार पहिया में सीट बेल्ट लगाने वाले भी सिर्फ 41 फीसदी थे।

डॉ. एके सिंह और डॉ. पीके मिश्रा की यह रिपोर्ट क्यूरस मेडिसिन जर्नल में प्रकाशित हुई है। अध्ययन में कुल 3,705 घायलों को शामिल किया गया। रिपोर्ट के अनुसार घायलों

के कुल मामलों में से 67.3 फीसदी सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित थे, जिनमें 84.7 फीसदी दोपहिया वाहन दुर्घटनाएं थीं। 78.3 फीसदी मरीज पुरुष थे और उनकी औसत आयु 37.5 वर्ष थी। सबसे ज्यादा 44.5 फीसदी मामले सिर की चोट के थे।

अध्ययन में यह भी देखा गया कि काफी बुजुर्ग बाथरूम में गिरकर घायल हो रहे हैं। इसकी बड़ी वजह बाथरूम में लगे चिकने टाइल्स हैं जिनकी फिसलन के शिकार बुजुर्ग हो जाते हैं। अध्ययन में पाया गया कि 58.4 फीसदी मरीजों को आईसीयू में भर्ती करना पड़ा और 45.8 फीसदी को मैकेनिकल वेंटिलेशन की आवश्यकता हुई। कुल मृत्यु दर चार फीसदी रही, जिसमें 42.2 फीसदी मौतें भर्ती होने के 24 घंटे के भीतर हुईं।

केजीएमयू में ट्रॉमा सर्जरी विभाग के प्रोफेसर डॉ. वैभव जायसवाल के मुताबिक, दुर्घटनाओं के लिए रफ्तार एक बड़ी वजह है। नए बन रहे एक्सप्रेसवे और बेहतर होते रास्ते एक से दूसरे स्थान पर जाने में हमारा समय बचाते हैं, लेकिन दुर्घटना की वजह भी बन रहे हैं। इन दुर्घटनाओं में सबसे बड़ी वजह लापरवाही और जागरूकता की कमी है।

बच्चों का किराया उम्र से नहीं लंबाई से होगा तय, नमो भारत और मेट्रो ट्रेन में किराये को लेकर अनोखा नियम

मेरठ, एजेंसी। नमो भारत और मेट्रो ट्रेन में बच्चों के किराये को लेकर अनोखा नियम लागू है। सामान्य तौर पर परिवहन सेवाओं में उम्र के आधार पर छूट दी जाती है लेकिन यहां लंबाई का मानक तय किया गया है। स्टेशन परिसर और एएफसी गेट्स के पास लंबाई मापने के लिए निशान लगाए गए हैं। यदि बच्चे की लंबाई 90 सेमी (2.95 फीट) से नीचे है तो वह अपने अभिभावक के साथ मुफ्त सफर कर सकता है। यदि लंबाई 90 सेमी या उससे ऊपर है तो उसे पूरा टिकट लेना होगा।

दरअसल कम उम्र के कुछ बच्चे भी ज्यादा लंबे होते हैं। ऐसे में अगर कोई 3 साल का बच्चा 92 सेमी लंबा है तो उसे टिकट लेना होगा। इसके विपरीत कम लंबाई वाला 4-5 साल का बच्चा भी मुफ्त यात्रा का लाभ उठा सकता है।

इन 7 मुख्य बातों का खास ख्याल रखें

अक्सर लोग किसी को छोड़ने या स्टेशन देखने अंदर चले जाते हैं। नियम के अनुसार आप जिस स्टेशन से प्रवेश करेंगे, वहीं से 20 मिनट के भीतर बाहर निकल सकते हैं।

टिकट बुक करने के लिए नमो भारत ऐप तो है, लेकिन ध्यान रहे कि मोबाइल ऐप से खरीदे गए क्यूआर टिकट न तो रिफंड होंगे और न ही उन्हें कैंसिल किया जा सकेगा।

चाहे आपने पेपर टिकट खरीदा हो या मोबाइल ऐप से डिजिटल टिकट लिया हो, टिकट जेनरेट होने के 120 मिनट (2 घंटे) के भीतर आपको स्टेशन के एएफसी गेट पर उसे स्कैन करके प्रवेश करना अनिवार्य है। यात्रा के दौरान आपका टिकट या कार्ड खो जाता है तो गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने पर अधिकतम किराया और साथ में निर्धारित अतिरिक्त शुल्क वसूला जाएगा। यह भुगतान कस्टमर केयर सेंटर पर करना होगा।

आप अपने तय स्टेशन से आगे जाना चाहते हैं तो बाहर निकलने से पहले कस्टमर केयर सेंटर पर अतिरिक्त किराये का भुगतान करना होगा। यदि आप कार्ड धारक हैं तो गेट से बाहर निकलते समय बढ़ा हुआ किराया अपने आप कट जाएगा।

किसी भी बैंक का नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) यहां चलेगा। इसे स्टेशन काउंटर से खरीदा या रिचार्ज किया जा सकता है। वहीं स्टेशन पर लगी टिकट वेंडिंग मशीन या टिकट काउंटर से क्यूआर कोड वाला टिकट मिल जाएगा।

तीन बच्चे और पत्नी का कत्ल, फिर खुद भी दे दी जान; सत्यवीर ने क्यों खत्म किया पूरा परिवार

कासगंज, एजेंसी। यूपी के कासगंज स्थित अमांपुर में एक ही परिवार के पांच सदस्यों की मौत ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया। सत्यवीर ने अपना पूरा परिवार खत्म कर दिया। इसके बाद खुद की भी जान दे दी। आखिर उसने ये खौफनाक कदम क्यों उठाया, इसके पीछे के पांच कारण सामने आए हैं। कासगंज के अमांपुर के एटा रोड स्थित मकान से शनिवार शाम पुलिस ने सत्यवीर, उनकी पत्नी रामश्री, बेटियां प्राची और अमरवती और बेटा गिरीश के शव बरामद किए। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस ने सभी शव कब्जे में लेकर देर रात एंबुलेंस से पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए।

सत्यवीर के अवसाद में जाने के 5 प्रमुख कारण आए सामने

1- सत्यवीर का बेटा गिरीश न्यूरो समस्या से गंभीर बीमार था। 15 से 20 हजार रुपये महीने का खर्च इलाज में आ रहा था। बेटे का इलाज आगरा में चल रहा था।

2- सत्यवीर आर्थिक तंगी के कारण अमांपुर कस्बे के पिता के नाम के मकान में भी हिस्सेदारी की मांग कर रहा था। इस मकान में उसका भाई देशराज रहता है।

3- उधार रुपये चुकाने का भी दबाव बना हुआ था। सत्यवीर ने कुछ लोगों से अलग अलग उधार रुपये ले रखे थे। उधार देने वाले लोग लगातार रुपये मांग रहे थे।

4- सत्यवीर के नाम एक बोलेरो कार थी। किराए पर चलती थी। पिता इसका संचालन कराते थे। बोलेरो की दुर्घटना होने पर मुआवजे की राशि सत्यवीर को मिली जिसमें कुछ रुपये उसने अपने पास रख लिए। यह रुपये रखने के लिए परिवार के लोगों से कहासुनी भी होती थी।

5- सत्यवीर के हिस्से की जमीन पर परिवार के लोग कब्जा जमाए थे और उसके खेती करने में अड़चनें पैदा कर रहे थे। लोगों के बीच इस तरह की चर्चाएं काफी थीं।

एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत की गुत्थी और सही कारणों तक पहुंच पाना पुलिस के लिए चुनौती भरा है। अभी तक की जांच पड़ताल में यह साफ हो चुका है कि बच्चों की जहर देकर जान ली गई है जबकि पत्नी को भी जहर दिया गया और गले पर चाकू से प्रहार भी किया। पत्नी और बच्चों की जान लेने के बाद सत्यवीर ने खुद फंदे पर लटकर जीवन समाप्त कर लिया। फॉरेंसिक टीम को एक खरपतवारनाशक का खाली डिब्बा मौके से मिला वहीं एक चाकू भी। जिस पर रक्त के निशान लगे हैं।

कौन सा जहर दिया, किसी को नहीं पता : सत्यवीर ने जान लेने के लिए कौन सा जहर खिलाया यह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि जान लेने में जिस जहर का प्रयोग किया वह काफी तीव्र है और उसकी दुर्गंध काफी अधिक है। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम ने तीन घंटे तक काफी गहनता से एक एक चीज की जांच पड़ताल की जिससे कोई स्पष्ट साक्ष्य हाथ लग सके।

बच्चों के प्रति असामान्य यौन इच्छा गंभीर मानसिक विकार है

लखनऊ, एजेंसी। बच्चों के प्रति असामान्य यौन इच्छा गंभीर मानसिक विकार है। वयस्क का बच्चों के प्रति यौन आकर्षण होने को पीडोफीलिया कहा जाता है। मनोरोग विशेषज्ञों के अनुसार बच्चों पर नजर रखने के साथ ही बातचीत करना बेहद जरूरी होता है।

बच्चों के यौन शोषण के मामले में बांदा के दंपती को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद पीडोफीलिया शब्द चर्चा में आ गया है। मनोरोग विशेषज्ञों के अनुसार पीडोफीलिया का मतलब वयस्क का बच्चों के प्रति यौन आकर्षण होना है। यह गंभीर मानसिक विकार है। इससे ग्रसित व्यक्ति की पहचान करना आसान नहीं है। इसलिए बच्चों पर नजर रखना और उनसे बातचीत करना बेहद जरूरी है।

बच्चों से बातचीत बेहद जरूरी- केजीएमयू के मनोरोग विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. विवेक अग्रवाल के अनुसार पीडोफीलिया भी असामान्य यौन इच्छा रखने वालों का एक प्रकार है। इस मानसिक विकार से पीड़ित व्यक्ति चोरी-छिपे बच्चों का यौन शोषण करते रहते हैं। इसलिए जरूरी है कि बच्चों से बातचीत करते रहें। उन पर नजर रखें, उनकी गतिविधियों को ध्यान से देखें और किसी भी असामान्य स्थिति में उनको भरोसे में लें।

चिकित्सीय परामर्श से संभव है पीडोफीलिया का इलाज- केजीएमयू के पूर्व मनोरोग विशेषज्ञ प्रो. आदर्श त्रिपाठी ने बताया कि कई बार असामान्य या तीव्र यौन इच्छा वाले व्यक्ति चिकित्सीय सलाह लेने आते हैं। इनमें बच्चे भी होते हैं। कई बार पत्नियां अपने पति को लेकर भी आती हैं। कुछ दवाओं और काउंसलिंग से पीडोफीलिया का इलाज संभव है।

बड़ी चुनौती है यौन शोषण झेलने वाले बच्चों का पुनर्वास-केजीएमयू के बाल मनोरोग विशेषज्ञ डॉ. पवन कुमार गुप्ता के मुताबिक यौन शोषण झेलने वाले बच्चों का पुनर्वास बड़ी चुनौती है। बचपन में हुए बलात्कार या फिर यौन शोषण की चोट का असर बच्चे के मन पर जीवन भर बना रह सकता है। इसलिए इन बच्चों को विशेष काउंसलिंग और पुनर्वास की जरूरत होती है। डॉ. गुप्ता के अनुसार, केजीएमयू में भी यह सुविधा मौजूद है।

छह करोड़ की डकैती के मामले में एसओजी ने सराफ को हिरासत में लिया

बरेली, एजेंसी। पीलीभीत एसओजी ने बहेड़ी में दबिश देकर एक सराफ को हिरासत में लिया। डकैती के मामले में सराफ से पूछताछ की गई। इसके बाद उसे छोड़ दिया गया। पीलीभीत जिले में बीते दिनों हुई छह करोड़ रुपये की डकैती के मामले में एसओजी ने रविवार को बरेली के बहेड़ी से पूछताछ के लिए एक सराफ को हिरासत में लिया। दरअसल, डकैती के खुलासे के लिए एसएसपी ने पीलभीत एसओजी को जांच सौंपी। एसओजी की जांच के दौरान वारदात में शामिल एक बदमाश को पकड़ा गया। पुलिस ने उससे पूछताछ की, जिसमें लूटा गया सोना बहेड़ी में एक सराफ को बेचने की बात सामने आई। एसओजी बदमाश को साथ लेकर माथुर रोड स्थित एक ज्वैलर्स के यहां पहुंची। उसकी निशानदेही पर ज्वैलर्स के मालिक को उठा कर अपने साथ पीलीभीत ले गई।उधर, ज्वैलर्स को उठाने की खबर से सराफा बाजार में खलबली मच गई। कुछ सराफ दुकान बंद कर मौके से खिसक लिए। उठाये गए सराफ के परिजनों ने बदमाश की ओर से माल बेचने की बात को झूठा बताया। साजिशन फंसाने की बात कही। सराफ की पैरवी में कई अन्य सराफ भी पीलीभीत गए। घंटों की पूछताछ के बाद सराफ को दोबारा फिर बुलाने की बात कहकर परिजनों को सौंपा। बहेड़ी थाने के इंस्पेक्टर पवन कुमार ने बताया कि पीलीभीत एसओजी किसी मामले में आई है। वह अपना काम कर रही है।

तेलंगाना के फ्यूचर सिटी विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधिमंडल ने ग्रेटर नोएडा का किया दौरा, इंफ्रास्ट्रक्चर और नीतियों की ली जानकारी

ग्रेटर नोएडा (शिखर समाचार)। तेलंगाना सरकार के फ्यूचर सिटी विकास प्राधिकरण का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पहुंचा और यहां की औद्योगिक नगरी के विकास मॉडल का अध्ययन किया। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने बताया कि तेलंगाना सरकार द्वारा हैदराबाद के निकट एक नई औद्योगिक नगरी विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। इसी उद्देश्य से ग्रेटर नोएडा के विकास मॉडल, नीतियों और आधारभूत संरचना की जानकारी प्राप्त करने के लिए यह दौरा किया गया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एन. जी. रवि कुमार के निर्देश पर प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल

के साथ विस्तृत बैठक कर भूमि अधिग्रहण से लेकर भूखंड आवंटन तक की पूरी प्रक्रिया और नीतियों की जानकारी साझा की। बैठक में फ्यूचर सिटी विकास प्राधिकरण के उप जिलाधिकारी (विशेष श्रेणी) वेंकटेश्वर लू, नियोजन अधिकारी स्नेहमाला, उप कार्यपालक अभियंता वेंकट किरन तथा सहायक नगर नियोजक अक्षय कुमार शामिल रहे। बैठक में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुमित यादव, वित्त महाप्रबंधक स्वतंत्र गुप्ता, प्रधान महाप्रबंधक संदीप चंद्रा, विशेष कार्याधिकारी नवीन कुमार सिंह तथा प्रबंधक अरविंद मोहन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल को विभिन्न विषयों पर जानकारी दी। प्राधिकरण के नियोजन विभाग ने प्रतिनिधिमंडल को मास्टर प्लान, सेक्टर विन्यास, भवन उपविधियां, बसावट व्यवस्था, भूमि अधिग्रहण की धाराओं तथा किसानों को दिए जाने वाले लाभों की विस्तार से जानकारी दी। परियोजना विभाग द्वारा ग्रेटर नोएडा की आधारभूत संरचना के विकास कार्यों की जानकारी प्रस्तुत की गई। वित्त विभाग के महाप्रबंधक स्वतंत्र गुप्ता ने प्राधिकरण की वित्तीय व्यवस्था का प्रस्तुतीकरण करते हुए बताया कि किस प्रकार प्राधिकरण को स्ववित्त पोषित संस्था के रूप में विकसित किया गया है। उद्योग विभाग के प्रबंधक अरविंद मोहन ने ग्रेटर नोएडा में लागू औद्योगिक नीतियों, योजनाओं और भूखंड आवंटन की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्रतिनिधिमंडल ने एकीकृत औद्योगिक नगरी का भी भ्रमण किया, जहां प्लग एंड प्ले व्यवस्था, अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र तथा चौबीस घंटे बिजली और पानी की उपलब्धता की व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त की। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने ग्रेटर नोएडा की आधारभूत संरचना और नियोजन प्रणाली की सराहना करते हुए कहा कि यहां से प्राप्त अनुभव तेलंगाना में नई नगरी बसाने की योजना को सफल बनाने में सहायक सिद्ध होंगे।

ग्रेटर नोएडा में 20 वेंडरों को मिले प्लेटफॉर्म, विधायक ने सौंपे आवंटन पत्र

ग्रेटर नोएडा (शिखर समाचार)। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा निर्मित वेंडिंग जोन में 20 वेंडरों को प्लेटफॉर्म आवंटित कर दिए गए हैं। दादरी विधायक तेजपाल नागर ने प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्रीलक्ष्मी वीएस और प्रेरणा सिंह की मौजूदगी में पात्र वेंडरों को आवंटन पत्र सौंपे। विधायक ने कहा कि प्राधिकरण की इस पहल से जरूरतमंद लोगों को अपने परिवार के भरण पोषण का स्थायी साधन मिलेगा और सड़क किनारे रेहड़ी लगाने की जरूरत कम होगी, जिससे यातायात व्यवस्था भी बेहतर होगी। प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एन.जी. रवि कुमार के निर्देशन में रेहड़ी पटरी कारोबारियों को व्यवस्थित स्थान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शहर के विभिन्न सेक्टरों में वेंडिंग जोन विकसित किए गए हैं। सेक्टर अल्फा दो, बीटा एक व दो, सेक्टर 36, ओमीक्रॉन एक ए व तीन, ज्यू दो व तीन, गामा दो, डेल्टा एक व तीन तथा पाई एक व दो समेत 12 सेक्टरों में कुल 769 प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। अब इन प्लेटफॉर्मों का

चरणबद्ध तरीके से आवंटन किया जा रहा है। प्राधिकरण के नगरीय सेवा विभाग के विशेष कार्याधिकारी मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि पहले चयनित पात्र आवेदकों में से 109 को प्लेटफॉर्म देने का निर्णय लिया गया था, लेकिन कुछ नामों पर आपत्तियां प्राप्त हुईं। इसके बाद पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारियों की समिति द्वारा दोबारा सत्यापन कराया गया। सत्यापन के बाद प्रथम चरण में 20 पात्र आवंटियों को प्लेटफॉर्म देने का निर्णय लिया गया। ये प्लेटफॉर्म सेक्टर अल्फा दो, बीटा दो और सेक्टर 36 में आवंटित किए गए हैं। वेंडिंग जोन में वेंडरों की सुविधा के लिए प्लेटफॉर्म के साथ शेड भी बनाए गए हैं। इसके अलावा बिजली, पानी और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था भी की गई है। प्राधिकरण द्वारा आगे भी नए वेंडिंग जोन विकसित कर पात्र वेंडरों को चरणबद्ध तरीके से प्लेटफॉर्म आवंटित किए जाएंगे। अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रेरणा सिंह ने बताया कि जिन सेक्टरों में सभी वेंडिंग प्लेटफॉर्म आवंटित हो जाएंगे, वहां यातायात व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए संबंधित क्षेत्र को नो वेंडिंग जोन घोषित किया जाएगा। इस अवसर पर वरिष्ठ प्रबंधक राजेश गौतम सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

फैक्ट्री में लगी आग, दमकल विभाग ने पाया पर आग पर काबू

गाजियाबाद (शिखर समाचार)। दिल्ली से सटे महानगर गाजियाबाद में अग्नि हादसे लगातार बरकरार है। गाजियाबाद में एक बार फिर फैक्ट्री के अंदर आग लगने का मामला सामने आया है। इस बार आग साइट-4 साहिबाबाद में फैक्ट्री में लगी। गनीमत रही की दमकल विभाग की गाड़ी सही समय पर फैक्ट्री पहुंच गई और आग को फैलने से रोक लिया गया। दमकल विभाग ने आग को पूरी तरह से बुझा दिया है। चीफ फायर ऑफिसर राहुल पाल ने बताया कि आग की सूचना प्राप्त हुई और तत्काल फायर स्टेशन साहिबाबाद से दोनों फायर टेंडर घटनास्थल के लिए रवाना हुए। घटनास्थल पर पहुंचने पर देखा कि आग आइंस्टाइन फैक्ट्री प्लाट संख्या अ-10, साइट-4, साहिबाबाद फैक्ट्री में लगी हुई थी। फैक्ट्री कर्मचारियों द्वारा प्रारंभिक स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा था। फायर सर्विस यूनिट ने त्वरित एवं कुशल कार्रवाई करते हुए टक्कू से पम्पिंग कर आग बुझाने का

कार्य प्रारंभ किया। जानकारी करने पर फैक्ट्री स्टाफ द्वारा बताया कि एल्यूमिनियम की कटिंग के दौरान निकली चिंगारी से फ्लोर पर पड़ी एल्यूमिनियम की डस्ट में आग लग गई थी। फायर सर्विस कर्मियों की सूझबूझ एवं तत्परता के कारण आग पर शीघ्र ही पूर्ण रूप से नियंत्रण पा लिया गया, जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई तथा संभावित बड़े नुकसान को टाल दिया गया। वही आग लगने से बचने के लिए फैक्ट्री कर्मियों को जागरूक किया गया है।

होली पर्व से पहले खाद्य विभाग सख्त, मिलावटी खाद्य पदार्थों पर कार्रवाई

ग्रेटर नोएडा (शिखर समाचार)। आगामी होली पर्व को ध्यान में रखते हुए जनपद में शुद्ध खाद्य एवं पेय पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने सघन जांच अभियान शुरू कर दिया है। अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम विभिन्न प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर संदिग्ध खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र कर रही है। सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय सर्वेश मिश्रा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी विशाल कुमार गुप्ता और सय्यद इबादुल्लाह की टीम ने तिलपता, ग्रेटर नोएडा स्थित चौधरी पनीर भंडार पर छापेमारी की। यहां लगभग 200 किलोग्राम पनीर पाया गया, जो प्रदूषित और प्रथम दृष्टया मिलावटी प्रतीत होने पर उसका एक नमूना जांच के लिए लिया गया तथा शेष पनीर को नष्ट करा दिया गया। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी एस.के. पांडेय और ओ.पी. सिंह की टीम ने सेक्टर 45 नोएडा स्थित गणेश्वरम रेस्टोरेंट से खोया का एक नमूना लिया। वहीं खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुकेश कुमार और विजय बहादुर पटेल की टीम ने सेक्टर 93 नोएडा स्थित गोपाला स्वीट से खोया का एक नमूना संग्रहित किया। इस प्रकार कुल तीन नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशन में यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। विभाग का उद्देश्य जनपदवासियों को निर्धारित मानकों के अनुरूप सुरक्षित एवं शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है, ताकि त्योहार के अवसर पर मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाई जा सके।

भाजपा नेता को हत्या में फंसाने की कथित साजिश, वायरल ऑडियो रिकॉर्डिंग से मचा हड़कंप

शामली (शिखर समाचार)। जनपद शामली में एक कथित वायरल ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता मनीष चौहान को एक हत्या के मामले में फंसाने की कथित साजिश का मामला सामने आया है। इस संबंध में मनीष चौहान ने कांधला थाने में तहरीर देकर तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और ऑडियो रिकॉर्डिंग की सत्यता की जांच कराई जा रही है।

बताया गया है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही ऑडियो रिकॉर्डिंग में सहारनपुर क्षेत्र के दो युवकों के बीच बातचीत सुनाई दे रही है। बातचीत में कथित रूप से सहारनपुर क्षेत्र के एक ग्राम प्रधान की हत्या कर उसका आरोप मनीष चौहान पर लगाने की योजना बनाई जा रही है। ऑडियो रिकॉर्डिंग में यह भी कहा जा रहा है कि घटना को अंजाम देने के बाद मनीष चौहान के नाम से एक वीडियो तैयार कर उसे प्रसारित किया जाएगा, ताकि उन्हें कानूनी विवाद में उलझाया जा सके और राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाया जा सके।

मनीष चौहान, वीरेंद्र सिंह के पुत्र तथा जिला पंचायत सदस्य हैं। उन्होंने कांधला थाने में दी गई तहरीर में बताया कि रोहित प्रधान नाम की एक सामाजिक माध्यम पहचान से ऑडियो रिकॉर्डिंग प्रसारित की जा रही है, जिसमें उन्हें जानबूझकर हत्या के मामले में फंसाने की साजिश रची गई है। उनका कहना है कि यह साजिश राजनीतिक द्वेष से प्रेरित प्रतीत होती है और उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है।

तहरीर में यह भी उल्लेख किया गया है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग से संबंधित कड़ी में नदीम पुत्र शब्बीर निवासी ग्राम बरला, थाना कैराना, जनपद शामली का नाम सामने आया है, जबकि दूसरे व्यक्ति की पहचान स्पष्ट नहीं हो सकी है। बातचीत के दौरान मनीष चौहान के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणियां किए जाने तथा राजनीतिक विरोध के स्वर भी सुनाई देने की बात कही गई है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार पीड़ित की शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। प्रकरण की जांच के लिए तकनीकी साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं तथा ऑडियो रिकॉर्डिंग की सत्यता का परीक्षण कराया जाएगा। जांच के निष्कर्ष के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है और संबंधित व्यक्तियों की भूमिका का पता लगाया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि सत्यता सामने आने के बाद दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

गौतम बुद्ध नगर में जिला उद्योग बंधु समिति की बैठक सम्पन्न, अनुपस्थित अधिकारियों पर जिलाधिकारी सख्त

ग्रेटर नोएडा (शिखर समाचार) जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला उद्योग बंधु समिति तथा जिला एमआईयू की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद के औद्योगिक वातावरण को अधिक सुगम, सुरक्षित एवं सुदृढ़ बनाने तथा उद्यमियों की समस्याओं का समयबद्ध और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा प्रमुख उद्यमी संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी ने नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण तथा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के वर्क सर्कल एसीईओ एवं ओएसडी के बैठक में अनुपस्थित रहने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से पत्राचार कर एक सप्ताह के भीतर विस्तृत आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि शासन को अवगत कराया जा सके और भविष्य में ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति न हो।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि संबंधित प्राधिकरण एवं जिला स्तरीय अधिकारी बैठक से पहले उद्यमियों द्वारा दी गई समस्याओं का निस्तारण सुनिश्चित करते हुए एक सप्ताह पूर्व आख्या उपलब्ध कराएं, जिससे समीक्षा बैठक अधिक प्रभावी और परिणामोन्मुखी बन सके।

बैठक में उद्यमी प्रतिनिधियों ने अतिक्रमण, यातायात जाम, कूड़ा-कचरा निस्तारण, पार्किंग की समस्या,

खराब सड़कें, स्ट्रीट लाइट, जलभराव, जीएसटी संबंधी जटिलताओं, जल आपूर्ति तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं प्रमुखता से उठाईं। साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों और प्रमुख बाजारों की स्थानीय समस्याओं से भी अधिकारियों को अवगत कराया गया।

जिलाधिकारी ने उद्यमियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि व्यापारिक गतिविधियां व्यवस्थागत बाधाओं से प्रभावित न हों। उन्होंने बाजार क्षेत्रों में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान चलाने तथा आवश्यकतानुसार जुमार्ना लगाने के निर्देश दिए। पुलिस विभाग को यातायात व्यवस्था मजबूत करने तथा व्यस्त समय में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश भी दिए गए।

कूड़ा निस्तारण व्यवस्था को सुधारने के लिए संबंधित अधिकारियों को क्षेत्रवार सफाई कर्मचारियों की सूची उपलब्ध कराने तथा उनकी नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि अनुपस्थित पाए जाने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए तथा चिन्हित कूड़ेदान स्थलों पर संबंधित कर्मचारी और वाहन चालक के मोबाइल नंबर सार्वजनिक किए जाएं, ताकि समस्या होने पर तुरंत सूचना दी जा सके।

जिलाधिकारी ने उद्यमी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए शौचालयों के समुचित रखरखाव तथा आवश्यकतानुसार नए शौचालयों के निर्माण के निर्देश भी दिए। उन्होंने सभी सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों को 24 घंटे संचालित रखने पर विशेष जोर दिया, ताकि महिला उद्यमियों एवं कर्मचारियों को सुविधा मिल सके।

बैठक का संचालन उपायुक्त उद्योग पंकज निर्वाण ने किया। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

चिकित्सक के खाते से 32 लाख रुपये ट्रांसफर मामले में, बैंक के बाहर दूसरे दिन भी जारी रहा धरना

मोदीनगर (शिखर समाचार)। नगर के चिकित्सक श्रवण कुमार शर्मा के बैंक खाते से 32 लाख रुपये ट्रांसफर होने के मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। मंगलवार को भी चिकित्सक अपने समर्थकों के साथ बैंक के बाहर धरने पर बैठे रहे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई तथा रकम वापस दिलाने की मांग करते रहे। जानकारी के अनुसार चिकित्सक श्रवण कुमार शर्मा के खाते से 17 से 19 फरवरी के बीच लगभग 32 लाख रुपये अज्ञात खातों में ट्रांसफर हो गए। चिकित्सक का नगर के एक निजी बैंक में खाता है। जब उन्हें खाते से रुपये निकलने की जानकारी हुई तो उन्होंने बैंक प्रबंधन से संपर्क किया, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद चिकित्सक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और बैंक के बाहर धरना शुरू कर दिया, जो मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। चिकित्सक का कहना है कि जब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी और उनकी रकम वापस नहीं मिलेगी, तब तक उनका धरना जारी रहेगा। इस संबंध में एसीपी भास्कर वर्मा ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

किराना मर्चेंट एसोसिएशन के प्रधान राकेश सिंहल व मंत्री सौरभ गोयल निर्विरोध चुने गए

हापुड़ (शिखर समाचार) हापुड़ किराना मर्चेंट एसोसिएशन के चुनाव में अधिकांश पदों पर निर्विरोध निर्वाचन संपन्न हुआ। एक एक नामांकन दाखिल होने के कारण राकेश सिंहल (के.बी) को प्रधान, सौरभ गोयल पंसारी को मंत्री तथा अंकुर कंसल दाल मिल वाले को कोषाध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुना गया। चुनाव अधिकारी राजेंद्र कुमार पंसारी ने बताया कि एसोसिएशन के प्रधान पद के लिए केवल राकेश सिंहल ने ही नामांकन

पत्र दाखिल किया था, जिसके चलते उन्हें निर्विरोध प्रधान घोषित किया गया। इसी प्रकार मंत्री पद पर सौरभ गोयल तथा कोषाध्यक्ष पद पर अंकुर कंसल को निर्विरोध चुना गया। इसके अतिरिक्त उपप्रधान पद पर अमित जिंदल और जुगेंद्र गुप्ता को निर्विरोध निर्वाचित किया गया।

उपमंत्री के दो पदों के लिए चार नामांकन प्राप्त हुए हैं। इन पदों पर चार मार्च को मतदान कराया जाएगा, जिसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे।

बीएसए कार्यालय पर शिक्षक टीईटी अनिवार्यता के विरोध में करेंगे धरना प्रदर्शन : नीरज चौधरी

हापुड़ (शिखर समाचार)। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता थोपे जाने के विरोध में शिक्षक संगठन के आह्वान पर दूसरे दिन भी जनपद के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों ने बांह पर काली पट्टी बांधकर शिक्षण कार्य किया। शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष देवेन्द्र शिशौदिया और जिला मंत्री नीरज चौधरी ने संयुक्त रूप से बताया कि परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक 24 और 25 फरवरी को भी काली पट्टी बांधकर शिक्षण कार्य करेंगे। इसके बाद 26 फरवरी को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय हापुड़ पर धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आगामी मार्च माह के तीसरे सप्ताह में दिल्ली में भी एक बड़ी रैली का आयोजन प्रस्तावित है, जिसमें विभिन्न जनपदों से शिक्षक भाग लेंगे। शिक्षक नेताओं का कहना है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता से मुक्त किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि जब तक वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा से छूट नहीं दी जाएगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष संदीप सिरोही ने कहा कि सरकार को इस निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए शिक्षकों को सम्मानजनक समाधान देना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शिक्षकों की मांगों को अनदेखा किया गया तो विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। इस अवसर पर योगेश सैनी, प्रवेश सैनी, संजय कुमार, जफर, अंकुर त्यागी, अमित कुमार, अमरजीत, आबिद अली, कंचन, सुधा यादव और कपिल कुमार सहित अनेक शिक्षक उपस्थित रहे।

गाली गलौज के विरोध पर मारपीट और पथराव, कई घायल

गढ़मुक्तेश्वर (शिखर समाचार) गढ़ नगर के मोहल्ला राजीव नगर में बारात के दौरान शुरू हुआ विवाद बाद में हिंसक झड़प में बदल गया। गाली गलौज का विरोध करने पर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट और पथराव हुआ, जिसमें कई लोग घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार गढ़ नगर निवासी कुंवरपाल पड़ोसी की बारात में शामिल होने गए थे। बारात की चढ़त के दौरान एक युवक से कहासुनी और गाली गलौज हो गई, जिसे मौके पर मौजूद लोगों ने शांत करा दिया था। आरोप है कि बारात से लौटते समय आरोपी पक्ष ने गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। विरोध करने पर कुछ लोग पीड़ित के घर में घुस आए और हमला कर दिया। हमले के दौरान बीच बचाव करने पहुंचे अंकित, राजेंद्र, संजय, अमरजीत सिंह, प्रवीण और पूनम घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा और मामले की जानकारी ली। बताया गया कि आरोपी पक्ष ने दोबारा पीड़ित पक्ष के घरों पर पथराव कर दिया, जिससे मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। पुलिस के पहुंचते ही आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घटनास्थल से एक धारदार हथियार बरामद किया है। कोतवाली पुलिस का कहना है कि मामले की जांच शुरू कर आरोपियों की तलाश की जा रही है।

फैक्ट्री के अवशिष्ट से गंगा का जल प्रभावित, पुरोहितों में रोष

गढ़मुक्तेश्वर (शिखर समाचार) ब्रजघाट में गंगा के जल का रंग काला पड़ने से तीर्थनगरी के पुरोहितों और श्रद्धालुओं में भारी रोष व्याप्त है। श्रद्धालुओं ने प्रशासन से गंगा में अतिरिक्त जल छोड़े जाने और जल के रंग परिवर्तन की जांच कर कार्रवाई की मांग की है।

ब्रजघाट नगरी में गंगा का जल अचानक काला दिखाई देने लगा, जिसे देखकर श्रद्धालुओं में चिंता फैल गई। आदर्श गंगा समिति के तीर्थ पुरोहित अध्यक्ष राजकुमार शर्मा लालू का कहना है कि गंगा का जल अचानक काला पड़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि किसी फैक्ट्री द्वारा रसायनयुक्त पानी छोड़ा गया है।

उन्होंने बताया कि पिछले कई दिनों से गंगा का जल साफ और स्वच्छ बह रहा था, लेकिन बीती रात अचानक जल का रंग बदल गया। इससे ब्रजघाट में स्नान करने आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था प्रभावित हुई है।

उपजिलाधिकारी श्रीराम यादव ने बताया कि गंगा की पवित्रता शासन प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। समय समय पर आसपास के उद्योगों की जांच कराई जाती है। यदि बिना शोधन के अवशिष्ट डाला जा रहा है तो यह गंभीर मामला है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के साथ टीम गठित कर जांच कराई जाएगी।

संपादकीय

एआई इंपैक्ट समिट में कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन पर राजनीति : क्या उचित, क्या अनुचित

हाल ही में आयोजित ए इंपैक्ट सबमिट के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा किए गए शर्टलेस प्रदर्शन ने भारतीय राजनीति में एक नई बहस को जन्म दिया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध और प्रदर्शन नागरिक अधिकारों का हिस्सा होते हैं, लेकिन विरोध के तरीके हमेशा चर्चा का विषय बन जाते हैं। यही कारण है कि इस घटना ने राजनीतिक गरिमा, विरोध की संस्कृति और लोकतांत्रिक मयार्दाओं पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि क्या इस प्रकार का प्रदर्शन जनता की समस्याओं को सामने लाने का प्रभावी तरीका है या फिर यह केवल राजनीतिक सुर्खियां बटोरने का माध्यम बनकर रह जाता है।

भारतीय लोकतंत्र की परंपरा में विरोध प्रदर्शन हमेशा से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज तक राजनीतिक दलों ने अपनी बात रखने के लिए धरना, प्रदर्शन, पदयात्रा और आंदोलन जैसे अनेक तरीकों का उपयोग किया है। इन आंदोलनों ने कई बार सरकारों को नीतियां बदलने पर मजबूर भी किया है। लेकिन लोकतांत्रिक विरोध की एक मयार्दा भी होती है, जो उसे गंभीरता और विश्वसनीयता प्रदान करती है। जब विरोध प्रदर्शन प्रतीकात्मकता से आगे बढ़कर नाटकीयता का रूप ले लेते हैं, तब उनकी गंभीरता पर सवाल उठना स्वाभाविक हो जाता है।

ए इंपैक्ट सबमिट के दौरान हुआ शर्टलेस प्रदर्शन भी इसी श्रेणी में आता है। प्रदर्शन करने वाले नेताओं का तर्क था कि वे महंगाई, बेरोजगारी या अन्य जनसमस्याओं को उजागर करना चाहते थे और इस तरह का प्रदर्शन जनता का ध्यान आकर्षित करने का माध्यम था। निस्संदेह, किसी भी लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका सरकार को आईना दिखाने की होती है और विपक्ष अगर आवाज नहीं उठाएगा तो लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। इस दृष्टि से देखा जाए तो विरोध का अधिकार पूरी तरह वैध है। लेकिन दूसरी ओर यह भी सच है कि सार्वजनिक मंचों पर इस प्रकार का प्रदर्शन राजनीतिक संवाद को गंभीरता से हटाकर तमाशे की दिशा में ले जाता है। आज के दौर में मीडिया और सोशल मीडिया की शक्ति इतनी अधिक है कि किसी भी घटना की तस्वीरें और वीडियो कुछ ही मिनटों में पूरे देश में फैल जाते हैं। ऐसे में प्रदर्शन का स्वरूप अक्सर मुद्दों से अधिक प्रदर्शन की शैली पर केंद्रित हो जाता है। परिणाम यह होता है कि जिन समस्याओं को सामने लाने का दावा किया जाता है, वे पीछे छूट जाती हैं और चर्चा केवल विरोध के तरीके तक सीमित रह जाती है।

राजनीति का स्तर गिरने की बात अक्सर कही जाती है। संसद से लेकर सड़कों तक भाषा और व्यवहार में गिरावट की शिकायतें आम हैं। ऐसे समय में राजनीतिक दलों से अपेक्षा की जाती है कि वे जनता के सामने एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करें। विरोध की संस्कृति लोकतंत्र का अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन विरोध ऐसा होना चाहिए जो जनता को प्रेरित करे और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत बनाए। यदि विरोध केवल सनसनी पैदा करने के लिए किया जाएगा तो वह अल्पकालिक चर्चा तो पैदा कर सकता है, लेकिन दीर्घकालिक प्रभाव नहीं छोड़ पाएगा।

यह भी ध्यान रखना चाहिए कि राजनीति केवल नेताओं की नहीं बल्कि जनता की भी होती है। आम नागरिक अपने प्रतिनिधियों से गंभीरता, संयम और जिम्मेदारी की अपेक्षा करता है। जब नेता असामान्य या नाटकीय तरीके अपनाते हैं तो जनता के मन में राजनीति की छवि कमजोर होती है। लोकतंत्र की मजबूती केवल चुनाव जीतने से नहीं बल्कि राजनीतिक आचरण की गुणवत्ता से भी तय होती है।

~ मौलिक चिंतन ~

हार न मानने से भी जीत की संभावना को बल मिलता है।

© विनय संकोची

कार्टेल के खिलाफ जंग और मेक्सिको की अग्निपरीक्षा

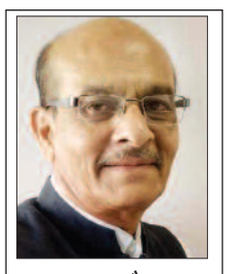

सनत जैन

मेक्सिको में कुख्यात ड्रग सरगना नेमेंसियो ओसेगेरा सर्वांतेस उर्फ 'एल मेंचो' के मारे जाने की खबर के बाद हुई भारी हिंसा से मेक्सिको को अनिश्चितता के दौर में लाकर खड़ा कर दिया है। आम जनता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करती नजर आई है। नशे के कारोबार में (सीजेएनजी) प्रमुख के रूप में ड्रग लॉर्ड को न केवल मेंक्सिको, बल्कि अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का केंद्रीय चेहरा माना जाता था। मेक्सिको की सरकार इस कार्रवाई को बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत कर रही है। किंतु ड्रग सरगना के मारे जाने के तुरंत बाद भड़की आगजनी, हाईवे जाम और सुरक्षा कर्मियों पर हमले से यह सवाल उठता है, क्या किसी सरगना के मारे जाने पर जनता का विद्रोह इस रूप में देखने को मिल सकता है? एल मेंचो पर अमेंरिका की सरकार ने बड़ा इनाम घोषित किया था। डोनाल्ड ट्रम्प के कार्यकाल से ही मेक्सिको पर ड्रग तस्करी के खिलाफ कठोर कार्रवाई का दबाव अमेंरिका की सरकार बनाती रही है। फेंटानिल संकट ने अमेंरिका की आंतरिक राजनीति को झकझोर दिया है, इसका प्रभाव द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ना तय है। मेक्सिको की हिंसा केवल आंतरिक सुरक्षा का प्रश्न नहीं है, बल्कि इसका असर अमेंरिका सहित अन्य देशों पर भी पड़ना तय है। यह घटना भू-राजनीतिक समीकरणों से भी जुड़ी दिखती है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या यह मेक्सिको की संप्रभु रणनीति का हिस्सा है, या अमेंरिकी दबाव का परिणाम है। इतिहास बताता है कि कार्टेल के शीर्ष नेता को मार देने से इस समस्या का हल नहीं होता है। इससे ड्रग के कारोबार, राजनीतिक एवं सामाजिक संबंधों में स्थिरता संभव नहीं है। 2016 में जोक्विन एल चापो गुजमान की गिरफ्तारी के बाद भी बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। आम जनता और सत्ता के बीच संघर्ष बढ़ा था। संगठित अपराध का नेटवर्क समानांतर व्यवस्था की तरह संचालित होता है। एक चेहरा हटता है, तो उसके कई दावेदार उभरते हैं। गैंग में वर्चस्व की लड़ाई आम नागरिकों की सुरक्षा और जीवन यापन के लिए सबसे बड़ा खतरा बनती है। एल मेंचो की मौत के बाद इस तरह की घटनाएं इसी आशंका को पुष्ट कर रही हैं। ड्रग कारोबार और राजनीतिक संरक्षण का मूल मेक्सिको, अमेंरिका एवं कई अन्य देशों तक फैला हुआ है। दशकों से मेक्सिको में फैली गरीबी, बेरोजगारी, राजनीतिक संघर्ष, भ्रष्टाचार और कमजोर तथा भ्रष्ट न्यायिक व्यवस्था से जुड़ता है। मेक्सिको के सीमावर्ती इलाकों में प्रशासनिक पकड़ हमेंशा से कमजोर रही है। नशे के कारोबारी और इससे जुड़े हुए लोगों की समानांतर सत्ता चलती है। नशे के कारोबार में लगे अपराधी तत्व जिस तरह से काम करते हैं, उससे स्थानीय कारोबारियों को वसूली के डर से नियंत्रण और सीमापार तस्करी इनके साधन हैं। ऐसे में सैन्य कार्रवाई समाधान नहीं हो सकती है। मेक्सिको सरकार के लिए यह दोहरी चुनौती है। एक ओर सरकार के ऊपर तत्काल कानून-व्यवस्था बहाल कर नागरिकों में भरोसा कायम करना है, दूसरी ओर दीर्घकालिक सुधारों पर गंभीरता से काम करना होगा।

मेक्सिको में न्यायिक पारदर्शिता, गवाहों की सुरक्षा, नशे की कारोबार में नेटवर्क पर वित्तीय प्रहार और पुलिस सुधार अनिवार्य है। सरकार, पुलिस और प्रशासन के बीच का भ्रष्टाचार रोकना, संस्थागत ढांचे को मजबूत नहीं किया तो यह 'जीत' अस्थायी साबित होगी। इसके साथ ही, इसका असर अमेंरिका में भी पड़ना तय है। अमेंरिका की सुरक्षा एजेंसियों और सरकार को भी आत्ममंथन करने की जरूरत है। जब तक अमेंरिका में नशीली दवाओं की मांग बनी रहेगी, आपूर्ति के नए रास्ते और नए गिरोह समय-समय पर उभरते रहेंगे। नशे का कारोबार केवल मेक्सिको की समस्या नहीं है। यह अंतरराष्ट्रीय समस्या है। इससे निपटने के लिए साझा जिम्मेंदारी जरूरी है। दबाव की नीति के बजाय सहयोग, खुफिया साझेदारी और सामाजिक पुनर्वास कार्यक्रमों पर ध्यान देना होगा। एल मेंचो का अंत प्रतीकात्मक जीत हो सकती है, असली परीक्षा तो अब शुरू होगी। यदि मेक्सिको में सुशासन और पारदर्शिता चाहिए तो भुखमरी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए सामाजिक निवेश की ठोस रणनीति बनानी होगी। तभी नशे के कारोबार के गैंगस्टरों की छाया से मेक्सिको बाहर निकल पाएगा। इतिहास खुद को दोहराने में देर नहीं करता है। नशे के कारोबार का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है, इसमें भारी पैसा है। इस नेटवर्क को इस तरह से खत्म नहीं किया जा सकता है, जिस तरह से अभी कार्रवाई की गई है। कार्यवाही के पश्चात जिस तरह के हालात मेक्सिको के बन गए हैं, उस चुनौती से निपटना सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है। अमेंरिका इस मामले में मेक्सिको की क्या मदद करता है, यह भी देखना होगा।

कचरे पर कड़ा रुख: न्यायपालिका के निर्देश और जमीनी सच्चाई

सुनील कुमार महला

ठोस कचरे का प्रबंधन आज के समय की एक बहुत बड़ी आवश्यकता बन चुका है। कहना गलत नहीं होगा कि आज लगातार बढ़ती जनसंख्या, बढ़ते शहरीकरण, औधोगिकीकरण और उपभोग की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण धरती पर ठोस कचरे की मात्रा लगातार बढ़ रही है, जिससे हमारे पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र, मानव व जीवों के स्वास्थ्य और विभिन्न संसाधनों पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। यदि इस कचरे का सही तरीके से संग्रहण, पृथक्करण, पुनर्चक्रण(रि-साइक्लिंग) और इसका समय रहते निपटान नहीं किया गया, तो नीले ग्रह(धरती पर) पर भूमि, जल और वायु प्रदूषण की समस्या और भी गंभीर हो सकती है।

वास्तव में, आज के समय में ठोस कचरे को बोझ नहीं बल्कि संसाधन के रूप में देखने की आवश्यकता है। गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग करना, जैविक कचरे से खाद बनाना, प्लास्टिक और अन्य पदार्थों का पुनर्चक्रण(रि-साइक्लिंग) करना तथा जन-जागरूकता बढ़ाना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि स्वच्छ और स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए ठोस कचरे का प्रभावी प्रबंधन केवल सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह तो प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। जब समाज और प्रशासन मिलकर प्रयास करेंगे, तभी सतत विकास(सस्टेनेबल डेवलपमेंट) और स्वच्छ पर्यावरण का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा।

बहरहाल, यहां पाठकों को बताता चलूं कि इस क्रम में हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ठोस कचरा प्रबंधन नियमों के ठीक से पालन न होने पर चिंता जताई है और 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नए नियमों को प्रभावी बनाने के लिए कई निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि साफ और स्वस्थ पर्यावरण में जीना, जीवन के अधिकार का ही अहम् हिस्सा है। गौरतलब है कि न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति एस. वी. एन. भट्टी की पीठ ने 19 फरवरी को यह आदेश सुनाया। दरअसल, यह मामला भोपाल नगर निगम की उन अपीलों से जुड़ा था, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ दायर की गई थीं।

अदालत ने यह बात कही है कि अभी कानून में सुधार का इंतजार करना ठीक नहीं है, क्योंकि कचरे की खराब व्यवस्था से लोगों के स्वास्थ्य और देश की अर्थव्यवस्था दोनों पर असर पड़ता है। कोर्ट ने माना कि पूरे देश में कचरा प्रबंधन नियमों का पालन समान रूप से नहीं हो रहा है और घरों से गीला-सूखा-खतरनाक कचरा अलग-अलग करने की व्यवस्था अभी तक भी पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई है। बड़े शहरों में बढ़ते कचरे के ढेर भी चिंता का कारण हैं।कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा अब नहीं तो कभी नहीं और स्पष्ट किया कि अगर स्रोत पर कचरा अलग नहीं होगा और जरूरी सुविधाएं नहीं होंगी, तो अच्छे परिणाम की उम्मीद करना व्यर्थ है। अदालत ने पार्षदों, महापौरों और वार्ड प्रतिनिधियों को कचरा अलग कराने के लिए जिम्मेदार लीड फैसिलिटेटर बनाने को कहा, ताकि हर नागरिक नियमों का पालन करे। यहां पाठकों को बताता चलूं कि लीड फैसिलिटेटर वह व्यक्ति होता है जो किसी कार्यक्रम, प्रशिक्षण, कार्यशाला या परियोजना में पूरे समूह की प्रक्रिया का नेतृत्व करता है और यह सुनिश्चित करता है कि गतिविधियाँ सही दिशा में और निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार चलें। अच्छी बात यह है कि सभी नगर निकायों को 100% पालन के लिए समय-सीमा तय कर सार्वजनिक करने, प्रगति की फोटो जिलाधिकारी को भेजने और बड़े कचरा उत्पादकों से 31 मार्च तक नियमों का पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। इतना ही नहीं, प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को चार तरह के कचरे (गीला, सूखा, सैनिटरी और विशेष) के अलग-अलग प्रबंधन की व्यवस्था जल्दी तैयार करने को कहा गया है।

अदालत ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्देश दिया कि कचरा प्रबंधन नियमों को स्कूल की पढ़ाई में शामिल किया जाए और इन्हें सभी राज्यों की स्थानीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराया जाए।अब नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई होगी। पहले जुमार्ना, बार-बार उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई और जरूरत पड़ने पर आपराधिक केस भी दर्ज किया जा सकता है। लापरवाही करने वाले अधिकारी भी इसके दायरे में आएंगे। कोर्ट ने मोबाइल अदालतों की संभावना पर भी विचार करने की बात कही है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 1 अप्रैल 2026 से देश के सभी न्यायालयों और संस्थानों में भी कचरा प्रबंधन नियमों का पालन होना चाहिए। नगर निकायों को लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए अभियान चलाने होंगे, जैसे कचरा कम करना, घर में खाद बनाना और सैनिटरी कचरे को सुरक्षित तरीके से पैक करना।ये सभी निर्देश इसलिए दिए गए हैं ताकि 1 अप्रैल 2026 से पहले पूरी तैयारी हो सके और नियम सही तरीके से लागू किए जा सकें।

अंत में यही कहूंगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सही चिंता जताई है कि ठोस कचरा प्रबंधन केवल पर्यावरण नहीं, बल्कि जन-स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। नियमों के कमजोर अनुपालन, स्थानीय निकायों की जवाबदेही की कमी और योजनाओं जैसे अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन तथा स्मार्ट सिटीज मिशन में खामियों के कारण समस्या बढ़ी है। समाधान के लिए सख्त नियम लागू करना, जनजागरण, अधिकारियों की जवाबदेही और बेहतर शहरी अवसंरचना निवेश अनिवार्य हैं, तभी कचरा-मुक्त भारत का लक्ष्य संभव हो पाएगा।

मुफ्त रेवड़ी संस्कृति जीवंत लोकतंत्र के लिये घातक

ललित गर्ग

लोकतंत्र का मूल उद्देश्य जनकल्याण है। राज्य का दायित्व है कि वह गरीब, वंचित और कमजोर वर्गों को सहारा दे। सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं, न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी-ये सब कल्याणकारी राज्य की पहचान हैं। लेकिन जब जनहित और चुनावी लाभ के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, तब समस्या जन्म लेती है। लक्षित समर्थन और अतिरेक उदारता में अंतर है। एक ओर ऐसी योजनाएं हैं जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती हैं, दूसरी ओर ऐसी घोषणाएं हैं जो केवल मतदाता को तात्कालिक राहत देकर उसे निर्भरता की आदत सिखाती हैं।

भारतीय लोकतंत्र की विडंबना यह है कि चुनाव आते ही जनसेवा का स्वरूप बदलकर जनलुभावन राजनीति में परिवर्तित हो जाता है। राजनीतिक दलों ने मुफ्त की योजनाओं को चुनावी सफलता का शॉर्टकट बना लिया है। मतदाताओं को तात्कालिक आर्थिक लाभ देकर वोट हासिल करने की प्रवृत्ति लगातार मजबूत हो रही है। आगामी तीन-चार माह में विधानसभा चुनाव होने है, इसी संदर्भ में जब असम, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हुईं, तब इस संस्कृति का प्रभाव और स्पष्ट दिखाई देने लगा। इसी पृष्ठभूमि में देश की शीर्ष अदालत, सर्वोच्च न्यायालय, ने मुफ्त की योजनाओं के अनियंत्रित विस्तार पर गंभीर टिप्पणी की। यह टिप्पणी केवल कानूनी दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा को लेकर एक चेतावनी है।

लोकतंत्र का मूल उद्देश्य जनकल्याण है। राज्य का दायित्व है कि वह गरीब, वंचित और कमजोर वर्गों को सहारा दे। सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं, न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी-ये सब कल्याणकारी राज्य की पहचान हैं। लेकिन जब जनहित और चुनावी लाभ के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, तब समस्या जन्म लेती है। लक्षित समर्थन और अतिरेक उदारता में अंतर है। एक ओर ऐसी योजनाएं हैं जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती हैं, दूसरी ओर ऐसी घोषणाएं हैं जो केवल मतदाता को तात्कालिक राहत देकर उसे निर्भरता की आदत सिखाती हैं। जब राजस्व घाटे से जूझ रहे राज्य मुफ्त बिजली, मुफ्त यात्रा या नकद वितरण की घोषणाएं करते हैं, तो प्रश्न उठता है कि यह संसाधन कहां से आएंगे और इसकी कीमत कौन चुकाएगा? राजकोषीय अनुशासन किसी भी राज्य की आर्थिक सेहत का आधार है। यदि राज्य अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिए खजाने को खाली करता है, तो दीर्घकालिक विकास प्रभावित होता है। जो धन बुनियादी ढांचे के निर्माण, अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण, विद्यालयों की गुणवत्ता सुधार और रोजगार सृजन में लगना चाहिए, वह वोटों की फसल काटने में खर्च हो जाता है। यह प्रवृत्ति केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि नैतिक दृष्टि से भी चिंताजनक है। लोकतंत्र में मतदाता की स्वतंत्रता सर्वोपरि मानी जाती है। यदि मतदाता को परोक्ष रूप से आर्थिक प्रलोभन देकर प्रभावित किया जाता है, तो यह स्वतंत्र निर्णय की भावना को कमजोर करता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने तार्किक प्रश्न उठाया कि राज्य रोजगार सृजन और कौशल विकास पर अधिक ध्यान क्यों नहीं देते? वास्तव में रोजगार ही स्थायी सशक्तीकरण का माध्यम है। जब व्यक्ति अपने श्रम और कौशल से आय अर्जित करता

है, तब उसमें आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दोनों विकसित होते हैं। इसके विपरीत, निरंतर मुफ्त सुविधाएं व्यक्ति को निर्भर बनाती हैं। धीरे-धीरे परिश्रम की संस्कृति कमजोर पड़ती है और समाज में अकर्मण्यता की मानसिकता पनपने लगती है। यह स्थिति लोकतंत्र की सुदृढ़ता के लिए खतरनाक है, क्योंकि लोकतंत्र केवल वोट डालने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि सक्रिय और जिम्मेदार नागरिकता का नाम है। चुनाव पूर्व घोषित योजनाओं की निष्पक्षता भी प्रश्नों के घेरे में है। जब आचार संहिता लागू रहने के दौरान बड़े पैमाने पर आर्थिक वितरण होता है, तो विपक्षी दल इसे असमान प्रतिस्पर्धा मानते हैं। ऐसे मामलों में निष्पक्ष निगरानी की जिम्मेदारी भारत का निर्वाचन आयोग पर आती है। निर्वाचन आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी दल मतदाताओं को अप्रत्यक्ष रिश्वत देकर चुनावी लाभ न ले। आचार संहिता का उल्लंघन केवल तकनीकी त्रुटि नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मयार्दा का हनन है। यदि इस पर कठोर कार्रवाई नहीं होती, तो भविष्य में यह प्रवृत्ति और गहरी जड़ें जमा सकती है। निस्संदेह, इस बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती है कि राज्यों का यह प्राथमिक कर्तव्य है कि वे विशेष रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की खास तौर से देखभाल करें। हालांकि, जब राजस्व घाटे वाले राज्य मुफ्त की योजनाओं पर बड़ी रकम खर्च करते हैं, तो सरकारी खजाने पर दबाव और अधिक बढ़ जाता है। विडंबना यह है कि जिस धनराशि का इस्तेमाल बुनियादी ढांचे में सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं को सक्षम बनाने और शिक्षा की सुविधा को समृद्ध करने के लिये किया जाना चाहिए, वो राशि अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिये खर्च कर दी जाती है। जरूरत इस बात की है कि कौशल विकास के जरिये लोगों को इस तरह सक्षम बनाया जाए जिससे उन्हें दीर्घकालिक व स्थायी लाभ मिल सकें।

यह भी समझना होगा कि मुफ्त योजनाओं का हर स्वरूप गलत नहीं है। आपातकालीन परिस्थितियों में राहत देना, महामारी या प्राकृतिक आपदा के समय सहायता पहुंचाना, सामाजिक न्याय के तहत वंचित वर्गों को अवसर देना-ये सब राज्य की जिम्मेदारी है। परंतु चुनावी मौसम में अचानक घोषणाओं की बाढ़ आ जाना और दीर्घकालिक वित्तीय परिणामों की अनदेखी करना लोकतांत्रिक परिपक्वता का संकेत नहीं है। यह राजनीतिक दलों के वैचारिक दिवालियेपन को दशार्ता है, जहां दूरदृष्टि की जगह तात्कालिक लाभ को प्राथमिकता दी जाती है। लोकतंत्र की मजबूती केवल संस्थाओं से नहीं, बल्कि नागरिकों की सजगता से भी आती है। यदि मतदाता केवल तात्कालिक लाभ देखकर मतदान करता है, तो वह अनजाने में ऐसी संस्कृति को प्रोत्साहित करता है जो अंततः उसी के भविष्य को प्रभावित करती है। परिपक्व मतदाता वही है जो घोषणाओं के पीछे की मंशा और आर्थिक व्यवहार्यता को समझे। वह यह पूछे कि पांच साल बाद राज्य की आर्थिक स्थिति क्या होगी, विकास की दिशा क्या होगी और रोजगार के अवसर कितने बढ़ेंगे। लोकतंत्र में वोट केवल अधिकार नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी है।

आज भारत स्वयं को वैश्विक मंच पर एक सशक्त लोकतंत्र के रूप में स्थापित करना चाहता है। हम विश्वगुरु बनने का संकल्प लेते हैं, लेकिन यदि हमारी राजनीति लोकलुभावनवाद के जाल में उलझी रहेगी, तो यह संकल्प खोखला सिद्ध होगा। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का गौरव तभी सार्थक है जब हमारी नीतियां दूरदर्शी, संतुलित और टिकाऊ हों। मुफ्त की संस्कृति से बाहर निकलकर उत्पादकता, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना ही वास्तविक प्रगति का मार्ग है। यह समय आत्ममंथन का है। राजनीतिक दलों को समझना होगा कि जनता को सशक्त बनाना केवल धन बांटने से संभव नहीं है। शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य और रोजगार-ये चार स्तंभ किसी भी राष्ट्र की मजबूती तय करते हैं। यदि इन पर निवेश बढ़ेगा, तो नागरिक आत्मनिर्भर बनेंगे और राज्य पर बोझ कम होगा। वहीं, नागरिकों को भी यह ठानना होगा कि वे तात्कालिक प्रलोभनों के बजाय दीर्घकालिक विकास को प्राथमिकता देंगे। लोकतंत्र की सुदृढ़ता तभी सुनिश्चित होगी जब शासन और जनता दोनों अपने-अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करें।

निस्संदेह, चुनावी निष्पक्षता के लिये यह आवश्यक हो गया है कि चुनाव से पहले घोषित की गई या लागू की गई लोकलुभावनी नीतियों व योजनाओं की गहन पड़ताल की जाए। विपक्षी दलों द्वारा बिहार सरकार पर आरोप लगाया गया था कि पिछले साल अक्तूबर में आचार संहिता लागू रहने के दौरान मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिला लाभार्थियों को 15,600 करोड़ रुपये दिए गए थे। जो कि स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विरुद्ध कदम था। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि भारत के निर्वाचन आयोग की ओर से राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को अपरोक्ष रूप से रिश्वत देने के प्रयासों पर पैनी नजर रखी जाए। साथ ही इस दिशा में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के रूप में कार्रवाई भी करनी चाहिए। निर्विवाद रूप से चुनाव प्रक्रिया में कोई भी पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाना हमारे जीवंत लोकतंत्र के लिये हानिकारक है। मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की प्रवृत्ति लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करती है। यह कार्य करने की मानसिकता को बाधित करती है और समाज में सरकार-निर्भरता एवं अकर्मण्यता की संस्कृति को जन्म देती है। यदि इस प्रवृत्ति पर समय रहते नियंत्रण नहीं लगाया गया, तो आर्थिक असंतुलन और राजनीतिक अविश्वास दोनों बढ़ेंगे। इसलिए आवश्यक है कि नीतियों की पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन और चुनावी निष्पक्षता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। यही लोकतंत्र की वास्तविक रक्षा है, यही राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला है।

आयरन की कमी से जूझती आधुनिक महिलाएं

संतुलित जीवनशैली ऐसी चीज है, जिसके बारे में अनेक महिलाओं के लिये बातें करना बहुत आसान होता है लेकिन जब इसे जीवन में लागू करने की बात आती है तो यह बहुत कठिन होता है। आधुनिक भारतीय कामकाजी महिलाएं तनावपूर्ण जिंदगी और थकाने वाली जिम्मेदारियों के बीच संतुलन स्थापित करते हुए ताउम्र चलती हैं। सुबह उठकर नाश्ता बनाने से लेकर, बच्चों का लंच, उन्हें तैयार कर स्कूल भेजना, पति को दफ्तर जाने के लिये तैयार करती हैं और खुद समय पर अपने ऑफिस पहुंचने के लिये भागदौड़ करती हैं। शाम को थकी-मांदी घर लौटती हैं और रसोई के काम में जुट जाती हैं, रात का भोजन तैयार करती है, बच्चों को होम वर्क कराती हैं और अगले दिन की तैयारी करती हैं।

इस थकान का असर महिलाओं के स्वास्थ्य पर पड़ता है। यही वजह है कि अधिकतर महिलाएं एनीमिया (खून में हीमोग्लोबिन का कम स्तर) ग्रस्त हो जाती है। इस कारण शरीर में ऑक्सीजन के स्तर में कमी आ जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप हमेशा थकान महसूस होती है। एनीमिया विश्व भर में सामान्य समस्या है, जिससे दुनिया भर में 40 करोड़ महिलाएं ग्रस्त हैं।

भारत सरकार के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एन एफ एच एस) की आर से 2006 में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार हर दो में से एक महिला एनीमिया से पीड़ित है और 15 से 49 वर्ष के आयु वर्ग में 39 प्रतिशत भारतीय महिलाएं मामूली एनीमिया से गस्त हैं। इसका मतलब यह हुआ कि भारत में प्रजनन आयु वर्ग की कुल साढ़े ग्यारह करोड़ महिलाएं एनीमियाग्रस्त हैं। इंडियन जर्नल आफ कम्युनिटी मेडिसिन में प्रकाशित अध्ययन रिपोर्ट से यह तथ्य उजागर हुआ है कि केवल आयरन एवं फोलिक एसिड के सप्लीमेंट का सेवन एनीमिया को रोकने या उसे दूर करने के लिहाज से अपर्याप्त है। एनीमिया से बचने तथा इसे दूर करने के लिये रक्त निर्माण करने वाले (हीमोपोएटिक) पोषक तत्वों का सेवन उतना ही महत्वपूर्ण है। आयरन के अलावा ऐसे अन्य पोषक तत्व भी हैं, जो एनीमिया से या तो बचा सकते हैं या उसे कम कर सकते हैं। इन पोषक तत्वों में विटामिन बी 6, विटामिन बी 2, विटामिन बी 12, विटामिन सी, फ्लोएट और प्रोटीन शामिल हैं। ये पोषक तत्व रक्त निर्माण (हीमोपोएसिस) की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इन तत्वों को हीमोपोएटिक पोषक तत्व का नाम दिया गया है।

समुचित आहार के साथ जरूरी है कि आहार को सही तरीके से लिया जाये। ज्यादातर महिलाएं यह नहीं जानतीं कि भोजन के साथ चाय, काफी या कोला का सेवन करने से आयरन पचाने की शरीर की क्षमता घट जाती है और इससे शरीर में आयरन की कमी हो जाती है। भारत में आमतौर पर खाये जाने वाले भोजन में मुख्य तौर पर अनाज होते हैं जिसमें फायटेट नामक पदार्थ होते हैं, ये आयरन पचाने की शरीर की क्षमता घटाते हैं। भोजन के साथ विटामिन सी युक्त फलों एवं सलाद का सेवन करना लाभदायक होता है क्योंकि ये आयरन पचाने की शरीर की क्षमता को बढ़ाते हैं।

अधिकतर महिलाएं थकावट, खराब त्वचा, बेजान बाल, गुस्सैल प्रवृत्ति और एकाग्रता में कमी जैसे स्पष्ट लक्षणों की भी अनदेखी करती हैं क्योंकि वे मानती हैं कि ये सभी आधुनिक व्यस्त जीवन के अभिन्न हिस्से हैं। सभी आवश्यक हीमोपोएटिक पोषक तत्वों से भरपूर पोषक सप्लीमेंट्स की समुचित खुराक को नियमित रूप से लेने से इन पोषण तत्वों की रोजाना की कमी का सामना करने में मदद मिलती है। आदर्श सप्लीमेंट वह है, जिसमें शरीर के रोजाना की कार्यप्रणाली के लिये जरूरी अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्वों के साथ-साथ हीमोपोएटिक पोषक तत्व वांछित स्तर तक मौजूद हों।

मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है भोजन

भोजन का संबंध न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य से है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य से भी है। अमेरिका में हुए शोधों से पता चला है कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य काफी हद तक भोजन पर ही निर्भर करता है। डिप्रैशन आदि मनोरोग किसी पौष्टिक तत्व के अभाव में भी हो सकते हैं या किसी खाद्य पदार्थ से एलर्जी के कारण भी। एक शोध में विशेषज्ञों ने डिप्रैशन से पीड़ित कुछ लोगों पर प्रयोग किया और पाया कि उन व्यक्तियों में डिप्रैशन की वजह गेहुं से एलर्जी थी।

हेल्थ प्लस

किडनी रोगों से बचाता है विटामिन डी

किडनी संबंधी जटिल बीमारियों (सीकेडी) की चपेट में आने से होने वाली मौतें विटामिन डी के सेवन से कम हो सकती है। अमेरिकी शोधकर्ताओं ने इस संबंध में खुलासा किया है। किडनी संबंधी बीमारियों से होने वाली मौतें विटामिन डी के सेवन से चार गुना कम हो सकती है। वाशिंगटन विश्वविघालय के शोधकर्ताओं ने 1,418 किडनी रोगियों पर अध्ययन किया। अध्ययन में शामिल रोगियों में हड्डियों को कमजोर करने वाला रोग 'हाईपरपाराथाइरायड' भी पाया गया था। रोगियों में पाराथाइरायड हॉरमोन स्तर को बढ़ाने के लिए विटामिन डी की खुराक दी गई। अध्ययन दल में शामिल ब्रायन केस्टेनबाउम ने कहा कि किडनी संबंधी बीमारियों के चपेट में आने वाले रोगियों पर दो वर्षों तक अध्ययन किया गया। रोगियों के दो समूहों में से एक को पाराथाइरायड हॉरमोन को नियंत्रित करने के लिए कोलेस्ट्रॉल दिया गया। विटामिन डी युक्त कोलेस्ट्रॉल का रोगियों पर सकारात्मक असर दिखा।

छोटा सा तिल,गुण हैं अनमोल

तिल शब्द का अर्थ ही है तेल या तरल वसा। तिल के बीजों में तेल का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। तेल के अतिरिक्त तिल कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन का भी अच्छा स्त्रोत हे। काले तिलों में तुलनात्मक रूप से प्रोटीन अधिक व कार्बोहाइड्रेट कम मात्रा में पाया जाता है। तिल का प्रयोग अल्प मूत्र, घाव भरने के लिए, चर्म रोगों में, कृमिनाशक के रूप में, संधिवात, केश वृद्धि के लिए। रक्तातिसार व कुपचन में लाभकारी होता है। तिल में कैल्शियम अधिक होने के कारण इसका प्रयोग दांतों के लिए लाभकारी होता है। प्रतिदिन 25 ग्राम तिल चबाकर खाने से दांत मजबूत होते हैं। इसके साथ ही मुंह में 5-10 मिनट तिल भरकर रखने से पायरिया भी ठीक होता है। तिल के सेवन से स्मरण शक्ति, ग्रहण शक्ति व बुद्धि का विकास होता है।

मसड़ों की बीमारी से हो सकता है कैंसर

दांतों और मसूढ़ों का स्वस्थ न होना किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या की आर इशारा करता है। एक अध्ययन में दावा किया गया है कि मसूड़ों की बीमारी कैंसर का जोखिम बढ़ने का संकेत हो सकती है। इंपीरियल कालेज लंदन के अनुसंधानकर्ताओं के दल ने पाया है कि मसूड़ों की बीमारी से ग्रस्त लोगों में फेफड़े, किडनी, खून और अग्नाशय का कैंसर होने की आशंका बढ़ती है। मसूड़ों की बीमारी से परेशान धूम्रपान करने और न करने वाले दोनों लोगों में कैंसर की आशंका अधिक होती है। लानसेट आन्कोलाजी जर्नल में प्रकाशित खबर के अनुसार मुख्य अनुसंधानकर्ता डा. डोमिनीक मिस्ज्यूड का कहना है कि मसूड़ों में लगातार तकलीफ बनी रहना रोक प्रतिरोधक क्षमता के कम होने और कमजोरी के बढ़ने का संकेत है। अध्ययन में अनुसंधानकर्ताओं के दल ने 50 हजार लोगों के स्वास्थ्य रिकार्ड की जांच में पाया कि जिन लोगों का मसूड़ों की बीमारी का इतिहास रहा है उन्हें कैंसर होने की संभावना 14 प्रतिशत अधिक होती है बनिस्पत उन लोगों के जिनका इतिहास मसूड़ों की बीमारी का नहीं रहा है। मसूड़ों की बीमारी से ग्रस्त लोगों में फेफड़ों के कैंसर के साथ यकृत कैंसर और अग्नाशय कैंसर की आशंका 50 प्रतिशत बढ़ती है तथा ल्यूकेमिया जैसा रक्त कैंसर होने की संभावना तीस प्रतिशत अधिक होती है। अध्ययन के अनुसार धूम्रपान न करने वाले लोगों में फेफड़ों के कैंसर की आशंका में तो कोई वृद्धि नहीं होती पर अन्य प्रकार का कैंसर होने का जोखिम थोड़ा बढ़ जाता है। मसूड़ों के लंबे समय तक रोगग्रस्त रहने से शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली में परिवर्तन आते हैं जिस कारण कैंसर के जोखिम में वृद्धि होती है।

मछली का तेल बनाता है बच्चों को चुस्त दुरूस्त

आप चाहते हैं कि आपका बच्चा परीक्षा में बेहतर करे, तो आप अपने बच्चों को रोज मछली के तेल का खुराक दीजिए। यह आपके बच्चों की मदद कर सकता है। जी हां, एक नये शोध में यह बात सामने आयी है मछली का तेल बच्चों को चुस्त बनाता है।

ब्रिटेन में अनुसंधानकर्ताओं ने एक अध्ययन में यह पाया है कि जो बच्चे नियमित रूप से मछली के तेल का खुराक लेते हैं वह परीक्षाओं में बेहतर कर सकते हैं। यह उनकी मानसिक क्षमता को भी बढ़ाता है। अनुसंधानकर्ताओं ने अपना अध्ययन ब्रिटेन के तीन हजार ऐसे बच्चों पर किया जो नियमित रूप से पिछले छह महीने से रोज मछली कैप्सूल ले रहे थे। ये बच्चे परीक्षा में भी आगे रहे हैं।

इस अनुसंधान की तुलना उन बच्चों से की गयी जो इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं थे। मछली तेल का खुराक लेने नहीं लेने वाले बच्चों की तुलना में इसका सेवन करने वाले बच्चे उनकी परीक्षाओं में पहले की अपेक्षा दो स्थान उपर चले गए। वैज्ञानिकों ने लेकिन इस प्रयोग को खारिज कर दिया है।

टाईम पास

आज का राशिफल

मेष चू चे चो ला ली लू ले लो आ

संतान की ओर से हर्ष के प्रसंग बनेंगे। समय को देखकर कार्य करना ज्यादा हितकर रहेगा। परिश्रम अधिक करना पड़ेगा तभी आप लाभ की आशा कर सकते ह। कार्य क्षेत्र में पदोन्नति के योग बनेंगे। आलस्य को त्याग। पुरुषार्थ का सहारा लें। व्यवसायिक अभ्युदय भी होगा और प्रसन्नताएं भी बढ़ेगी। शुभांक-3-6-9

वृष इ उ ए ओ वा वी वू वे वो

कर्म बल पर आपको सफलता मिलेगी। व्यवसायिक क्षेत्र में वर्तमान क्षमता को बढ़ायेगें। उपक्रम का विस्तार करने का प्रयास सफल होगा। अच्छी सफलताएं प्राप्त करेग। बुद्धि कौशल से चुनौतीपूर्ण कार्यों में सफलता मिलेगी। आर्थिक दृष्टि से समय उपलब्धिकारक रहेगा। भाई-बहनों का प्रेम बढ़ेगा। शुभांक-1-5-7

मिथुन का की कू घ ड छ के को हा

मानसिक एवं शारीरिक शिथिलता पैदा होगी। कामकाज सीमित तौर पर ही बन पाएंगे। स्वास्थ्य कमजोर बना रहेगा। कुछ आर्थिक संकोच पैदा हो सकते ह। महत्वपूर्ण कार्य को समय पर बना लें तो अच्छा ही होगा। श्रम अधिक करना पड सकता है। वरिष्ठजनों से मतभेद उभर सकते है। शुभांक-2-5-7

कर्क ही हू हे हो डा डी डू डे डो

शनै:-शनै: स्थिति पक्ष की बनने लगेगी। मेल-मिलाप से काम बनाने की कोशिश लाभ देगी। यात्रा का दूरगामी परिणाम मिल जाएगा। आशा और उत्साह के कारण सक्रियता बढ़ेगी। सुखद समय की अनुभूतियां प्रबल होगी। अभिभावकों के प्रति उत्तरदायित्व निभाने होंग। शुभांक-4-6-9

सिंह मा मी मू मे मो टा टी टू टे

विकास के लिए बनाई योजना सफल होगी। अच्छा हो कि आप अपने उद्देश्य को लेकर सचेत रहें। प्रियजनों से समागम का अवसर मिलेगा। कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य सौंपे जा सकते है जो कि अतिविश्वसनीय व्यक्तियों को ही दिये जाते हैं। कार्य सार्धक दिन है व्यर्थ न गंवाऐ। शुभांक-5-7-9

कन्या टो पा पी पू ष ण ठ पे पो

क्षमता से अधिक कार्य करने की नौबत आ सकती हैं। उत्तरदायित्व की अधिकता निजी जीवन में अपने ही ढंग की परेशानियां पैदा करेंगी। कारोबार की उन्नति के लिये एक से अधिक सीढ़ी चढ़कर लोंगो को आश्चर्य में डाल देंगे। बौद्धिक क्षेत्र में प्रतियोगिता जीतने का मौका मिलेगा। शुभांक-1-5-7

तुला रा री रु रे रो ता ती तू ते

सुबह-सुबह की महत्वपूर्ण सिद्धि के बाद दिन-भर उत्साह रहेगा। किसी लाभदायक कार्य के लिए व्ययकारक स्थितियां पैदा होंगी। अल्प-परिश्रम से ही लाभ होगा। कामकाज में आ रहा अवरोध दूर होकर प्रगति का रास्ता मिल जाएगा। घरेलू बहुमूल्य वस्तुओं के क्रय का योग है। शुभांक-4-5-7

वृश्चिक तो ना नी नू ने नो य यी यू

परामर्श व परिस्थिति सभी का सहयोग मिलेगा। अधिकारी वर्ग से आपकी निकटता बढ़ेगी। व्यावसायिक उपक्रम में उलटफेर की शुरूआत हो सकती हैं। स्थाई सम्पति के निर्माण, मरम्मत व पुर्नस्थापना पर व्यय भार बढ़ेगा। महत्वपूर्ण यात्राओं के संकेत हैं। चल-अचल सम्पति में वृद्धि होगी। शुभांक-3-5-7

धनु ये यो भा भी भू धा फा ढा भे

कार्य सार्धक दिन है व्यर्थ न गंवाऐ। विश्वस्त लोगों के कहे अनुसार चलें। राजकीय कार्यों में सतर्कता बरतें। मान-सम्मान को ठेस लग सकती है। जोश से कम व होश में रहकर कार्य करें। नये आगंतुकों से लाभ होगा। चल-अचल सम्पति में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में संतोषजनक सफलता मिलेगी। शुभांक-5-7-9

मकर भे जा जी खी खू खे खो गा गी

पुरानी पारिवारिक समस्याओं का समाधान होगा। परिश्रम प्रयास से काम बनाने की कोशिश लाभ देगी। व्यापार व व्यवसाय में ध्यान देने से सफलता मिलेगी। नौकरी में सावधानीपूर्वक कार्य करें। अपनों का सहयोग प्राप्त होगा। पत्नी व संतान पक्ष से थोड़ी चिंता रहेगी। शुभांक-2-5-7

कुंभ गू गे गो सा सी सू से सो दा

दाम्पत्य जीवन में तनाव का वातावरण बन सकता है। शारीरिक सुख के लिए व्यसनों का त्याग करें। आत्मचिंतन करें। पुराने मित्र से मिलन होगा। पठन-पाठन में स्थिति कमजोर रहेगी। खान-पान में सावधानी रखें। अपने अधीनस्थ लोगों से कम सहयोग मिलेगा। भ्रातृपक्ष में विरोध होने की संभावना है। शुभांक-6-8-9

मीन दी दू थ झ ञ दे दो चा ची

कहीं रुका हुआ पैसा वसूलने में मदद मिल जाएगी। व्यर्थ प्रपंच में समय नहीं गंवाकर अपने काम पर ध्यान दीजिए। अच्छे कार्य के लिए रास्ते बना लेंगे। अपने हित के काम सुबह-सबेरे निपटा लें। नियोजित कार्यक्रम सरलता से संपन्न हो जाएंगे। व्यापार व व्यवसाय में स्थिति उत्तम रहेगी। शुभांक-3-5-7

काकुरो पहेली -3811

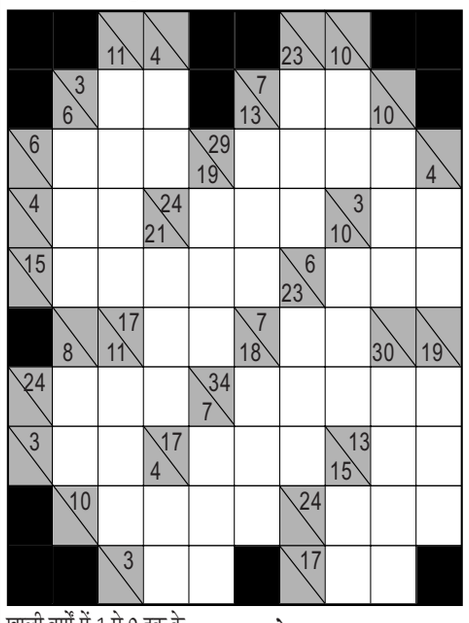

खाली वर्गों में 1 से 9 तक के अंक लिखकर नीचे से ऊपर व दाएं से बाएं की जोड़ हल्के रंग के आधे वर्ग की संख्या से मेल खानी चाहिए.किसी भी अंक का उस जोड़ में पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता.

उदाहरणतः

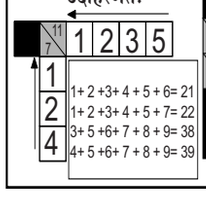

काकुरो - 3810 का हल

■	8	9	■	7	1	■	6	1
■	1	7	■	8	7	■	7	2
■	■	8	6	9	■	9	8	■
■	■	■	2	5	■	6	9	4
■	■	3	1	■	9	8	■	2
■	1	2	■	1	8	■	3	7
■	3	5	■	4	7	■	7	1
■	■	1	3	2	■	6	9	■
■	■	■	1	3	■	1	8	■

लॉफिंग ज़ोन

एक बार में थर्टी फर्स्ट की पार्टी मना रहे युवक-युवतियों का ध्यान अचानक बोर्ड पर गया, जिसमें लिखा था 'यहाँ देर रात तक नहीं चलेगी पार्टियाँ।'

उनमें से एक युवक ने घड़ी देखी और घबराया हुआ मेन गेट पर आकर झाँकने लगा।

तभी पास ही गश्त लगा रहे पुलिस वाले ने कहा- तुम्हारे पास अब सिर्फ चार ही मिनट बचे है। यहाँ से जल्दी भागो वर्ना अंदर कर दूँगा।

□ □ □

प्रेमिका से मिलने गया प्रेमी बोला- अभी तुमसे मिलने आते समय रास्ते में किसी ने मेरी जेब ही काट ली?

प्रेमिका- तो तुमने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की?

प्रेमी नहीं- ...जैसे ही मैंने कटी हुई जेब देखी, फौरन पास वाले दर्जी से सिलवा ली।

□ □ □

अपने दोस्तों के साथ ताश खेल रहा क्रोधित पति (पत्नी से)- युधिष्ठिर भी तो जुआ खेलते थे, फिर तुम मुझे क्यों रोकती हो?

पत्नी इतराकर बोली- कभी नहीं रोकूँगी! खूब खेलो जुआ, लेकिन इस बात को याद रखना की द्रौपदी के पाँच पति थे।

फिल्म वर्ग पहेली- 3811

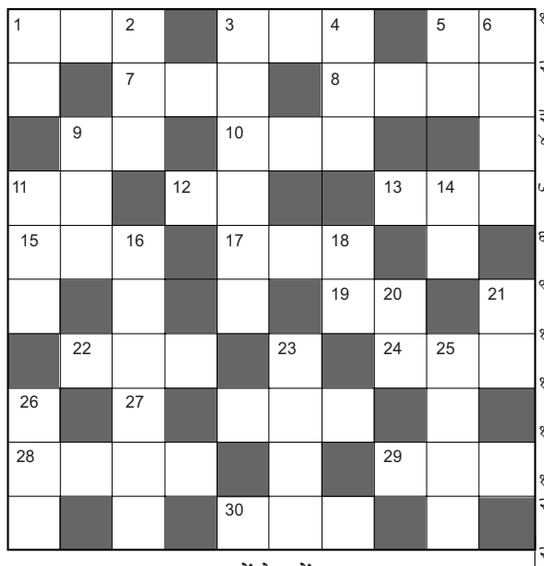

ऊपर से नीचे:-

१. 'कैसे कटे दिन कैसे' गीत वाली राजेश, गोविंदा, जूही की फिल्म-२
२. अमिताभ, जयाप्रदा की 'मंजिलें अपनी जगह हैं' गीत वाली फिल्म-३
३. फिल्म 'तेरे नाम' में नायक कौन था-४,२
४. ऋषि, चंकी, नीलम की 'देखा जो हुस्न आपका' गीत वाली फिल्म-३
५. काहे कोयल शोर, मचाये' गीत वाली राजकपूर, नर्गिस की फिल्म-२
६. जीतेंद्र, लीना चंदावरकार की 'तूने तूने ओ सनम' गीत वाली फिल्म-४
९. 'है मुबारक आज का' गीत वाली मिथुन चक्रवर्ती, रति की फिल्म-३
११. संजय दत्त, अनिता की 'तुन्ना तुन्ना तक तक तुन्ना' गीत वाली फिल्म-३
१४. 'हम तुम को निगाहो' गीत वाली सलमान, अरबाज, शिल्पा की फिल्म-२
१६. राजकपूर, वहीदा रहमान की 'सजन रे झूठ मत बोलो' गीत वाली फिल्म-३,३
१८. फिल्म 'मिस ४२०' में नायिका कौन थी-२
२०. सनी देओल, सलमान, करिश्मा, तब्बू की 'तू धरती पे चाहे जहाँ' गीत वाली फिल्म-२
२१. 'फूल ये कहाँ से' गीत वाली जैकी श्रॉफ, डिम्पल कपाड़िया की फिल्म-२
२३. अजय देवगन, अमीषा पटेल की 'प्यार तो होता है प्यार' गीत वाली फिल्म-४
२५. 'मेरे अंगने में तुम्हारा' गीत वाली अमिताभ, जीनत अमान की फिल्म-४
२६. अरविंद स्वामी, प्रभुदेवा, काजोल की 'एक बगिया में रहती है' गीत वाली फिल्म-३

बायें से दायें:-

१. 'ये तारा वो तारा' गीत वाली आशुतोष गोवारीकर की फिल्म-३
३. 'तुम्हें अपना बनाने की' गीत वाली संजयदत्त, पूजा भट्ट की फिल्म-३
५. राजकपूर, नर्गिस की 'ये शाम की तन्हाइयाँ' गीत वाली फिल्म-२
७. 'चलती है पुरवाई' गीत वाली जतिन ग्रेवाल, नेहा की फिल्म-३
८. ऋषिकपूर, जयाप्रदा की 'रामजी की निरली सवारी' गीत वाली फिल्म-४
९. 'मैं शायर तो नहीं' गीत वाली ऋषिकपूर, डिम्पल की फिल्म-२
१०. राजेश खन्ना, शर्मिला की 'कन्हैया कन्हैया तुझे' गीत वाली फिल्म-३
११. 'बंदा ये बिंदास है' गीत वाली अमिताभ, रवीना, नंदिता की फिल्म-२
१२. अमिताभ, जीनत की 'ये मेरा दिल यार का दीवाना' गीत वाली फिल्म-२
१३. 'दिन सारा गुजारा' गीत वाली शम्मी कपूर, सायरा की फिल्म-३
१५. राजेंद्रकुमार, वहीदा की 'ये मौसम भीगा भीगा है' गीत वाली फिल्म-४
१७. 'वो शाम कुछ अजीब थी' गीत वाली राजेश खन्ना, वहीदा की फिल्म-३
१९. आमिर, जूही, ममता की 'धीरे धीरे आप मेरे' गीत वाली फिल्म-२
२२. फिल्म 'रिफ्यूजी' में अभिषेक के साथ नायिका कौन थी-३
२४. अक्षयकुमार, करीना की 'दिल ले गया परदेसी' गीत वाली फिल्म-३
२७. 'बहारों फूल बरसाओ' गीत वाली राजेंद्रकुमार, वैजयंती की फिल्म-३
२८. किशोरकुमार की 'एक चतुर नार करके सिंगार' गीत वाली फिल्म-४
२९. 'फिर वही चांद वही गम' गीत वाली देवआनंद, नूतन की फिल्म-३
३०. डिनो, बिपाशा की 'जब दिल चुराये कोई' गीत वाली फिल्म-३

फिल्म वर्ग पहेली- 3810

श	हु	ल	■	ना	■	गै	ब	ल	र
जा	■	■	घा	य	ल	■	द	■	न
औ	ला	द	■	ब	गा	व	त	■	■
र	■	स	त्या	■	न	■	मी	ना	क्षी
रं	गी	ला	■	टी	■	अ	ज	य	■
क	■	ख	ल	ना	य	क	■	क	था
■	दो	■	की	■	■	ल	क्ष्य	■	ने
खू	ब	सू	र	त	■	मं	■	दा	दा
■	द	■	■	ला	■	द	स	■	र
डॉ	न	■	रे	श	नी	■	नी	तू	■

सूडोकु -3811

3	9			1	4			2
1	2		6		3		5	
		5		8	7			9
	7			6	9			8
2	1			5			4	6
4			3	2			9	
9			8	4		5		
	6		9		5		2	4
8			1	7			6	3

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु -3810 का हल

6	9	2	3	7	4	5	8	1
3	8	5	6	2	1	7	4	9
7	4	1	8	9	5	6	2	3
2	3	9	5	4	6	8	1	7
1	7	4	9	8	3	2	6	5
5	6	8	7	1	2	9	3	4
4	5	7	1	6	8	3	9	2
8	2	3	4	5	9	1	7	6
9	1	6	2	3	7	4	5	8

शब्द पहेली - 3811

बाएँ से दाएँ

1. ईश्वर,करतार-3
3. मुस्कुराहट-3
5. ईख-2
6. रजनीगंधा -2,1,2
9. समुद्र तट (अंग्रेजी-2)
11. ताकत,दम-2
12. अमिताभ व किमी काटकर की फिल्म-2
13. वेतन,पगार-3
16. मनोनीत,नामकृत-3
18. बंधक,गिरवी वस्तु-3
20. निशा,रात्री-3
22. वचन,प्रतिज्ञा-3
23. श्रीनगर की झील-2
24. मूल्य,कीमत-2
25. असावधान-3
28. धिक्कार,फटकार-3
30. हवा,पवन-3
31. झाझर,कुंभ-3
33. चिंतन-3
35. संस्कृत में मेरा-2
36. मादा का विलोम-2
38. कुबेर,भूत-2
40. परोपकारी,जितेंद्र की एक फिल्म-5
41. फलों का राजा-2
42. फूल चुननेवाली-3
43. घोड़ों की देखभाल करनेवाला-3

ऊपर से नीचे

1. तमिल भाषा में बड़ा भाई-2
2. बेकार-3
3. दीवान,खजांची-3
4. पैगंबर,रसूल-2
5. झूठ,मिथ्या -3
7. तेल में पकाना-3
8. आराम,मदद-3
10. गुलिस्ता-3
14. नरकभोगी-5
15. खुजली-2
17. सखा,दोस्त-2
18. मजा,आनंद-2
19. स्वदेशवासी-5
21. सुई (अंग्रेजी-3)
22. विष्णुप्रिया-3
26. पुनः,वापस-2
27. मर्करी,पारद-2
29. भीगा हुआ-2
30. वक्त,टाईम-3
31. अच्छी बुद्धि-3
32. निम्नता-3
34. मुलायम-3
35. बड़ा,विशाल-3
37. धनवान-3
39. माफी-2
41. उम्मीद-2

शब्द पहेली -3810 का हल

का	■	बु	आ	■	द	■	स	ख्त	■	मु
र	क्त	■	कु	क	र	मु	त्ता	■	जा	ला
तू	■	म	ल	■	मि	■	धी	र	■	य
स	क्रि	य	ता	■	या	■	श	ब	न	म
■	या	■	■	■	न	■	■	■	या	■
रा	शी	क	र	ण	■	भा	र	ही	न	ता
■	ल	■	■	■	टी	■	■	■	वे	■
ती	ता	प	न	■	ना	■	न	ह	ला	ना
इं	■	स	जा	■	मु	■	का	म	■	का
ब	लि	■	क	हा	नी	का	र	■	छ	वि
सं	■	गी	त	■	म	■	ना	नी	■	ल

बेंगलुरु में खुला अमेज़न का एशिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑफिस

12 मंजिला, 11 लाख वर्ग फुट का आधुनिक परिसर, एक साथ 7,000 कर्मचारी काम करेंगे

बेंगलुरु। अमेरिकी ई-कॉमर्स दिग्गज एमेजान ने बेंगलुरु में अपना एशिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑफिस खोलने की घोषणा की। नया परिसर 12 मंजिला और 11 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ है। यह केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से मात्र 15 किलोमीटर दूर स्थित है और इसमें भारत में 7,000 से अधिक कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल और सहयोगी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। अमेज़न ने भारत में अब तक 40 अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया है और 2030 तक अतिरिक्त 35 अरब डॉलर निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। कर्नाटक के लघु एवं मध्यम उद्योग एवं अवसंरचना विकास मंत्री एम.बी. पाटिल ने उद्घाटन के दौरान कहा कि इस निवेश से उच्च गुणवत्ता वाली नौकरियां पैदा होंगी, स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत होगा और भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को समर्थन मिलेगा। नए परिसर को टीम सहयोग, लचीलापन, सीखने और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कर्मचारियों के लिए बास्केटबॉल और पिकलबॉल कोर्ट, एम्फीथिएटर, हरे-भरे लॉन और सामुदायिक बाहरी क्षेत्र जैसी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। कैफेटेरिया दो मंजिलों पर फैला है और इसमें वैश्विक व्यंजनों की विस्तृत श्रृंखला परोसी जाती है। इस परियोजना में जिम्मेदार सामग्री स्रोत, कार्यालय संपत्तियों का पुनः उपयोग और उच्च दक्षता वाली प्रणालियाँ शामिल हैं, जिनका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। यह पहल अमेज़न की दीर्घकालिक सतत विकास रणनीति का हिस्सा है। अमेज़न इंडिया के एक अधिकारी के अनुसार, बेंगलुरु लंबे समय से कंपनी की तकनीकी और व्यावसायिक टीमों का घर रहा है और आज भी यह नवाचार और प्रतिभा का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। नया ऑफिस कंपनी के भारत में निरंतर निवेश और विस्तार का प्रतीक है।

ऐपल ने भारत में पीएलआई योजना के तहत 2.5 लाख से अधिक नौकरियां दी

नौकरियों में 70 प्रतिशत से अधिक 19-24 वर्ष की महिलाएं शामिल

नई दिल्ली ।

क्यूपर्टिनो मुख्यालय वाली एप्पल इंक ने पिछले पांच वर्षों में भारत में 2,50,000 से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा की हैं। यह तेजी से बढ़ती संख्या मोबाइल-फोन विनिर्माण के लिए 2021 में शुरू हुई उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के कारण संभव हुई। खास बात यह है कि इन नौकरियों में 70 प्रतिशत से अधिक महिलाएं शामिल हैं, जिनमें कई की उम्र 19-24 वर्ष है और यह उनका पहला रोजगार अवसर है। आईफोन के दो मुख्य वेंडर, टाटा समूह और फॉक्सकॉन ने मिलकर लगभग 1,40,000 प्रत्यक्ष नौकरियां प्रदान की हैं, जो योजना के तहत प्रतिज्ञात 1,18,290 नौकरियों से अधिक है।

इसके अतिरिक्त 1,10,000 नौकरियां अन्य भारतीय, विदेशी और संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा दी गई हैं, जो मुख्य रूप से एमएसएमई क्षेत्र से जुड़ी हैं और आईफोन से संबंधित उपकरणों का उत्पादन करती हैं। इन कंपनियों का नेटवर्क भारत के उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, झारखंड, तमिलनाडु और कर्नाटक तक फैला हुआ है। ये कंपनियां मुख्य रूप से आईफोन असेंबली प्लांट को उपकरण और पुर्जे उपलब्ध कराती हैं, जबकि कुछ कंपनियां जैसे जाबिल और एक्सेस सीधे ऐपल की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में योगदान देती हैं। टाटा समूह के तीन आईफोन प्लांट लगभग 72,000 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, वहीं फॉक्सकॉन के दो कारखानों में 70,000 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। पीएलआई योजना के प्रभाव से मोबाइल निर्माण में औसत मासिक वेतन 11,000 से बढ़कर 18,000-20,000 रुपए हो गया। अकेले ऐपल और इसके सहयोगी नेटवर्क में अनुमानित 7,50,000 अप्रत्यक्ष नौकरियां उत्पन्न हुई हैं। भारत का स्मार्टफोन निर्यात 2025 में 30 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें आईफोन की हिस्सेदारी 23 अरब डॉलर रही।

एनएमपी 2.0 का 16.72 लाख करोड़ मुद्रीकरण जुटाने का लक्ष्य

- योजना के तहत 2,000 से अधिक संपत्तियों में निजी भागीदारी लाई जाएगी

नई दिल्ली ।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी 2.0) के दूसरे चरण का अनावरण करते हुए वित्त वर्ष 2026 से 2030 के बीच 16.72 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य घोषित किया। इस योजना का उद्देश्य केंद्र सरकार के मंत्रालयों और सार्वजनिक उपक्रमों की उत्पादक संपत्तियों के मुद्रीकरण के माध्यम से पूंजी जुटाना है। सरकार का कहना है कि इससे नई अवसंरचना परियोजनाओं और पूंजीगत व्यय के लिए संसाधन उपलब्ध होंगे, बिना राजकोषीय बोझ बढ़ाए।

नीति आयोग के एक वे रिष्ठ अधिकारी के अनुसार एनएमपी 2.0 में राजमार्ग, बिजली, बंदरगाह और रेलवे जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। योजना के तहत 2,000 से अधिक संपत्तियों में निजी भागीदारी लाई जाएगी। कुल लक्ष्य का एक-चौथाई से अधिक हिस्सा राजमार्ग क्षेत्र से आने की उम्मीद है, जबकि बंदरगाह, कोयला और खनिज क्षेत्रों से भी महत्वपूर्ण योगदान संभावित है। इस चरण में पहली बार पांच वर्षों के दौरान 5.8 लाख करोड़ रुपये के निजी निवेश का अनुमान जोड़ा गया है। वित्त वर्ष 2026 में 2.49 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया है, हालांकि वास्तविक प्राप्ति करीब 2 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

योजना में अस्थायी संपत्ति हस्तांतरण, सूचीबद्ध कंपनियों में हिस्सेदारी का विनिवेश और नकद प्रवाह का प्रतिभूतिकरण जैसे उपाय शामिल हैं। रेलवे को 2.62 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें सात सूचीबद्ध रेलवे पीएसयू में सरकारी हिस्सेदारी घटाकर 83,700 करोड़ रुपये जुटाने का प्रावधान है। सरकार को उम्मीद है कि एनएमपी 2.0 से बुनियादी ढांचे के विकास को नई गति मिलेगी।

पीएम सूर्य घर योजना 30 लाख घरों में रूफटॉप सौर इकाई स्थापित

नई दिल्ली ।

केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत फरवरी 2024 से अब तक देशभर में 30 लाख से अधिक घरों की छतों पर सौर ऊर्जा इकाई लगाई जा चुकी है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने यह जानकारी दी।

जोशी ने बताया कि जब एक करोड़ घरों में रूफटॉप सौर संयंत्र स्थापित हो जाएंगे, तो अनुमानित 1,000 अरब यूनिट नवीकरणीय बिजली का उत्पादन संभव होगा। इन इकाइयों के 25 साल के जीवनकाल में लगभग 72 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आने का अनुमान है। मंत्री ने कहा कि यह योजना घरेलू बिजली बिल कम करने के साथ-साथ देश की ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हरित परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। केंद्र सरकार का लक्ष्य 2026-27 तक देशभर में 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सौर इकाई स्थापित करना है, जिससे टिकाऊ ऊर्जा और

पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।

बायजूज़ अरबों डॉलर के वैल्यूएशन से कानूनी और वित्तीय संकट तक

- ऑनलाइन शिक्षा की मांग में गिरावट और बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा से हुओ नुकसान

नई दिल्ली ।

भारत की प्रमुख एड-टेक कंपनी बायजूज़ कभी 22 अरब डॉलर (लगभग 1.98 लाख करोड़ रुपये) के वैल्यूएशन तक पहुंची थी। कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन शिक्षा की बढ़ती मांग ने कंपनी को तेजी से बढ़ने का अवसर दिया। बायजूज़ ने वैश्विक विस्तार, बड़े अधिग्रहण और ब्रांडिंग में भारी निवेश किया। महामारी के बाद फंडिंग सस्ती नहीं रही और निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ। ऑनलाइन शिक्षा की मांग में गिरावट और बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने कंपनी की आय को प्रभावित किया। नवंबर 2021 में लिया गया 1.2 अरब डॉलर का टर्म लोन बायजूज़ के लिए चुनौती बन गया। तिमाही ब्याज भुगतान (330 करोड़ रुपए) में चूक के बाद विदेशी लेंडर्स ने अमेरिका में मुकदमा दायर किया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत कंपनी के दफ्तरों पर छापे मारे और लगभग 9,362 करोड़ रुपए के कथित उल्लंघन का नोटिस जारी किया। इसके अलावा बायजूज़ और लेंडर्स के बीच समय से पहले भुगतान और कानूनी कार्रवाई को लेकर भी विवाद चल रहा है। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि 533 मिलियन डॉलर का फंड गायब है, जिससे कंपनी पर विवाद और बढ़ गया है। महामारी के समय में किए गए आक्रामक विस्तार और निवेश की रणनीति अब बायजूज़ के लिए बोझ साबित हो रही है।

रुपया गिरावट के साथ बंद

मुंबई ।

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया मंगलवार को 4 पैसे कि गिरावट के साथ ही 90.93 पर बंद हुआ आज सुबह कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और अमेरिकी डॉलर के मजबूत रुख से रुपया शुरुआती कारोबार में सात पैसे नीचे आकर 90.96 पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार घरेलू शेयर बाजारों की खराब शुरुआत से स्थानीय मुद्रा पर और दबाव डाला, हालांकि विदेशी निवेशकों के निवेश ने इसे सहारा दिया एवं तेज गिरावट को रोक दिया। वहीं अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.91 पर खुला। फिर टूटकर 90.96 प्रति डॉलर पर आ गया जो पिछले बंद भाव से सात पैसे की गिरावट दिखाता है। रुपया सोमवार को पांच पैसे की बढ़त के साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.89 पर बंद हुआ था। इस बीच छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दिखाने वाला डॉलर सूचकांक 0.11 फीसदी की बढ़त के साथ 97.81 पर रहा।

चांदी दो दिन में 16 हजार महंगी, कीमत 2.67 लाख/किलो

सोना 5 हजार बढ़ा, 10 ग्राम 1.60 लाख का हुआ

नई दिल्ली। सोने-चांदी के दाम में मंगलवार, 24 फरवरी को तेजी रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (इब्जा) के अनुसार, 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1,283 रुपए बढ़कर 1,59,503 रुपए पहुंच गया है। इससे पहले यह 1,58,220 रुपए पर था। सोना 2 कारोबारी दिनों में 5 हजार महंगा हुआ है। वहीं, एक किलो चांदी की कीमत 2,460 रुपए बढ़कर 2,66,535 रुपए पर पहुंच गई है। इससे पहले इसकी कीमत 2,64,075 रुपए किलो थी। इससे पहले भी चांदी 13 हजार रुपए महंगी हुई थी। यानी दो दिन में ये 16 हजार से ज्यादा बढ़ चुकी है। इस साल सोने-चांदी की कीमत में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सोना 2026 में अब तक 26,000 रुपए और चांदी 36,000 रुपए महंगी हो चुकी है। इस दौरान 29 जनवरी को सोने ने 1.76 लाख रुपए और चांदी ने 3.86 लाख रुपए का ऑल टाइम हाई भी बनाया था। 2025 में सोना 57 हजार (75 प्रतिशत) बढ़ा है। 31 दिसंबर 2024 को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 76 हजार का था, जो 31 दिसंबर 2025 को 1.33 लाख रुपए हो गया। चांदी इस दौरान 1.44 लाख (167 प्रतिशत) बढ़ी। 31 दिसंबर 2024 को एक किलो चांदी 86 हजार की थी, जो साल के आखिरी दिन 2.30 लाख प्रति किलो हो गई।

मोक्सी पावर ने तमिलनाडु में 558 मेगावाट बिजली आपूर्ति का ठेका हासिल किया

- बिजली आपूर्ति 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगी

नई दिल्ली । अदाणी पावर की सहायक कंपनी मोक्सी पावर को ते मिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन से पांच वर्षों के लिए 558 मेगावाट बिजली आपूर्ति का ठेका मिला है। कंपनी ने बोली में 5.910 रुपये प्रति यूनिट का सबसे प्रतिस्पर्धी शुल्क प्रस्तावित कर ठेका जीता। यह आपूर्ति 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगी। मोक्सी पावर तमिलनाडु के तूतीकोरिन में 1,200 मेगावाट क्षमता का संयंत्र संचालित करता है। अदाणी पावर भारत की सबसे बड़ी निजी बिजली उत्पादक कंपनी है, जिसकी कुल उत्पादन क्षमता 18.15 गीगावाट है। संयंत्र की दोनों इकाइयों के पास बिजली आपूर्ति समझौते हैं, जिससे संचालन और राजस्व में स्थिरता बनी रहती है। अदाणी पावर की परिचालन क्षमता का 95 फीसदी से अधिक हिस्सा मध्यम से दीर्घकालिक अनुबंधों के तहत सुरक्षित है। कंपनी का लक्ष्य अगले वर्ष तक सभी परिचालित और जल्द चालू होने वाले संयंत्रों के लिए लगभग 100 फीसदी पीपीए हासिल करना है। यह रणनीति अल्पकालिक बाजार अस्थिरता के जोखिम को कम करती है और दीर्घकालिक राजस्व की स्पष्टता प्रदान करती है। इस ठेके से तमिलनाडु के उपभोक्ताओं को विश्वसनीय और उच्च गुणवत्ता वाली बिजली उपलब्ध होगी। ग्रिड की स्थिरता मजबूत होगी और घरों, उद्योगों एवं व्यवसायों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी। प्रतिस्पर्धी शुल्क पर बिजली उपलब्ध होने से उपभोक्ताओं को किफायती और भरोसेमंद ऊर्जा का लाभ मिलेगा।

बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार; सेंसेक्स 1068 अंक टूटा, निफ्टी 25500 के नीचे

छह लाख करोड़ से अधिक का नुकसान

नई दिल्ली।

भारतीय बाजार मंगलवार को बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ। बेंचमार्क सेंसेक्स और निफ्टी में एक प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखने को मिली। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 1068.74 अंक या 1.28 प्रतिशत गिरकर 82,225.92 पर बंद हुआ। 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 288.35 अंक या 1.12 प्रतिशत गिरकर 25,424.65 पर बंद हुआ। शेयर बाजार में बिकवाली का दबाव व्यापक रहा, जिसमें मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांक में करीब 1 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई। तेज गिरावट के बीच निवेशकों की संपत्ति में भारी कमी आई। इससे निवेशकों को एक ही दिन में छह लाख करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ।

एआई के संभावित प्रभाव के कारण तकनीकी शेयरों में कमजोरी का रुझान जारी है। भारतीय आईटी कंपनियों के एडीआर में कमजोरी यह संकेत देती है कि यह सेगमेंट दबाव में बना रहेगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का आज बाद में होने वाला स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन और उसमें दिया जाने वाला संदेश वैश्विक बाजारों द्वारा उत्सुकता से देखा जाएगा।

इन कारणों से दिखी गिरावट

वैश्विक व्यापार और भू-राजनीतिक घटनाक्रमों को लेकर अनिश्चितता के बीच निवेशकों का मनोबल कमजोर बना रहा। यह कमजोरी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा 10-15 प्रतिशत वैश्विक टैरिफ ढांचे की घोषणा के बाद टैरिफ संबंधी चिंताओं के फिर से उभरने से उत्पन्न हुई है, जिससे वैश्विक आर्थिक विकास और कंपनियों की आय पर इसके संभावित प्रभाव को लेकर आशंकाएं बढ़ गई हैं।

भारत जर्मनी और कनाडा के साथ खनिज सहयोग समझौतों को दे सकता है मंजूरी

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिमंडल बैठक में भारत अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत करने के लिए जर्मनी और कनाडा के साथ महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में संयुक्त आशय घोषणा को मंजूरी देने पर विचार कर रहा है। जर्मनी के साथ प्रस्तावित समझौते का मुख्य फोकस संयुक्त अन्वेषण, सतत खनन, आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण होगा। यह भारत को लिथियम, कोबाल्ट, निकल और अन्य दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद करेगा। भारत और कनाडा के बीच भी इसी तरह का समझौता प्रस्तावित है। इससे ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा बदलाव के लिए आवश्यक संसाधनों में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। यह कदम महत्वपूर्ण खनिज मिशन और *खनन एवं खनिज (विकास व विनियमन) संशोधन अधिनियम के तहत हाल की नीलामी के अनुरूप है।

आरबीआई ने जारी किया सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के प्रीमैच्योर रिडेम्पशन कैलेंडर

अगले 6 महीने में 33 सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स भुना सकेंगे निवेशक

मुंबई । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 23 फरवरी 2026 को सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (एसजीबी) के समय से पहले रिडेम्पशन के लिए कैलेंडर जारी किया। यह सुविधा उन बॉन्ड पर लागू होगी जिनकी रिडेम्पशन तारीख 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 के बीच है। निवेशक 22 अक्टूबर 2021 के दिशानिर्देशों के अनुसार, जारी होने की तारीख से 5 साल पूरे होने पर एसजीबी समय से पहले भुना सकते हैं। आरबीआई के शेड्यूल के अनुसार 2018-19 से 2021-22 तक जारी 33 ट्रांच इस छह महीने की अवधि में प्रीमैच्योर रिडेम्पशन के लिए पात्र हैं। सबसे पहला ट्रांच 2018-19 सीरीज-2 है, जो 23 अप्रैल 2026 से भुनाई के लिए खुला रहेगा। आवेदन विंडो 23 मार्च से 13 अप्रैल 2026 तक रहेगी। आखिरी पात्र ट्रांच 2019-20 सीरी-10 है, जिसकी रिडेम्पशन 11 सितंबर 2026 होगी और आवेदन 11 अगस्त से 1 सितंबर 2026 तक होगा। निवेशक आरबीआई के अधिकृत कार्यालयों, डिपॉजिटरी या आरबीआई रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आरबीआई ने कहा है कि अप्रत्याशित अवकाश पर तारीखों में बदलाव हो सकता है। निवेशकों को अपनी ट्रांच की सटीक आवेदन अवधि पर ध्यान देना जरूरी है।

ईपीएफओ निष्क्रिय खातों में फंसे 30.52 करोड़ जल्द लौटाएगी

- 31.86 लाख निष्क्रिय खातों को बंद करने की बड़ी योजना

नई दिल्ली ।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने 7.11 लाख निष्क्रिय खातों में फंसे 30.52 करोड़ रुपये जल्द खाताधारकों या उनके कानूनी वारिसों को लौटाने का फैसला किया है। यह पहल 31.86 लाख निष्क्रिय खातों को बंद करने की बड़ी योजना का हिस्सा है। मंत्रालय के अनुसार, इनमें कुछ खाते 20 साल से पुराने हैं और पिछले तीन साल से इनमें कोई लेनदेन नहीं हुआ है। श्रम मंत्रालय ने इस योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसमें ऐसे खातों को चुना गया है जिनमें 0 से 1,000 रुपये तक की राशि है और जो आधार से जुड़े हैं। ईपीएफओ सीधे इन खातों में पैसे ट्रांसफर करेगा। पायलट प्रोजेक्ट सफल होने पर बाकी निष्क्रिय खातों में भी इसी तरह राशि लौटाई जाएगी। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पीएफ एक अनिवार्य सरकारी योजना है। इसमें कर्मचारी अपने मूल वेतन का 12 फीसदी योगदान करते हैं, जबकि नियोक्ता भी उतना ही योगदान करता है। यदि किसी खाते में तीन साल तक कोई लेनदेन नहीं होता तो उसे निष्क्रिय घोषित किया जाता है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ईपीएफओ सदस्य अपना पैसा आसानी से निकाल सकें। हालांकि, छोटे-छोटे निष्क्रिय खातों में फंसी राशि प्रशासनिक

जिम्मेदारियों और वित्तीय जवाबदेही में चुनौती पैदा करती है। हजारों करोड़ रुपये ऐसे निष्क्रिय खातों में फंसे हुए हैं क्योंकि लोग कम राशि निकालने के लिए आने-जाने की झंझट से बचते हैं। पायलट प्रोजेक्ट के सफल होने पर, ईपीएफओ धीरे-धीरे बाकी निष्क्रिय खातों में भी यह प्रक्रिया लागू करेगा। इससे खाताधारकों का पैसा सुरक्षित तरीके से लौटाया जाएगा और निष्क्रिय खातों का बोझ भी कम होगा।

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन 1,500 एक्सपर्ट्स की करेगा नियुक्ति

- लगभग 40 फीसदी पद संविदा या लचीले आधार पर होंगे

नई दिल्ली । केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) अब केवल कारखानों के निरीक्षण तक सीमित नहीं रहेगा। संगठन ने 1,500 वैज्ञानिक और विशेषज्ञों को नियुक्त करने की योजना बनाई है। ये विशेषज्ञ क्लिनिकल रिसर्च, बायोलॉजिक्स, सांख्यिकी, इंजीनियरिंग और नियामकीय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में काम करेंगे। इनमें से लगभग 40 फीसदी पद संविदा या लचीले आधार पर होंगे। इस कदम का उद्देश्य दवा मंजूरी और निगरानी प्रक्रिया को वैज्ञानिक, तेज़ और प्रभावी बनाना है। सीडीएससीओ ने जोखिम-आधारित निरीक्षण प्रक्रिया को तेज कर दिया है। निरीक्षण में उत्पाद की जोखिम स्थिति, पिछली अनुपालन स्थिति और खुफिया सूचनाओं को ध्यान में रखा जाता है। 2022 के अंत से अब तक 1,250 विनिर्माण इकाइयों का ऑडिट किया जा चुका है। स्टाफ की कमी के कारण अब निरीक्षण में अधिसूचित थर्ड-पार्टी एजेंसियों को शामिल किया जाएगा। इससे निगरानी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगी। कफ सिरप निर्माण क्षेत्र बार-बार गुणवत्ता समस्याओं का केंद्र रहा है। देश में 1,300 कफ सिरप निर्माता हैं, जिनमें से लगभग 1,100 इकाइयों का निरीक्षण हो चुका है। गंभीर कमियों वाली इकाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और कुछ को बंद करने का निर्णय लिया गया।

अभिषेक, तिलक और रिंकू पर लटक रही तलवार

अहमदाबाद (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट टीम के सहायक कोच टेन डोइशे और सितांशु का कहना है सुपर-8 के अगले मैचों के लिए टीम की फिर से समीक्षा करते हुए बदलाव किये जायगे। ऐसे में तय है कि अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और रिंकू सिंह की जगह खतरे में हैं। इन तीनो में से किसी एक का बाहर जाना तय है। ये तीनो ही अब तक इस टूर्नामेंट में असफल रहे हैं। इसके अलावा टीम प्रबंधन शीर्ष क्रम में अधिक बाएं हाथ के बल्लेबाजों को उतारे जाने की रणनीति पर भी फिर विचार करेगा। दक्षिण अफ्रीका से पहले ही मुकाबले में भारतीय टीम की हार के बाद से ही उसके लिए अब बचे हुए दोनो मैच बड़े अंतर से जीतना जरुरी है। इसलिए फार्म से बाहर चल रहे खिलाड़ियों को बनाये रखने का खतरा नहीं उठाया जा सकता है। अभिषेक अब तक चार मैचों में 15 रन जबकि तिलक वर्मा पांच मैचों में 107 रन ही बना पाये हैं। इसके अलावा रिंकू भी फिनिशर की भूमिका में विफल रहे हैं। वह 29 गेंदों में 82.75 की स्ट्राइक रेट से केवल 24 रन ही बना पाये हैं।

कोटक ने कहा, अगर मुख्य कोच और टीम प्रबंधन को लगता है कि हमें कुछ बदलाव करने हैं तो हम करेंगे। अब इस पर विचार हो रहा है कि अगर हमें बदलाव करना है तो वह क्या होगा और कैसे होगा। अब हम ऐसे स्थान पर पहुंच गए हैं कि हमें कुछ भी बादलाव करते समय कई बातों का ध्यान रखना होगा। वहीं डोइशे ने माना है कि टीम में बैकअप में विशेषज्ञ बल्लेबाजों की की है। उन्होंने कहा, या तो आप उन्हीं खिलाड़ियों को चुनते हैं जो आपको लगता है कि पिछले डेढ साल में अच्छा खेल रहे हैं, भले ही अभी रन नहीं बना पा रहे हैं। या फिर बदलाव करके संजू सैमसन को लाते हैं जो शानदार खिलाड़ी है और उनके आने से शीर्षक्रम में दायें और बाएं का संयोजन लाभकारी रहेगा। उन्होंने कहा, अगले दो अहम मैचों से पहले सैमसन को शामिल करने के बारे में विचार होगा। साथ ही कहा कि अभिषेक और तिलक का फॉर्म चिंता का विषय है। उन्होंने कहा, ये दोनो ही अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाये हैं। वहीं अभिषेक को सलाह दिये जाने को लेकर कोटक ने कहा, बल्लेबाजी कोच होने के कारण मेरा मानना है कि उसे जरूरत से ज्यादा सलाह देने की जरुरत नहीं है। उसके दिमाग को ठीक से काम करने दें। लगातार सलाह से मानसिक दबाव पड़ता है जिससे बल्लेबाज का मनोबल गिरता है। उसे अपने अनुसार खेलने देना ही बेहतर रहेगा

आईपीएल की तरह बदलाव वाली नीति विश्वकप में नहीं चलती : अश्विन

नई दिल्ली । भारतीय टीम के पूर्व स्पिनर आर अश्विन ने टीम प्रबंधन की रणनीति पर सवाल उठाये हैं। अश्विन के अनुसार टी20 विश्वकप जीतने के लिए टीम प्रबंधन को आईपीएल वाली बदलाव की सोच से बाहर आना होगा। अश्विन ने कहा कि प्रबंधन ने जिस प्रकार दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उपकप्तान अक्षर पटेल को बाहर बिठाया वह समझ से परे हैं। साथ ही कहा कि ये सब आईपीएल में चलता पर विश्वकप में नहीं। अश्विन ने कहा कि इस प्रकार के बदलाव आईपील में इसलिए चलते हैं क्योंकि टीम को 14 गेम खेलने होते हैं पर आईसीसी टूर्नामेंट में बदलाव कम से कम होने चाहिये और जितना आज टीम को स्थर रखते हैं उतना ही लाभ होता है। अश्विन ने साथ ही कहा, आपको नहीं भूलना चाहिए कि अक्षर ने पिछले विश्व कप में किस प्रकार का प्रदर्शन किय था।

टी20 विश्व कप के सुपर-8 में न्यूजीलैंड के खिलाफ हर हाल में जीत दर्ज करने उतरेगी श्रीलंका

कोलंबो (एजेंसी)। मेजबान श्रीलंकाई टीम बुधवार को अपने दूसरे सुपर-8 मैच में बुधवार को न्यूजीलैंड का मुकाबला करेगी। श्रीलंकाई टीम को अपने पहले ही मुकाबले में इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में अब अगर वह न्यूजीलैंड से हारती है तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। मेजबान श्रीलंकाई टीम के बल्लेबाज अपने पहले मैच में असफल रहे थे, ऐसे में उसे अगर कीवी टीम से जीतना है तो स्पिनरों के खिलाफ अपने प्रदर्शन को सुधारना होगा। इंग्लैंड के खिलाफ श्रीलंकाई 147 रनों का लक्ष्य भी हासिल नहीं कर पाए थे। श्रीलंका की पिचें बल्लेबाजी के लिए कठिन मानी जाती हैं। इसके अलावा इन मैदानों पर बड़े शॉट खेलना भी कठिन होता है।

सुपर आठ के पहले मैच में श्रीलंका के बल्लेबाज गलत शॉट खेलकर अपना विकेट गंवाते दिखे थे और उसकी टीम को अपनी इन गलतियों से सबक लेना होगा। बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौड़ ने टीम के खराब प्रदर्शन पर कहा, 'यह एक टी20 मैच है, इसलिए जाहिर है कि आप अधिक से अधिक रन बनाने की कोशिश करते हैं पर जब गेंद बल्ले पर ठीक से नहीं आ रही होती है, तो कहना आसान है पर रन बनान कठिन है।'

पथुम निसांका ने बल्लेबाजी में शानदार प्रदर्शन किया है जबकि बाएं हाथ के स्पिनर दुनिथ वेलालेज ने भी अच्छी गेंदबाजी की है। वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मुकाबला बारिश से नहीं हो पाया था। जिससे दोनो को ही एक-एक अंक मिला है। कीवी टीम के पास भी कप्तान मिचेल सेंटनर सहित अच्छे स्पिनर हैं जो श्रीलंका के बल्लेबाजों की परीक्षा लेंगे।

दोनों टीम सुपर आठ में पहली जीत के लिए पूरी ताकत लगा देंगी। न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज फिन एलन और टिम सीफर्ट की जोड़ी ने लीग चरण के दौरान जबरदस्त बल्लेबाजी की है। इसके अलावा रचिन रविंद्र भी कनाडा के खिलाफ अर्धशतक लगाकर फॉर्म में आ गये हैं। ऐसे में श्रीलंकाई गेंदबाजों के लिए कीवी बल्लेबाजों पर अंकुश लगाना आसान नहीं रहेगा।

दोनो ही टीमें इस प्रकार हैं

श्रीलंका: दासुन शनाका (कप्तान), पथुम निसांका, कामिल मिशारा, कुसल मेंडिस, कामिंडु मेंडिस, कुसल जेनिथ परेरा, चैरिथ असलांका, जेनिथ लियानागे, पवन रथनायके, वानिंदु हसरंगा, दुनिथ वेललागे, महीश थीक्षाना, दुशमंथा चमीरा, मथीशा पथिराना, ईशान मलिंगा।

न्यूजीलैंड: मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे,

जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, डैरिल मिशेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, टिम सीफर्ट, इश सोढ़ी, कोल मैकॉन्ची।

तिलक अंतिम ग्यारह में शामिल करने के लायक नहीं : श्रीकांत

-सैमसन को मिले अवसर

चेन्नई (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कृष्णामाचारी श्रीकांत ने कहा है कि तिलक वर्मा अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर रहे। इसलिए अंतिम ग्यारह में उनकी जगह नहीं बनती है। श्रीकांत के अनुसार अभी के समय में तिलक को टीम में रखना फायदेमंद नहीं है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच में भी वह केवल एक रन बनाकर पेवेलियन लौट गये। इससे अन्य बल्लेबाजों पर दबाव आ गया था। उन्हें ऐसे समय पर अच्छी बल्लेबाजी करनी चाहिये थी। , क्योंकि ईशान किशन बिना खाता खोले आउट हो गए थे।

अब तक विश्वकप के पांच मैचों में तिलक 118.88 के स्ट्राइक रेट से 107 रन बना पाये हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तिलक के आउट होने के तरीके से श्रीकांत नाराज हैं। उनका कहना है कि अब सुपर-8 के बचे हुए मैचों में संजू सैमसन को उनकी जगह शामिली किया जाना चाहिये। श्रीकांत ने कहा, ÷अगर सैमसन को 11 में आना है, तो तिलक के लिए कोई जगह नहीं है। कई अनय लोग भी तिलक के बल्लेबाजी के तरीके से हैरान हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने जो शॉट खेला, उसके लिए उन्हें 11 से बाहर किए जाने की पूरी संभावना है। यह काफी खराब शॉट था और ऐसा शॉट खेलने के बाद वह क्रीज पर टिके रहने के लायक नहीं थे।÷

श्रीकांत ने कहा कि विराट कोहली के संन्यास के बाद बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम मुश्किल में आ जाती है।

ब्रिस्बेन वनडे में टीम इंडिया की करारी हार, स्मृति मंधाना का अर्धशतक गया बेकार

ब्रिस्बेन (एजेंसी)। मंगलवार को ब्रिस्बेन के एलन बॉर्डर फील्ड में खेले गए वनडे द्विपक्षीय श्रृंखला के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने भारत को छह विकेट से हरा दिया। एलिसा हीली की अगुवाई वाली टीम ने तीन मैचों की वनडे श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज में 1-2 से हार के बाद इस मैच में उतरी थी। उन्होंने मेहमान टीम को 214 रनों पर रोककर 215 रनों के लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा किया।

लक्ष्य का पीछा करते हुए, कप्तान हीली ने फोएबे लिचफील्ड (32 गेंदों में 32 रन) के साथ पहले विकेट के लिए 55 रनों की साझेदारी की। श्री चरानी ने 11वें ओवर में अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। उन्होंने इसी ओवर में जॉर्जिया वोल को भी आउट किया। आउट होने वाली कप्तान हीली ने 70 गेंदों में 50 रन बनाए। उन्होंने बेथ मूनी (79 गेंदों में 76 रन) के साथ दूसरे विकेट के लिए 64 रनों की साझेदारी की। एनाबेल सदरलैंड (44 गेंदों पर 48 रन नाबाद) और गार्डनर (4 गेंदों पर 5 रन नाबाद) नाबाद रहीं और ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से जीत हासिल कर ली। मैच

जिताने वाली इस शानदार पारी के लिए मूनी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

पहले बल्लेबाजी करने का विकल्प चुनते हुए, भारतीय महिला टीम ने पहले ही ओवर में अपना पहला विकेट खो दिया जब मेगन शट ने विकेट के सामने प्रतिका रावल को कैच दे दिया। शेफाली वर्मा एक रन पीछे बल्लेबाजी करने आईं और लय हासिल नहीं कर सकीं। उन्होंने 17 गेंदों में सिर्फ चार रन बनाकर पवेलियन लौट गईं। डार्सी ब्राउन ने उन्हें आठवें ओवर में कैच आउट किया। जेमिमा रोड्रिग्स भी सिर्फ आठ रन बनाकर आउट हो गईं। पावरप्ले खत्म होने के तुरंत बाद एशले गार्डनर ने उन्हें आउट कर दिया। बेथ मूनी ने विकेट के पीछे एक शानदार कैच पकड़ा।

स्मृति मंधाना ने 20वें ओवर में ताहलिया मैकग्राथ की गेंद पर एक रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। मैकग्राथ ने अपने अगले ओवर में मंधाना को 58 रन पर आउट कर दिया। उन्होंने अपनी प्रभावशाली पारी में सात चौके लगाए। दीप्ति शर्मा क्रीज पर आईं और जल्द ही सिर्फ दो रन बनाकर पवेलियन लौट गईं। इसके बाद ऋचा घोष कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ शामिल हुईं और दोनों ने छठे विकेट के लिए 37 रन जोड़े।

एफआई प्रो लीग में स्पेन ने भारतीय हॉकी टीम को हराया

होबार्ट । स्पेन ने एफआई एच प्रो लीग के ऑस्ट्रेलियाई चरण में भारतीय हॉकी टीम को शूटआउट में 4-3 से हरा दिया। दोनो टीमों के बीच तय समय तक मुकाबला 1-1 से बराबरी पर रहा पर इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में स्पेन ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपना पर गोल नहीं कर पायीं। 19वें मिनट में कप्तान हार्दिक सिंह के एक पास पर मनिंदर सिंह ने गोल दागकर भारतीय टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। वहीं तीसरे क्वार्टर में स्पेन ने जबरदस्त प्रहार किये पर भारतीय रक्षा पंक्ति और गोलकीपर ने बचाव कर लिया। इसके बाद भारतीय टीम ने भी जवाबी हमले किये। स्पेन के ब्रूनो फॉन्ट ने अंतिम क्षणों में शानदार गोल दागकर मुकाबले को 1-1 से बराबरी पर ला दिया। वहीं इसके बाद हुए शूटआउट में भारत के अभिषेक और हार्दिक सिंह गोल नहीं कर पाये जिससे स्पेन ने 4-3 से मुकाबला जीत लिया।

बीसीएल में खेलते नजर आयेंगे धवन

मुम्बई। हाल में आयरलैंड की सोफी शाइन से दूसरी शादी करने वाले पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन अब बिग क्रिकेट लीग (बीसीएल) के दूसरे सत्र में खेलते नजर आएंगे। धवन बीसएल के दूसरे सत्र में 'यूपी ब्रिज स्टार्स' की ओर से खेलेंगे। धवन जैसे अनुभवी क्रिकेटर का लाभ टीम के युवाओं को मिलेगा। इससे पहले इसे लीग के पहले सत्र में भी धवन ने अच्छा प्रदर्शन कर सभी को प्रभावित किया था। बिग क्रिकेट लीग का आयोजन ग्रेटर नोएडा के खेल परिसर में होगा। ये टूर्नामेंट 11 मार्च से शुरु होगा और इसका खिताबी मुकाबला 22 मार्च को खेला जाएगा। यूपी ब्रिज स्टार्स प्रबंधन को उम्मीद है कि धवन की कप्तानी में टीम बेहतर प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज करेगी। उनके रहने से से युवा खिलाड़ियों को भी सीखने का काफी अवसर मिलेगा ।बीसएल एक ऐसा टूर्नामेंट हैं जिसमें गली-मोहल्लों में खेलने वाले प्रतिभाशाली क्रिकेटरों को अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय सितारों के साथ खेलने का अवसर मिलता है। इस लीग में डॉक्टर, इंजीनियर, दुकानदार, वकील, किसान या किसी भी अन्य पेशे से जुड़ा व्यक्ति खेल सकता है। खास बात ये है कि आम खिलाड़ियों को भी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ खेलने का अवसर मिलता है।

धोनी ऐसी बाइक चलाते दिखे जो भारत में लांच ही नहीं हुई थी

रांची । भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बाइक ?स के काफी शौकीन हैं। रांची की सड़कों पर भी वह कई बार बाइक चलाते दिखते हैं। उनके पास एक से बढ़कर एक बाइकें हैं। जिसमें डुकाटी, कावासाकी, हार्ले-डेविडसन, यामाहा के अलावा कई विंटेज और हाई-परफॉर्मेंस बाइक्स भी हैं। वहीं अब धोनी एक वीडियो में

ऐसी बाइक चलाते दिखें हैं जो भारत में कभी लांच ही नहीं हुई थी। ये यामहा की एसआर400 है। यह पुराने जमाने की ऐसी बाइक है जो भारत में कुछ ही लोगों के पास हैं। ये क्लासिक रेट्रो-स्टाइल मोटरसाइकिल साल 1970 की यूनिवर्सल जापानी मोटरसाइकिल्स से प्रेरित होकर 1978 में बनायी गयी थी पर 2021 में इसे बनाना बंद कर दिया गया। इसका कारण है कि यह पुरानी टेक्नोलॉजी वाली बाइक थी और प्रदूषण के नये मानकों पर खरी नहीं उतरी। यह बाइक कस्टमाइज़ेशन के कारण काफी लोकप्रिय हुई है। इससे भारत में कभी भी आधिकारिक रुप से लांच नहीं किया गया केवल ये आयात की गयी है। ये एक मोटरसाइकिल नहीं, बल्कि दोपहिया वाहनों की दुनिया में एक 'टाइम मशीन' की तरह है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका 399सीसी का एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलिंडर इंजन है। इस बाइक की ट्यूनिंग इस तरह की गई है कि यह कम रफ्तार पर भी काफी अच्छी चलती है ।इसमें इलेक्ट्रिक स्टार्ट का विकल्प भी नहीं है और किक से स?टार्ट होती है। ये ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर भी काफी अच्छे से चलती है। इसमें सिग्नेचर टीयरड्रॉप फ्यूल टैंक, गोल हेडलाइट और चमकता हुआ क्रोम एग्जॉस्ट दिया गया है। ये बाइक 130-140 किमी/घंटा की टॉप स्पीड तक जा सकती है।

गंभीर की पॉलिटिक्स ने टीम इंडिया की इमेज को नुकसान पहुंचाया, पूर्व पाक बल्लेबाज का बड़ा बयान

नई दिल्ली (एजेंसी)। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 चरण में दक्षिण अफ्रीका से मिली हार के बाद भारतीय टीम पर सवाल उठने लगे हैं। इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज अहमद शहजाद ने टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर पर तीखी टिप्पणी की है। शहजाद का दावा है कि गंभीर की राजनीतिक पृष्ठभूमि का असर टीम के माहौल पर पड़ा है। साथ ही उन्होंने चयन फैसलों और संसाधनों के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल उठाए हैं।

सुपर 8 हार के बाद बढ़ा दबाव

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर 8 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मिली बड़ी हार ने भारतीय खेमे में चिंता बढ़ा दी है। इस हार के बाद सेमीफाइनल की राह मुश्किल हो सकती है, जिससे कोचिंग स्टाफ और टीम मैनेजमेंट पर दबाव साफ दिख रहा है। कुछ चयन फैसलों ने भी बहस को जन्म दिया। अहम मुकाबले में अक्षर पटेल की जगह वाशिंगटन सुंदर को मौका देने पर फैंस और क्रिकेट विशेषज्ञों ने सवाल उठाए।

पॉलिटिक्स टीम में भी आ गई : शहजाद

अहमद शहजाद ने कहा कि 2019 से

2024 के बीच राजनीति में सक्रिय रहने के दौरान गंभीर का दृष्टिकोण बदल गया। उनका इशारा उस समय की ओर था जब गंभीर सांसद रहे। शहजाद का मानना है कि राजनीति का असर अब टीम प्रबंधन में भी दिखाई दे रहा है। उनके मुताबिक, किसी भी खेल में सफलता के लिए पूर्ण फोकस जरूरी होता है, और अगर ध्यान बंटे तो उसका असर टीम के माहौल पर पड़ सकता है।

कुलदीप यादव को लेकर उठे सवाल

शहजाद ने यह भी कहा कि टीम अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल नहीं कर रही है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कुलदीप यादव का जिक्र किया, जिन्हें टूर्नामेंट में सीमित मौके मिले हैं। उनका कहना था कि कुलदीप जैसे मैच-विनर स्पिनर को लगातार बाहर रखना समझ से परे है। टी20 फॉर्मेट में विविधता और विकेट लेने की क्षमता बेहद अहम होती है, और कुलदीप उस भूमिका को निभा सकते हैं।

कप्तान के साथ विवाद की चर्चा

शहजाद ने एक कथित घटना का भी जिक्र किया, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ मैच के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव और कुलदीप के बीच कहासुनी की बात सामने आई थी। हालांकि बाद में दोनों खिलाड़ियों ने सार्वजनिक रूप से ऐसी किसी अनबन से इनकार किया। फिर भी शहजाद का मानना है कि कुलदीप को बाहर रखने के पीछे कोई और कारण हो सकता है। हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

चयन और रणनीति पर बहस

टीम इंडिया के चयन और रणनीति को लेकर चर्चा तेज है। आलोचकों का कहना है कि बड़े टूर्नामेंट में टीम कॉम्बिनेशन का संतुलन बेहद अहम होता है। स्पिन विकल्पों और ऑलराउंडर्स के बीच सही तालमेल बनाना जीत की कुंजी साबित हो सकता है। इसके बावजूद यह भी तथ्य है कि गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार की अगुवाई में भारत ने हालिया बाइलेटरल सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया है।

जब हम वेस्टइंडीज से खेलेंगे तो नेट रन-रेट जरूर मायने रखेगा : पार्थिव पटेल

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सुपर 8 मैच में अहमदाबाद में 76 रन से हार का सामना करना पड़ा। जियोस्टार के 'फॉलो द ब्लूज' पर बात करते हुए, जियोस्टार एक्सपर्ट पार्थिव पटेल ने भारत की हार, पावरप्ले में उनकी बैटिंग को लेकर चिंताओं और ज़िम्बाब्वे के खिलाफ अगले मैच के लिए प्लेइंग इ में संभावित बदलावों का विश्लेषण किया।

पार्थिव पटेल ने भारत के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका की जीत पर कहा, '12 मैचों की जीत का सिलसिला पक्का खत्म हो गया है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने बेहतर क्रिकेट खेला। मुझे लगा कि उन्होंने बहुत अच्छे से प्लान बनाया था और अपनी स्ट्रेटेजी को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया। हालांकि, हार का मार्जिन काफी है, और नेट रन-रेट निश्चित रूप से तब काम आएगा जब हम 1 मार्च को कोलकाता में वेस्ट इंडीज का सामना करने जाएंगे। यह दक्षिण अफ्रीका के लिए एक बड़ी जीत है, और यह सभी मुश्किलों के बावजूद मिली, यह देखते हुए कि इंडियन टीम जिस तरह से खेल रही थी। आपको दक्षिण अफ्रीका को क्रेडिट देना होगा। हां, उन्हें कुछ समय के लिए अहमदाबाद में खेलने का फायदा मिला, लेकिन यह हमारा घर है। जाहिर है, भारतीय टीम वापस जाकर यह देखना चाहेगी कि क्या उन्होंने चीजों को सिंपल रखने के बजाय उन्हें कॉम्प्लिकेटेड बना दिया था।'

पावरप्ले में भारत को जरूरी शुरुआत नहीं मिलने पर पार्थिव पटेल ने कहा, 'सिर्फ इस गेम में ही नहीं, बल्कि नामीबिया या अमेरिका और पाकिस्तान के खिलाफ भी, हालांकि वह बैटिंग के लिए मुश्किल विकेट था, लेकिन जल्दी विकेट खोना भारत के लिए चिंता की बात रही है। जिस तरह से भारत ने पावरप्ले में विकेट खोए हैं, खासकर ऑफ-स्पिनरों के खिलाफ, वह चिंता की बात है। इस बार यह मार्करम के लिए था। वे बहुत ज़्यादा शॉट खेल रहे हैं, एंगल के खिलाफ जा रहे हैं। शायद वे बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा बदलाव करने के बारे में सोच सकते हैं, खासकर टॉप पर तीन लेफ्ट-हैंडर होने पर। वे सूर्यकुमार को नंबर तीन पर भेज सकते थे। मुझे लगा कि भारत इस गेम में ऐसा कर सकता था। जब आप हाई-रिस्क, हाई-रिवॉर्ड वाला गेम खेलते हैं, तो ऐसे दिन आना तय है।'

पटेल ने संजू सैमसन की प्लेइंग इ में वापसी पर कहा, 'मैं अक्षर पटेल को टीम में वापस आते देखना चाहूंगा। उन्होंने पहले भी अहम पारियां खेली हैं। हां, मैच-अप की भी अहमियत है, लेकिन मैं अक्षर पटेल को जरूर लाऊंगा। संजू सैमसन का भी सवाल है। चेन्नई में अब उनकी घर वापसी भी हो सकती है। यह कुछ ऐसा है जिस पर भारत जरूर विचार करेगा, खासकर यह देखते हुए कि भारतीय लेफ्ट-हैंडर ऑफ-स्पिनर के खिलाफ बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। जब आप जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हैं, तो सिकंदर रजा भी पावरप्ले में काम आ सकते हैं। मैं तिलक की जगह संजू सैमसन को नहीं उतारूंगा। हां, संजू सैमसन भी

अच्छे फॉर्म में नहीं हैं। या शायद, भारत बैटिंग ऑर्डर बदलने की कोशिश कर सकता है, फिर सूर्या को नंबर तीन पर बैटिंग करनी होगी।'

अब अपनी हॉबी को ही बना सकते हैं करियर ऑप्शन

आज के समय में जॉब करना आसान नहीं रह गया है। यह काम तब और मुश्किल हो जाता है, जब किसी का प्रोफेशन और हॉबी अलग-अलग हो। जिसके कारण आजकल कई लोग जॉब तो कर रहे हैं , लेकिन वे उन जॉब्स से खुश नहीं हैं। पैसा कमाने के लिए जॉब करना और अपने पैशन को फॉलो करके उसमें आगे जाना दोनों बहुत अलग बात हैं। फिर चाहे उसमे पैसे थोड़े कम क्यों न हो।

फोटोग्राफी, राइटिंग, म्यूजिक, डांस, सिंगिंग, कुकिंग, पेंटिंग समेत कई ऐसी हॉबी होती हैं, जिन्हे आप फुल टाइम करियर में बदल सकते हैं। सोचिये जो काम आपको सबसे ज्यादा पसंद है और आपकी हॉबी है, उसे आप अलग से समय निकाल कर करते हैं, अगर इसी हॉबी को अपना प्रोफेशन बना लें तो कितना अच्छा रहेगा। अगर आप भी अपनी हॉबी को करियर का रूप देना चाहते हैं, तो यहां पर दिए गए 7 टिप्स को फॉलो कर सकते हैं।

सबसे पहले रिसर्च करें

अपनी हॉबी को प्रोफेशन में बदलने के लिए सबसे पहले जो काम आपको करना है वो है रिसर्च। किसी भी हॉबी के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। आपको पता लगाना है कि क्या आपकी हॉबी फुल टाइम करियर बना सकती है या नहीं। उसमें जॉब और करियर के क्या अवसर हैं और उस क्षेत्र में कितने लोग काम कर रहे हैं और कितने अनुभव की जरूरत पड़ती है।

सही फीडबैक लें

कोई भी व्यक्ति अपने काम को जज नहीं कर सकता और न ही आपका परिवार या दोस्त आपकी इसमें मदद कर सकते हैं। किसी भी काम को शुरू करने से पहले गाइडेंस के लिए जरूरत होती है एक अनुभवी प्रोफेशनल की जो आपका मेंटर बने। हमेशा याद रखें कि काम शुरू करने से पहले अपनी हॉबी के बारे में अपने मेंटर से ईमानदार फीडबैक लेना बिल्कुल ना भूलें।

शुरू से शुरुआत करें

यह बात पहले ही अपने मन में बैठा लें कि जब आप कोई करियर स्विच करेंगे तो हो सकता है कि आपको नीचे से ही शुरू करना पड़े। आप अपनी जॉब में फिलहाल ऊंची पोस्ट पर हों, लेकिन आपको नये करियर में नीचे से ही शुरू करना होगा। इसलिए अपनी तैयारी पहले से ही पूरी कर लें।

पुरानी स्किल्स का इस्तेमाल

आपके पुराने और नये करियर में भले ही कोई समानताएं न हों। लेकिन फिर भी हर जगह से हम कुछ न कुछ स्किल्स तो सीखने को मिलती ही हैं। ऐसी कई स्किल होती हैं, जो हर फील्ड में काम आती हैं। जैसे अगर आप किसी कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और पेंटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपकी मार्केटिंग स्किल यहां भी काम आएगी। इसलिए ध्यान रखें कि सभी स्किल का इस्तेमाल अपने नये करियर में करें।

अपनी फील्ड के एक्सपर्ट बनें

अपनी हॉबी में करियर बनाने से पहले आप उस फील्ड से जुड़े लोगों से संपर्क बनाएं। अपनी नॉलेज और स्किल्स को बढ़ाएं, एक अच्छा नेटवर्क बनाएं। यह आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। आपको उस फील्ड में सबसे बेहतर बनाने की कोशिश करें।

अपने काम को मोनेटाइज करें

प्रूफ ऑफ कंसेप्ट एक बिजनेस टर्म है जिसका इस्तेमाल उन उद्यमियों के द्वारा किया जाता है जो फंडिंग की तलाश में होते हैं। आपको भी अपने लिए फंडिंग का इंतजाम करना चाहिए। क्योंकि किसी भी काम के लिए आर्थिक सुविधा बहुत जरूरी है। अगर वह नहीं रहेगा तो आप आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए अपने काम से पैसे कमाने की कोशिश करें। आप चाहे तो आपकी स्किल को ऑनलाइन सिखा सकते हैं, एक्सपर्ट लेक्चर ले सकते हैं। या फिर खुद की वर्कशॉप भी लगा सकते हैं।

इस तरह बदले अपने पैशन को प्रोफेशन में

जब आपके मन में अपने पैशन को प्रोफेशन बनाने का विचार आए तो सबसे पहले अपने सभी हॉबी की लिस्ट बनाएं। मान लीजिये आपकी तीन हॉबी हैं। आपको लिखने का शौक हैं, फोटोग्राफी और पेंटिंग का भी शौक है। अब एक- एक हॉबी पर विचार कीजिए और उसके साथ कुछ दिन जी कर देखें। इससे आपको अपने आप ही मालूम हो जायेगा कि किस काम को लेकर आप ज्यादा बेहतर हैं और वह कार्य करते हुए आपको ज्यादा खुशी मिलती है।

सफलता के लिए हमेशा याद रखें...

किसी भी कार्य की सफलता के लिए भावना अच्छी होनी चाहिए। कार्य को प्रारम्भ करने के पीछे हमारा भाव क्या है। हम क्या करना चाहते हैं इसका महत्व है। सफलता के लिए भगवान का सुमिरन कर कार्य करें। भगवान का ध्यान कर किए जाने वाले कार्य में सफलता अवश्य मिलती है। केवल परिश्रम से कुछ नहीं होता। कुछ लोग भगवान की असीम कृपा से कम परिश्रम में भी सफलता की ऊंचाइयों को छू लेते हैं। संतों ने सफलता के 3 मंत्र बताए। पहला भगवान का स्मरण, दूसरा धैर्य तथा तीसरा परमार्थ की भावना जुड़ी होनी चाहिए।

प्रत्येक मंदिर बाहर से स्वच्छ होना चाहिए और भीतर से पवित्र होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति भी बाहर से स्वच्छ और भीतर से पवित्र होना चाहिए। फिर कोई लम्बी साधना करने की जरूरत नहीं। मां त्रिस्तरीय काम करती है। सृष्टि को उत्पन्न करती है, उसका परिपालन और उसका संघार करती है। अम्बा के 3 स्तर हैं, स्त्री शरीर अम्बा का ही अंश है। ऐसा मानकर उसका 3 स्तर पर सम्मान करना चाहिए। कन्या का सम्मान, धर्मपत्नी का सम्मान और मां का सम्मान। आनंद की अंतिम सीमा आंसू हैं। हम सबका जीवन फल होना चाहिए प्रेम। सत्य शायद हम चूक जाएं। करुणा छूट जाए लेकिन प्रेम बना रहे। यह जीवन का फल है।

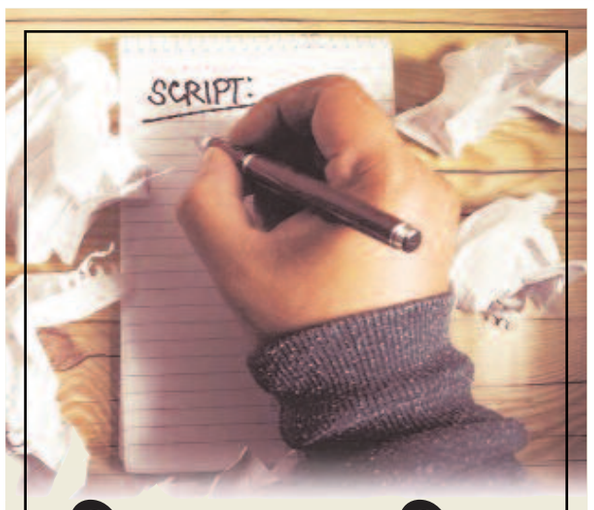

स्क्रिप्ट राइटिंग में करियर

यदि आप लेखन में दक्षता रखते हैं और आपको किताबें पढने में भी गहरी रुचि है तो स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर आप अपने शौक को करियर का रूप भी दे सकते हैं। जो युवा लिखने-पढने के साथ मानवीय संवेदनाओं को पकड़ कर अभिव्यक्त करने की क्षमता रखते हैं उनके लिए भी इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं।

कार्यक्षेत्र

विज्ञापनों के लिए स्क्रिप्ट राइटर्स की सेवाएं विशेष तौर पर ली जाती हैं। अक्सर विज्ञापनों में ऐसे शब्दों या पंक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है जो लोगों की जुबान पर चढ़ जाती हैं। ये सब स्क्रिप्ट राइटर के दिमाग की ही उपज होते हैं। ऐसी रोचक बातों को जिंगल्स कहा जाता है।

बेशक स्क्रिप्ट राइटर का काम सिर्फ जिंगल लिखना ही नहीं होता बल्कि और कई चीजें हैं जो स्क्रिप्ट राइटर करते हैं लेकिन अधिकतर की शुरूआत जिंगल्स से ही होती है। जाहिर है कि स्क्रिप्ट राइटिंग कहानियां और कविताएं लिखने से कुछ अलग होता है क्योंकि स्क्रिप्ट में लिखी गई हर बात का फिल्मांकन किया जाता है इसीलिए लेखक को यह सोचकर लिखना पड़ता है कि उसके द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं देखी जाएगी।

कौशल

इसमें क्षेत्र में करियर बनाने के लिए छात्रों में रचनात्मकता का होना आवश्यक है। कम शब्दों में आपको उत्पादों की विशेषताओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाना होता है। विज्ञापनों के लिए ऐसी जिंगल्स की रचना करनी पड़ती है कि सुनते या पढ़ते ही वह ग्राहक के जेहन में आ जाए। वैसे कोई डिग्री कोर्स तो नहीं होता पर ये जर्नलिज्म के अंतर्गत आता है।

कल तक विज्ञापन ग्राहकों की संतुष्टि के लिए बनाए जाते थे लेकिन आज जो विज्ञापन आ रहे हैं वे ग्राहकों के संतोष के साथ उसकी खुशी और मनोरंजन को भी महत्व दे रहे हैं। मानवीय भावनात्मक पक्षों को छूते विज्ञापन न सिर्फ देर तक याद रहते हैं बल्कि मन पर भी गहरा असर छोड़ते हैं।

जिस भी भाषा में आप स्क्रिप्ट राइटिंग करना चाहते हैं उसका गहन ज्ञान आपको होना चाहिए। आपको अधिक से अधिक पुस्तकों को भी पढना चाहिए ताकि आपको विभिन्न लेखकों की शैली की जानकारी भी प्राप्त हो सके। साथ ही फिल्मों तथा धारावाहिकों की स्क्रिप्ट पर गौर करने की आदत भी डाल लें। इसके बाद आप स्क्रिप्ट लेखन में हाथ आजमाएं।

योग्यता

स्क्रिप्ट राइटिंग में सबसे अहम जरूरत रचनात्मकता की होती है जो पूर्णत- व्यक्ति की विश्लेषण और कल्पना क्षमता पर आधारित होती है लेकिन फिर भी इसके लिए पत्रकारिता का कोर्स कर लिया जाए तो बेहतर होता है। किसी भी विषय में 12वीं कक्षा पास करने के बाद पत्रकारिता में ग्रैजुएशन कर सकते हैं। जो छात्र ग्रैजुएशन कर चुके हैं वे किसी प्रतिष्ठित संस्थान से पत्रकारिता में एम.ए. भी कर सकते हैं।

प्रमुख संस्थान

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
एमिटी स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, नई दिल्ली
इंडियन इंस्टी. आफ मास कम्युनिकेशन नई दिल्ली
जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर, मध्य प्रदेश
माखन लाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल, मध्य प्रदेश।

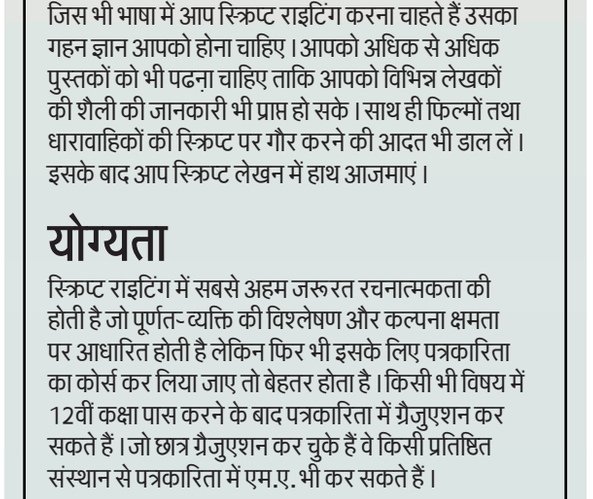

भारत में लगातार बढ़ती जा रही प्रतिस्पर्धा की वजह से अपनी इमेज मैनेज करना भी एक अहम जरूरत बन चुकी है। अधिक से अधिक लोग अब इस जरूरत को महसूस कर रहे हैं जिस वजह से देश में इमेज कंसल्टैंट की सेवाओं की मांग में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है।

लाभदायक करियर इमेज कंसल्टिंग

इमेज कंसल्टिंग के तहत लोगों को अपने भीतर छुपी क्षमताओं को निखारने और साथ ही साथ उन क्षमताओं को सभी के समक्ष प्रदर्शित करने के लिए अपनी अपीयरैंस (दिखावट) के प्रबंधन हेतु मार्गदर्शन किया जाता है। इमेज कंसल्टिंग के तहत लोगों को परिधान पहनने व तैयार होने के ढंग, बॉडी लैंग्वेज, शिष्टाचार एवं सॉफ्ट स्किल्स के बारे में शिक्षित किया जाता है। इमेज कंसल्टैंट व्यक्तिगत रूप से तथा समूह में कोचिंग प्रदान करते हैं। वे किसी एक व्यक्ति अथवा कम्पनियों को अपनी सेवाएं देते हैं। वे लोगों के लिए मुक्त कार्यशाला भी आयोजित करते हैं। इस क्षेत्र से जुड़े कार्यों में पर्सनल शॉपिंग, यूनिफॉर्म डिजाइन, इमेज मैनेजमैंट, पॉलिसी डिजाइन, स्टाइलिंग आदि भी शामिल हैं। भारत में लगातार बढ़ती जा रही प्रतिस्पर्धा की वजह से अपनी इमेज मैनेज करना भी एक अहम जरूरत बन चुकी है। अधिक से अधिक लोग अब इस जरूरत को महसूस कर रहे हैं जिस वजह से देश में इमेज कंसल्टैंट की सेवाओं की मांग में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है।

यह ऐसा करियर है, जिसमें व्यक्ति अन्य लोगों के विकास का मुख्य सहयोगी बनता है तथा अन्य लोगों को और अधिक सफल बनाने से उसे सफलता मिलती है। यह क्षेत्र उन महिलाओं को करियर बनाने का दूसरा मौका देता है जिन्होंने कुछ समय के लिए अपने पहले करियर को छोड़ रखा हो। इमेज कंसल्टिंग बिजनैस इंस्टी. भारत में इमेज कंसल्टैंसी की शिक्षा तथा प्रशिक्षण देने वाला अग्रणी संस्थान होने के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर भी एक प्रतिष्ठित संस्थान है। यह संस्थान इमेज कंसल्टिंग एवं बिजनैस प्रोग्राम संबंधी अनोखे पेशेवर कोर्स करवाता है। इस संस्थान की डायरैक्टर सुमन अग्रवाल भारतीय उपमहाद्वीप की वरिष्ठतम इमेज कंसल्टैंट मानी जाती हैं। उनकी कहानी भी एक उत्तम प्रेरणा स्रोत है। उन्हें कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ देनी पड़ी थी परंतु आज वह एक सफल उद्यमी तथा इस संस्थान की डायरैक्टर हैं, जिसकी स्थापना उन्होंने 2009 में की। यूनाइटेड किंगडम स्थित फैडरेशन ऑफ इमेज प्रोफैशनल इंटरनैशनल द्वारा उन्हें इमेज मास्टर अवार्ड से नवाजा गया जिससे वह भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वाधिक वरिष्ठ इमेज कंसल्टैंट बन गईं। इमेज कंसल्टिंग में पहनावे के महत्व पर वह कहती हैं, ''80 प्रतिशत से अधिक संवाद दृश्य होता है और पहनावा इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब भी आप किसी से मिलते हैं तो व्यक्ति का सबसे अधिक ध्यान सामने वाले के पहनावे पर ही जाता है। हालांकि यह बताना जरूरी है कि पहनावे के संबंध में कौशल एक इमेज कंसल्टैंट के पास होता है, वह सर्वश्रेष्ठ फैशन डिजाइनर समेत किसी अन्य पेशेवर के पास नहीं हो सकता है। महत्व बढ़िया परिधानों का नहीं होता, बल्कि उस संदेश का होता है जो आप अपने पहनावे से सामने वाले को देना चाहते हैं। सही पहनावे को सुनिश्चित बनाने के लिए व्यक्ति को अपने काम, लक्ष्यों एवं मौके का ध्यान रखने के अलावा आकर्षक दिखने के लिए अपने शारीरिक ढांचे, रंग-रूप, चेहरे के आकार आदि पर भी गौर करना पड़ता है।'' उनके अनुसार इस क्षेत्र में रुचि रखने वाले युवाओं के लिए यह एक उत्तम एवं बेहद लाभदायक करियर साबित हो सकता है।

पत्राचार शिक्षा से बदलती युवाओं की तकदीर

आज सभी विषयों में ग्रैजुएशन तथा मास्टर डिग्री कोर्स के अलावा अनेक सर्टीफिकेट कोर्स एवं डिप्लोमा भी पत्राचार माध्यम से दूरस्थ शिक्षा के रूप में उपलब्ध हैं। इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य छात्रों को सभी संबंधित विषयों का बुनियादी ज्ञान प्रदान करना होता है। अधिकतर पत्राचार पाठ्यक्रम विश्वविद्यालयों द्वारा चलाए जाते हैं और इनमें सभी विषय-विधाओं के 10+2 छात्रों को प्रवेश दिया जाता है।

कुछ प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में प्रवेश एक चयन परीक्षा के माध्यम से दिया जाता है। पत्राचार शिक्षा ने हमारे देश की शिक्षा प्रणाली में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन ला दिया है। पत्राचार माध्यम से अध्ययन करने वाले छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न आधुनिक तकनीकों का सहारा भी दिया जा रहा है। उपग्रह संचार, लो पावर ट्रांसमीटर्स की सहायता एवं सूचना सुपर-हाइवेज के माध्यम से देश भर में शिक्षा का प्रसार हो रहा है।

देश में अनेक मुक्त विश्वविद्यालय तथा उससे भी अधिक नियमित विश्वविद्यालय तथा कई अन्य संस्थाएं दूरस्थ अध्ययन कार्यक्रम चलाते हैं। दूरस्थ शिक्षा पद्धति कई श्रेणियों के शिक्षार्थियों, विशेष रूप से देरी से पढ़ाई शुरू करने वालों, जिन व्यक्तियों के घर के पास उच्चतम शिक्षा साधन नहीं है, सेवारत व्यक्तियों और अपनी शैक्षिक योग्यताएं बढ़ाने के इच्छुक व्यक्तियों को लाभ प्रदान कर रही है। मुक्त विश्वविद्यालय ऐसे लचीले पाठ्यक्रम विकल्प देते हैं जिन्हें वे छात्र ले सकते हैं जिनके पास कोई औपचारिक योग्यता नहीं है किन्तु अपेक्षित आयु (प्रथम डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए 18 वर्ष) के हो चुके हैं और लिखित प्रवेश परीक्षा भी उत्तीर्ण कर चुके हैं। ये पाठ्यक्रम छात्र अपनी सुविधानुसार भी ले सकते हैं। विश्वविद्यालयों के दूरस्थ शिक्षा केंद्र न्यूनतम पात्रता रखने वाले उम्मीदवारों को प्रवेश देते हैं। यह पात्रता नियमित पाठ्यक्रमों के समान ही होती है। पत्राचार शैक्षिक संस्थाएं छात्रों को पाठ्यक्रम सामग्री के साथ-साथ संपर्क कक्षाएं भी उपलब्ध कराती हैं और परीक्षाएं संचालित करती हैं।

अधिकांश विश्वविद्यालय मुद्रित अध्ययन सामग्री के अलावा अपने स्थानीय केंद्रों पर मल्टीमीडिया साधनों से भी छात्रों को शिक्षित करते हैं। ये विश्वविद्यालय ग्रैजुएशन पाठ्यक्रम, मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम, एम.फिल पीएच.डी. तथा डिप्लोमा एवं सर्टीफिकेट पाठ्यक्रम भी चलाते हैं जिनमें से अधिकांश पाठ्यक्रम करियर उन्मुखी होते हैं।

इंडो-हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनी प्रियामणि

प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड से निकलकर हॉलीवुड में एक अलग मुकाम बनाया है। साथ ही बाकी भारतीय कलाकारों के लिए भी राह खोली है। प्रियंका की राह पर चलते हुए साउथ एक्ट्रेस प्रियामणि भी अब एक इंडो-हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन रही हैं। इसमें उनके साथ टीवी पर 'महादेव' का किरदार निभाने वाला एक चर्चित एक्टर नजर आएगा।

मोहित रैना होंगे प्रियामणि के अपोजिट

इस फिल्म में प्रियामण के अपोजिट टीवी के चर्चित एक्टर मोहित रैना नजर आएंगे। वह बॉलीवुड फिल्मों और सीरीज में भी दमदार किरदार निभा चुके हैं। लेकिन टीवी सीरियल 'देवों के देव महादेव' में उन्होंने भगवान शिव की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म का हिस्सा बनने पर मोहित रैना कहते हैं, 'यह प्रोजेक्ट मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि यह पहचान और अपनेपन को बहुत ईमानदारी से दिखाता है।' वहीं प्रियामणि ने कहा, 'जिस चीज ने मुझे तुरंत इस फिल्म की तरफ खींचा, वह थी कहानी का इमोशन और सच्चाई।' यूएस बेस्ड रेड बाइसन प्रोडक्शंस ने इस क्रॉस बॉर्डर फीचर फिल्म के लिए मुंबई के एज्योर एंटरटेनमेंट के साथ पार्टनरशिप की है। यह फिल्म हर्ष महादेश्वर द्वारा लिखी गई। वही इसका डायरेक्ट करेंगे। अभी तक फिल्म का टाइटल नहीं रखा गया है। यह एक फीचर फिल्म होगी, जिसकी कहानी सच्ची कहानी पर आधारित है। इसमें एक अप्रवासी परिवार की भावुक कहानी दिखाई जाएगी। यह प्रोजेक्ट अप्रैल 2026 में शुरू होगा।

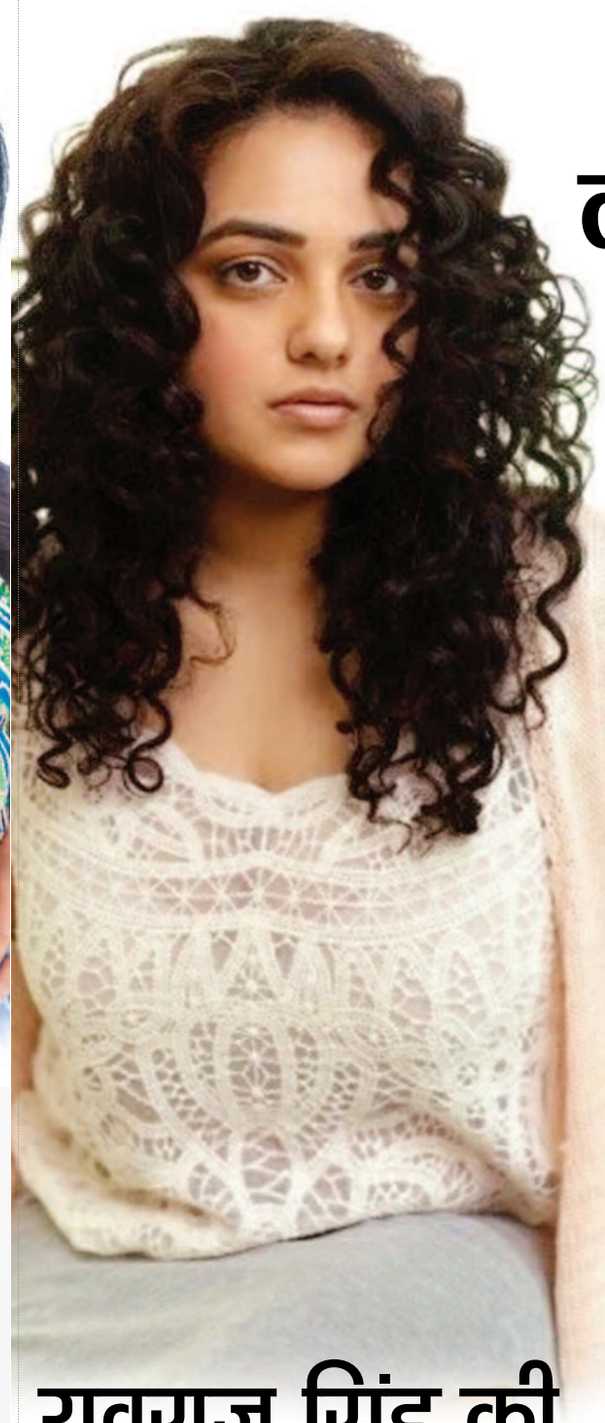

अब 'प्रोड्यूसर' बन लोगों का दिल जीतेंगी नित्या मेनन

अपने अभिनय से लोगों के दिलों में राज करने वाली साउथ सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री नित्या मेनन अब नई शुरुआत करने जा रही हैं। अभिनेत्री ने बताया कि वे अब बतौर प्रोड्यूसर डेब्यू करने जा रही हैं। अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक खास वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने नए प्रोडक्शन हाउस का ऐलान किया। अभिनेत्री नित्या मेनन ने लिखा, 'मेरे लिए फिल्में बनाना सिर्फ कहानियां सुनाना नहीं है, बल्कि दिल से दिल जुड़ने का तरीका है। जब मैं कुछ बनाती हूं तो यह न सिर्फ दर्शकों को बदलता है, बल्कि मुझे भी बदल देता है।' अभिनेत्री ने बताया कि रचनात्मक प्रक्रिया में डूबकर मैं खुद में बदलाव महसूस करती हूं और जो इसे देखते हैं, उनके अंदर भी एक हल्का-सा परिवर्तन आता है। अभिनेत्री ने लिखा, 'यह बदलाव शुरू में शायद नजर न आए, लेकिन यह हमेशा के लिए असर छोड़ जाता है। फिल्म बनाना मेरे लिए व्यक्तित्व के उस सच्चे और संवेदनशील हिस्से को छूने जैसा है, जो सबसे असली होता है, जब मैं अभिनय करती थी। उसी समय मैंने सोच लिया था कि मैं प्रोड्यूसर बनूंगी और अब प्रोड्यूस करने पर भी यही सोच बनी रहेगी। आपके सामने पेश है- कीयूरी प्रोडक्शंस।' वीडियो में बताया गया है कि केयुरी धरती की गुफाओं से निकली है, चट्टान से बनी है, रोशनी से प्यार करती है, और किसी खास रूप में नहीं बंधी है। यह नाम और उसका मतलब नित्या की रचनात्मक सोच को दर्शाता है, जहां वे ऐसी कहानियां बनाना चाहती हैं जो गहरी भावनाओं को छूएं और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं।

नित्या मेनन साउथ इंडियन सिनेमा में अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जानी जाती हैं। वे अभिनेत्री होने के साथ-साथ पार्श्व गायिका भी हैं, जो मुख्य रूप से मलयालम, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ फिल्मों में अपने दमदार अभिनय के लिए जानी जाती हैं। उन्हें 'थिरुचित्राम्बलम' (2022) के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और चार फिल्मफेयर अवार्ड साउथ मिल चुके हैं। साल 1998 में एक बाल कलाकार के रूप में शुरुआत करने वाली नित्या मेनन बॉलीवुड की फिल्म 'मिशन मंगल' में नजर आई थीं।

युवराज सिंह की बायोपिक करना चाहते हैं सिद्धांत चतुर्वेदी

अपनी आगामी फिल्म ' दो दीवाने सहर में' को लेकर चर्चा में बने अभिनेता सिद्धांत चतुर्वेदी ने एक बार फिर अपने उस ड्रीम रोल के बारे में खुलकर बात की है, जो सालों से उनके दिल के बेहद करीब है। जी हाँ, अपने करियर की शुरुआत क्रिकेट पर आधारित वेब सीरीज 'इनसाइड एज' से करनेवाले सिद्धांत चतुर्वेदी ने एक बार फिर क्रिकेट की तरफ लौटते हुए भारतीय क्रिकेट के दिग्गज क्रिकेटर युवराज सिंह की बायोपिक करने की इच्छा जताई है। गौरतलब है कि अमेजॉन प्राइम विडिओ के वेब सीरीज 'इनसाइड एज' में क्रिकेट की चमक-दमक के पीछे की अंधेरी दुनिया को सिद्धांत ने बखूबी उकेरा था। फिलहाल बायोपिक के संदर्भ में सिद्धांत कहते हैं, 'मैं वर्ष 2019 से कहता आ रहा हूं और आज भी कहूंगा और कहूंगा, बल्कि इसे मैनिफेस्टभी करता हूँ एक दिन मुझे मशहूर क्रिकेटर युवराज सिंह की बायोपिक करने का मौक़ा मिले। उनकी जर्नी एक रोलरकोस्टर की तरह वाकई अविश्वसनीय रही है। मुझे वे न सिर्फ क्रिकेटर के तौर पर पसंद हैं, बल्कि व्यक्तित्व भी उनका शानदार है। मैं उनके क्रिकेट के साथ उनकी लाइफस्टाइल, और समस्याओं के प्रति उनके जज्बे को सलाम करता हूँ, जिस तरह उन्होंने परेशानियों को मात दी। वाकई वे एक आइकन हैं, और दुनिया को उनकी कहानी जरूर जाननी चाहिए।' वैसे बायोपिक की बात करें तो सिद्धांत जल्द ही दिग्गज फिल्ममेकर 'वी. शांताराम' का चुनौतीपूर्ण बायोपिक में नजर आनेवाले हैं और इसके फर्स्ट लुक के साथ ही वे अपने दर्शकों की सराहना भी पा चुके हैं।

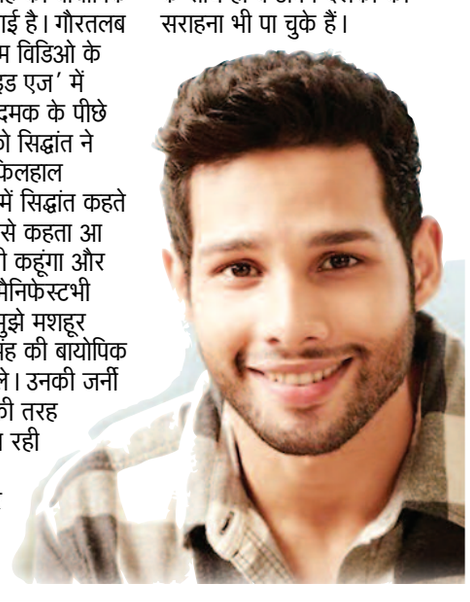

'धुरंधर 2' और 'टॉक्सिक' से बचकर निकले सनी देओल; आगे खिसकी 'गबरू' की रिलीज डेट

सनी देओल अभिनीत फिल्म 'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस पर जबर्दस्त तरीके से सफल हुई है। इस बीच वे अपने आगामी प्रोजेक्ट्स को लेकर चर्चा में हैं, जिनमें फिल्म 'गबरू' का भी नाम है। पहले यह फिल्म मार्च में रिलीज होने वाली थी। मगर, अब दर्शकों को इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। रिलीज डेट में बदलाव किया गया है।

'गबरू' कब होगी रिलीज?

'बॉर्डर 2' के बाद सनी देओल के फैंस की नजर उनकी आगामी फिल्मों पर टिकी है। शशांक उदयपुरकर निर्देशित यह फिल्म पहले 13 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी। मगर, अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, यह फिल्म 08 मई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। हाल ही में हड्डु के साथ बातचीत में सनी देओल ने 'गबरू' को अपने दिल के सबसे करीब फिल्मों में से एक बताया।

फिल्म 'चांद मेरा दिल' से होगा टकराव

फिल्म 'गबरू' को विशाल राणा और ओम छंगानी के प्रोड्यूस किया है। फिल्म में सनी देओल के साथ सिमरन और प्रीत कमानी अहम रोल में हैं। सनी देओल की 'गबरू' की रिलीज डेट में बदलाव के बाद अब इसका मुकाबला लक्ष्य ललवानी और अनन्या पांडे की फिल्म 'चांद मेरा दिल' से होगा। यह फिल्म भी 08 मई को रिलीज होने वाली है। अनन्या और लक्ष्य की फिल्म को करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले बनाया गया है।

'धुरंधर 2' और 'टॉक्सिक' से बच निकले सनी देओल

बता दें कि मार्च में दो बड़ी फिल्में सिनेमाघरों में दस्तक दे रही हैं। रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' और यश की 'टॉक्सिक'। दोनों ही फिल्में 19 मार्च 2026 को रिलीज हो रही हैं। 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर जबर्दस्त तरीके से सफल रही। इसके दूसरे पार्ट का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ, 'टॉक्सिक' का भी क्रेज है। संभवतः इन दोनों फिल्मों से भिड़ंत से बचने के लिए मेकर्स ने सनी देओल की 'गबरू' की रिलीज में बदलाव किया है।

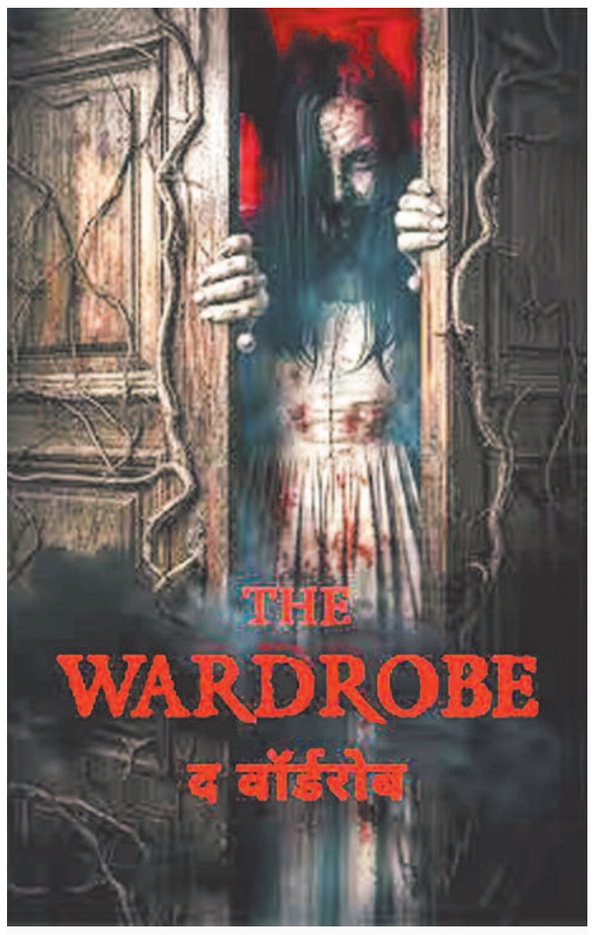

'द वॉर्डरोब' से होगा दिव्या अग्रवाल का बॉलीवुड डेब्यू

अपकमिंग बॉलीवुड हॉरर फिल्म 'द वॉर्डरोब' का फर्स्ट-लुक पोस्टर आ गया है। टीवी रियलिटी शोज की विजेता रह चुकीं दिव्या अग्रवाल इस फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं।

पोस्टर में एक पुरानी, आधी खुली लकड़ी की अलमारी से एक रहस्यमयी महिला बाहर आती दिखाई दे रही है। अलमारी के अंदर से निकलती लाल रोशनी उसके खून से सने सफेद गाउन को और डरावना बना रही है। चारों ओर धुआं, गहरे साए और खौफ का माहौल, पूरा सीन किसी डरावने सपने जैसा लगता है। लाल रंग में लिखा फिल्म का टाइटल 'द वॉर्डरोब' अंधेरे बैकग्राउंड पर और भी डरावना एहसास दे रहा है। दिव्या ने कहा, 'इस फिल्म ने मुझे एक कलाकार के तौर पर चैलेंज किया। कहानी बहुत ग्रिपिंग और एटमॉस्फेरिक है। मैं चाहती हूं कि दर्शक इसे जल्द से जल्द देखें।' वहीं रजनीश दुग्गल ने भी फिल्म की स्क्रिप्ट की तारीफ करते हुए कहा कि इसमें सस्पेंस और साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स का शानदार बेलेंस है।

फिल्म की कहानी एक साधारण-सी दिखने वाली अलमारी से शुरू होती है, जो धीरे-धीरे डरावनी घटनाओं की एक लंबी कड़ी को जन्म देती है। ट्विस्ट, शॉक और रहस्य से भरी यह कहानी दर्शकों को सीट से बांधे रखने पर मजबूर कर सकती है। फिल्म 24 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

फिल्म बनाने के लिए प्रियंका ने किया प्रेरित

मीरा चोपड़ा साउथ और बॉलीवुड फिल्मों के अलावा प्रियंका चोपड़ा की कजिन बहन के तौर पर पहचानी जाती हैं। शादी के बाद वह फिल्मों से दूर थीं लेकिन अब बतौर फिल्ममेकर उन्होंने साइलेंट फिल्म 'गांधी टॉक्स' के साथ वापसी की। हमसे खास बातचीत में उन्होंने अपने करियर, प्रियंका चोपड़ा की सलाह सहित कई विषयों पर बात की।

बतौर फिल्ममेकर डेब्यू करने के बाद क्या वह आगे अपनी फिल्म में बहन प्रियंका चोपड़ा को कास्ट करने के बारे में सोचती हैं। इस सवाल के जवाब में उन्होंने हंसते हुए कहा, 'नहीं...नहीं। अभी तो मैं वो नहीं कर सकती। मैं अभी उनको एफोर्ड ही नहीं कर सकती हूं। मैं कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोचती हूं। हां जब बड़ी फिल्ममेकर बन जाऊंगी तो एक दिन अपनी फिल्म में प्रियंका को कास्ट करना चाहूंगी।'

बिजनेस में हाथ आजमाने के मीरा के फैसले पर बहन प्रियंका चोपड़ा का क्या रिएक्शन था? इस बारे में वह बताती हैं, 'मैंने सीधे उन्हें अपनी फिल्म (गांधी टॉक्स) का टीजर भेजा। मैंने उनको बताया कि ये फिल्म मैंने प्रोड्यूस की है। उनको इस पर बहुत गर्व महसूस हुआ। प्रियंका का व्यवहार कुछ ऐसा है कि हम में से कोई जब कुछ अच्छा करता है, तो वह बहुत गौरवान्वित महसूस करती हैं। प्रियंका ने मुझे कहा था कि फिल्म बनाना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है, आपने टीजर बना दिया है तो प्लीज अब फिल्म बनाओ। दरअसल, उन्होंने इस इंडस्ट्री में ही नहीं, बल्कि इस वर्ल्ड में जिस तरह से अपनी पहचान बनाई है, वो ग्लोबल स्टार बन चुकी हैं। जब आपके परिवार में ऐसा कोई होता है तो आप उससे प्रेरित होते हैं। आप पहले उसको देखते हैं। हमेशा एक चाह थी कि मैं कुछ ऐसा करूं कि प्रियंका कहे कि मुझे तुम पर गर्व है और उन्होंने ऐसा कहा, ये मेरे लिए ये बड़ी है।

एक्टिंग में लगातार काम नहीं मिलता

एक इंटरव्यू में मीरा ने कहा था कि वह स्क्रीन पर वापसी के लिए लोगों के संपर्क में हैं। लेकिन अब वह बतौर फिल्ममेकर वापसी कर रही हैं। क्या शादी के बाद एक्टिंग में लौटना उनके लिए चुनौती भरा फैसला है? इस पर वह कहती हैं, 'मेरे सामने ऐसी कोई चुनौती नहीं आई। लेकिन एक्टिंग में क्या है कि आपको दो साल काम नहीं मिला तो आप काम नहीं करोगे, फिर एकदम से एक ही साल में दो प्रोजेक्ट आ जाएं तो आप काम करोगे। दरअसल, एक्टिंग ऐसा पेशा नहीं है कि लगातार आपको काम दे ही देगा। मैं ऐसा प्रोफेशन चाहती थी कि आपका लगातार काम चलता रहे, इसलिए मैंने प्रोडक्शन का काम शुरू किया। वो मेरे कंट्रोल में है कि मुझे कब क्या बनाना है, क्या करना है।

एक्टिंग में तो जब प्रोजेक्ट मिलेगा, जब आपको कुछ अच्छा लगेगा तब आप कर पाओगे। मैंने तीन साल काम करने के बाद फिर सोचा कि अब एक्टिंग में वापसी करूंगी और बहुत जल्द मैं आपको स्क्रीन पर दिखूंगी। एक्टिंग मेरा प्यार है, मैं जिंदगी में चाहे कुछ भी करूं, एक्टिंग नहीं छोड़ूंगी।'

फिल्म के गाने बनाने में समय लग गया

साइलेंट फिल्म के साथ बतौर प्रोड्यूसर वापसी करना और फिल्म की स्क्रीनिंग के लंबे समय बाद रिलीज करना कितनी बड़ी चुनौती थी? इस बारे में वह कहती हैं, 'जब हमने स्क्रीनिंग की थी तो हमारा मकसद था कि इतना बड़ा स्टेप उठाने पर लोगों का रिएक्शन कैसा रहेगा, जो कि काफी अच्छा था। फिर हमने एक बड़ा बदलाव किया कि फिल्म का संगीत पांच भाषाओं में बनाएंगे, क्योंकि फिल्म में डायलॉग नहीं थे तो फिल्म को एक भाषा में रिलीज करना हमें सही नहीं लगा। इसलिए ए.आर रहमान सर ने शुरू से फिल्म का संगीत बनाना शुरू किया। हिंदी के गाने पहले से ही तैयार थे, तमिल, मलयालम, तेलुगु, मराठी के गाने बनाने शुरू किए। उसमें एक साल और लग गया। लेकिन हमारी मंशा थी कि चाहे एक-दो साल लग जाएं लेकिन जब फिल्म दर्शकों के सामने आए तो लोगों की वाहवाही मिले।

दर्दनाक हादसा-घर में लगी भीषण आग, एक ही परिवार के छह लोग जिंदा जले, महिला घायल

मेरठ (एजेंसी)। यूपी के मेरठ जिले में एक मकान में आग लगने से पांच बच्चों सहित छह लोगों की मौत हो गई और एक महिला घायल हो गई। मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे ने मंगलवार को यहां बताया कि घटना किदवई नगर इलाके में बीती रात करीब आठ बजे हुई। उन्होंने बताया कि इकबाल अहमद के आवास पर आग लगने की सूचना रात आठ बजकर 49 मिनट पर मिली, जिसके बाद पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाया। उन्होंने बताया कि तीन मिनट के भीतर, डायल 112 पुलिस प्रतिक्रिया वाहन मौके पर पहुंच गया और उसके तुरंत बाद दमकल की गाड़ियां भेजी गईं। पुलिस के मुताबिक, घर में सिलाई का काम होता था और बड़ी मात्रा में कपड़े रखे हुए थे जिससे आग की लपटें तेजी से फैलने लगीं। उन्होंने कहा कि इलाके में संकरी गलियों के कारण दमकल वाहनों को घटनास्थल तक पहुंचने में चुनौती पेश आती है इसीलिए अग्निशमन विभाग के बेड़े में शामिल की गईं नयी मोटरसाइकिलों को भेजा गया। एसएसपी ने बताया कि एक स्थानीय निवासी ने भी फंसे लोगों को निकालने में मदद के लिए सीढ़ी लगाकर बचाव प्रयासों में सहायता की। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने का संदेह है और विस्तृत जांच की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना में सात लोग झुलसे हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में चिकित्सकों ने उनमें से छह लोगों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान रुखसार (25), महबीश (12), हम्माद (चार), अकदस (चार), नबिया (चार माह) और इनायत (चार माह) के रूप में की गई है, जो किदवई नगर में सुराही वाली मस्जिद के पास गली नंबर तीन के निवासी थे। एसएसपी ने बताया कि घायल महिला अमीर बानो (55) का उपचार किया जा रहा है। परिवार के एक सदस्य मोहम्मद फारूक ने कहा कि जब उन्हें आग लगने की सूचना मिली तो वह नमाज पढ़ने गए थे।

नीतिश के मंत्री का राहुल गांधी पर हमला, देश की जनता अब उन्हें गंभीरता से नहीं लेती

पटना (एजेंसी)। बिहार में नीतिश सरकार में मंत्री मंगल पांडे ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि देश की जनता अब उन्हें गंभीरता से बिल्कुल नहीं लेती। राहुल गांधी की पहचान अब इसतरह के नेता के तौर पर है जो देश की छवि को धूमिल करने का काम कर रहा हैं, लेकिन राहुल गांधी को सफलता हाथ नहीं लग रही है। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एआई समिट में यूथ कांग्रेस के शर्टलेस विरोध पर नीतिश सरकार में मंत्री पांडे ने कहा कि जब भी भारत को बदनाम करने या देश की इमेज खराब करने के लिए कांग्रेस सबसे आगे रहती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी तेजी से मजाक का विषय बनते जा रहे हैं। इसकारण भारत की जनता राहुल गांधी को कभी गंभीरता से नहीं लेती। मंत्री पांडे ने कहा कि एआई समिट विश्व का मंच था, जहां 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा वहां जिस तरह का प्रदर्शन हुआ है, वह निंदनीय है। कांग्रेस के इस प्रोटेस्ट से सभी को बहुत आघात पहुंचा है। कांग्रेस के लोग पता नहीं कि अब लोकतंत्र में क्या दिखाना क्या चाहती है। कांग्रेस ने शर्टलेस प्रोटेस्ट से देश की छवि को खराब करने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस को सफलता नहीं मिली। भाजपा नेता अश्विनी कुमार चौबे ने इंडिया एआई समिट में यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट पर कहा कि आपने देखा कि एआई समिट में 140 देशों के प्रतिनिधियों का कॉन्फ्रेंस चल रहा था और किस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा एक छोटी-सी बात को लेकर भारत की छवि को दुनिया के सामने खराब करने की कोशिश की गई।

लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में नमाज पढ़ने पर 13 छात्रों को नोटिस

लखनऊ (एजेंसी)। रमजान के महीने में लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में नमाज पढ़ने को लेकर पुलिस प्रशासन ने छात्रों के खिलाफ कार्रवाई कर दी है। लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर स्थित लाल बारादरी में नमाज पढ़ने के प्रकरण में प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई कर 13 छात्रों को नोटिस दे दिया है। सहायक पुलिस आयुक्त/ कार्यपालक मजिस्ट्रेट, महानगर कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा के तहत जारी नोटिस में आरोप लगाया गया है कि संबंधित छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में लाल बारादरी के पास चल रहे निर्माण कार्य को बाधित करने का काम किया। कैंटीन के सामने सड़क पर बैठकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थान पर नमाज पढ़ने की कोशिश की, जिससे शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका उत्पन्न हुई। पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर जारी आदेश में कहा गया है कि इन गतिविधियों से विश्वविद्यालय परिसर में तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई और भविष्य में लोक शांति भंग होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने सभी 13 छात्रों को निर्देश दिया है कि वे एक वर्ष तक शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की गारंटी के रूप में 50 हजार का व्यक्तिगत मुचलका और 50-50 हजार के दो जमानतदार प्रस्तुत करें। लखनऊ यूनिवर्सिटी परिसर की लाल बारादरी का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें हिंदू छात्रों ने चेन बनाकर मुस्लिम छात्रों को नमाज पढ़ने में मदद की थी। सोमवार को छात्रों के दूसरे संगठन ने इसके विरोध में प्रदर्शन किया था। आरोप है कि लाल बारादरी में रेनोवेशन का काम चल रहा है। इसके बावजूद छात्र यहां नमाज अदा करने पहुंचे थे। जब छात्रों को नमाज पढ़ने से रोका गया तब हिंदू छात्रों ने बैरिकेटिंग को गिरा दिया और ह्यूमन चेन बनाकर खड़े हो गए। इसके बाद छात्रों ने नमाज अदा की और रोजा खोला।

अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर महंगे आभूषण, लग्जरी घड़ियां और विदेशी मुद्रा के साथ महिला गिरफ्तार

नई दिल्ली (एजेंसी)। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई कर एक महिला यात्री को अवैध रूप से महंगे आभूषण, लग्जरी घड़ियां और विदेशी मुद्रा लाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। अमेरिकी पासपोर्ट धारक यह महिला हांगकांग से फ्लाइट नंबर सीएक्स-695 द्वारा टर्मिनल-3 पर पहुंची थी। महिला पर संदेह होने पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने उन्हें रोका और सामान की एक्स-रे जांच की। निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत विस्तृत तलाशी लेने पर भारी मात्रा में अघोषित विदेशी सामान बरामद हुआ।

बंगाल के एसआईआर में लाखों दावों-आपत्तियों से निपटेंगे झारखंड-ओडिशा के जज

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के एसआईआर में 80 लाख दावों और आपत्तियों से निपटने के लिए सिविल जजों को नियुक्त करने और पड़ोसी राज्यों झारखंड व ओडिशा से न्यायिक अधिकारियों को बुलाने की अनुमति दे दी है। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के एक पत्र पर संज्ञान लिया, जिसमें कहा गया था कि एसआईआर कवायद के लिए तैनात 250 जिला न्यायाधीशों को दावों और आपत्तियों से निपटने में करीब 80 दिन लगेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गंभीर स्थिति और समय की कमी को ध्यान में रखते हुए पीठ ने प्रक्रिया संचालित करने के लिए सिविल जजों की तैनाती की अनुमति दी। उसने कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से झारखंड और ओडिशा के अपने समकक्षों से

अनुरोध करने और स्थिति से निपटने के लिए समान पदों के न्यायिक अधिकारियों की मांग करने को कहा। पीठ ने निर्वाचन आयोग को झारखंड और ओडिशा से न्यायिक अधिकारियों की तैनाती का खर्च वहन करने का निर्देश भी दिया। हाई कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को 28 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने की अनुमति भी दी और स्पष्ट किया कि सत्यापन प्रक्रिया आगे बढ़ने पर चुनाव आयोग पूरक सूचियां जारी कर सकता है। वर्ष 2002 की मतदाता सूची से पारिवारिक संबंध जोड़ने में तार्किक विसंगतियों में ऐसे मामले शामिल हैं, जिनमें माता-पिता के नाम में असंगति पाई गई है और मतदाता व उसके माता-पिता के बीच आयु का अंतर 15 साल से कम या 50 साल से ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी को पश्चिम बंगाल सरकार और निर्वाचन आयोग के बीच गतिरोध से निराश होकर राज्य में विवादों से घिरे एसआईआर में आयोग की सहायता के लिए सेवारत और पूर्व जिला न्यायाधीशों को तैनात करने का एक निर्देश जारी किया था। चुनाव आयोग और बंगाल में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई टीएमसी सरकार के बीच दुर्भाग्यपूर्ण आरोप-प्रत्यारोप और विश्वास की कमी पर अफसोस जताते हुए पीठ ने एसआईआर प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कई नए निर्देश पारित किए थे।

गुटखे के प्रचार को लेकर हाईकोर्ट सख्त, शाहरुख, अजय देवगन और अक्षय कुमार को भी बनाया पक्षकार

लखनऊ (एजेंसी)। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खण्डपीठ ने गुटखा कंपनियों का प्रचार करने के मामले में अपने पूर्व के आदेश के पालन के संबंध में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण को जवाब देने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई छह अप्रैल को होगी। मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव की जनहित याचिका पर दिया है। दरअसल, हाईकोर्ट ने 25 नवंबर 2025 को हुई सुनवाई के दौरान प्राधिकरण से पूछा था कि 2023 में याची के प्रत्यावेदन पर अब तक जांच लंबित क्यों है? याचिका में गुटखा कंपनियों के साथ क्रिकेटर कपिल देव, सुनील गावस्कर, वीरेंद्र सहवाग, क्रिस गेल तथा अभिनेताओं अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सलमान खान, रितिक रोशन, टाइगर श्राफ, सैफ अली खां व रणवीर सिंह को भी पक्षकार बनाया गया है। याचिका में कहा गया है कि ये हस्तियां जो पान मसाला कंपनियों का प्रचार कर रही हैं उनमें से अधिकांश पद्म पुरस्कार धारक हैं और उनकी ओर से किए जाने वाले ऐसे विज्ञापनों से समाज में गलत संदेश जाता है। ये विज्ञापन उपभोक्ता कानूनों का उल्लंघन भी है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी राष्ट्रविरोधी ताकतों के प्रवक्ता बन चुके: अनुराग ठाकुर

कांगड़ा (एजेंसी)। भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी राष्ट्रविरोधी ताकतों के प्रवक्ता बन चुके हैं। कांगड़ा में भाजपा सांसद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कई गंभीर आरोप लगाए। सांसद ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी देश विरोधी ताकतों के प्रवक्ता बने हुए हैं। वह भारत में रहकर और भारत के बाहर रहकर देश विरोधी एजेंडा चलाते हैं, इतना ही नहीं नकारात्मक पॉलिटिक्स को बढ़ावा देकर अराजकता फैलाने का प्रयास करते हैं। अब उनका एकमात्र काम झूठ बोलना, कन्फ्यूजन पैदा करना, भारत को बदनाम करना और मोदी विरोधी राजनीति करना है। जब भारत की इकॉनमी सबसे तेजी से बढ़ रही है, तब वह भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकॉनमी कहते हैं। उन्हें भारत की तरक्की पसंद नहीं है। भाजपा सांसद ने कहा कि पूरी दुनिया ने एआई समिट की तारीफ की, वहां राहुल गांधी के इशारे पर उनके कार्यकर्ता शर्टलेस प्रदर्शन कर देश की छवि को धूमिल करने की कोशिश की। क्या राहुल गांधी की राजनीति विदेशों से तय हो रही है। कांग्रेसी विदेशियों का एजेंडा चला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जॉर्ज सोरेस के कहने पर चल रही है। कांग्रेस पार्टी राजीव गांधी फाउंडेशन में चंदा ले रही है और फिर चीन का गुणगान कर रही है।

उन्होंने कहा कि आज राहुल का मतलब क्या हो गया है? आर से रार, ह से हुडदंग, ल से लंफगई। उनकी जगहंसाई हो रही है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या राहुल गांधी सच में नेता प्रतिपक्ष हैं।

भाजपा सांसद ने कहा कि संसद में महिला सांसदों को भेजकर पीएम की सीट का घेराव करना किस तरह की राजनीति है। विदेशी मंचों पर जाकर राहुल गांधी बयान देते हैं। एक के बाद एक झूठ बोलते हैं, उनका यही काम रह गया है। कांग्रेस अराजकता, अफवाह और दंगा फैलाने की हरसंभव कोशिश कर रही है। राहुल गांधी जो सोच रहे हैं, वह सफल नहीं हो सकते है।

कांग्रेस डरपोक नहीं, संविधान की रक्षा के लिए जो भी त्याग करना पड़ेगा करेंगे

मल्लिकार्जुन खड़गे ने उदय भानु चिब की गिरफ्तारी को लेकर दी तीखी प्रतिक्रिया

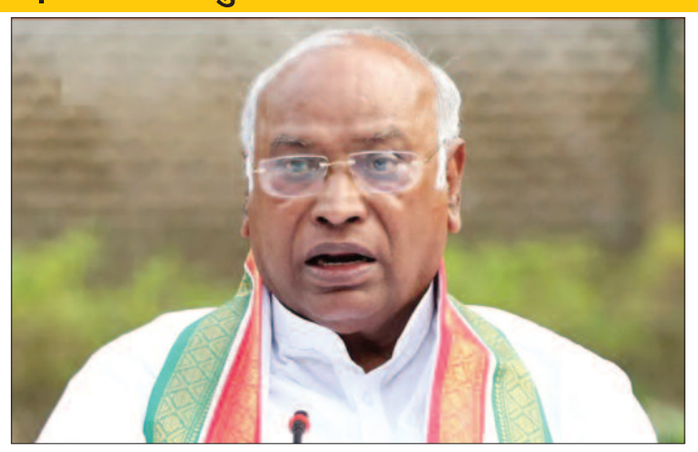

बेंगलुरु (एजेंसी)। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब की गिरफ्तारी को लेकर कहा कि वे हमारे युवा नेताओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस न तो डरपोक है और न ही डरने वाली है। लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए जो भी त्याग करना पड़ेगा, हम करेंगे।

बेंगलुरु में मीडिया से बातचीत में खड़गे ने कहा कि जब कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे थे, तो नितिन गडकरी और बीजेपी नेताओं ने क्या किया? ऐसे हर इवेंट में वे देश की भावना को समझने में नाकाम रहे। उन्होंने यह नहीं सोचा कि इससे उस समय भारत और विदेश के एथलीटों को क्या संदेश जाएगा। बीजेपी दूसरों के बारे में तो बहुत कुछ कहती है, लेकिन अपने गिरेबान में नहीं झांकती है। अगर वे अपने गिरेबान में झांकेंगे, तो शायद उन्हें अपनी सच्चाई दिखाई देगी। मैं यूथ कांग्रेस अध्यक्ष भानु की गिरफ्तारी की निंदा करता हूं।

रिपोर्ट के मुताबिक खड़गे ने कहा कि युवा आज नौकरी के लिए तड़प रहे हैं और देश का माहौल इतना खराब हो चुका है कि उसके कारण केंद्र सरकार के प्रति लोगों में भारी रोष है। मैं चाहता था कि पीएम मोदी देश के लिए कुछ अच्छा कार्य करें, लेकिन केंद्र सरकार नहीं कर रही है। हमारी सरकार वह कर रही है जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं। ऐसा लगता है कि ट्रंप के सामने सरकार ने घुटने टेक दिए हैं। उन्होंने भारत-अमेरिका ट्रेड डील से किसानों का नुकसान होगा। हमें बंधुआ मजदूर बनाने की दिशा में धकेला जा रहा है।

खड़गे ने कहा कि सरकार की ओर से कांग्रेस को डराया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस डरने वाली नहीं है और न ही डरपोक है। हमारे देश में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए जो भी त्याग करना पड़ेगा, हम करेंगे। हम लड़ते रहेंगे और सरकार के खिलाफ संघर्ष जारी रखेंगे। उन्होंने एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद पुलिस की कार्रवाई पर कहा कि प्रदर्शन करने के बाद अगर हिरासत में लिया जाता है तो पुलिस कुछ देर बाद छोड़ देती है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस को निशाना बनाकर डर पैदा करने के लिए काम कर रहे हैं और कांग्रेस डरने वाली नहीं है।

केरल का नाम बदलकर 'केरलम' करने पर थरुर का मजाकिया अंदाज

नई दिल्ली (एजेंसी)। केरल का नाम बदलकर 'केरलम' करने की चर्चा के बीच कांग्रेस सांसद शशि थरुर ने एक दिलचस्प लेकिन अहम भाषाई सवाल उठा दिया है। तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद थरूर ने अपनी पोस्ट पर प्रतिक्रिया देकर कहा कि नाम परिवर्तन सभी के लिए अच्छा कदम हो सकता है, लेकिन अंग्रेज़ी बोलने वालों के लिए एक छोटा सा भाषाई प्रश्न खड़ा होता है। उन्होंने हल्के-फुल्के अंदाज़ में पूछा कि अगर राज्य का नाम 'केरलम' हो जाएगा, तब वहां के निवासियों को क्या कहा जाएगा....केरलाइट', 'केरलन' या कुछ और?

कांग्रेस सांसद थरूर ने मजाकिया लहजे में लिखा कि 'केरलमाइट' शब्द सुनने में किसी सूक्ष्म जीव (माइक्रोब) जैसा लगता है, जबकि 'केरलमियन' किसी दुर्लभ खनिज (रेयर अर्थ मटीरियल) की तरह प्रतीत होता है। उन्होंने केरल के सीएम ऑफिस को टैग कर सुझाव दिया कि शायद मुख्यमंत्री नए शब्द के चयन के लिए कोई प्रतियोगिता आयोजित कर सकते हैं। उनका यह बयान तब आया है जब केंद्र की मोदी सरकार राज्य का नाम आधिकारिक रूप से 'केरलम' करने सहमति जता चुकी है।

महाराष्ट्र से एनसीपी पार्थ पवार को राज्यसभा चुनाव में उतारेगी, बीजेपी के अंदर नामों को लेकर मंथन

-शिवसेना शिंदे गुट के लिए एक सीट सुरक्षित

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र की सात राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव से पहले महाराष्ट्र में सियासत में हलचल तेज हो गई है। महायुति की सरकार में शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) ने इस लेकर अपने उम्मीदवार पर बड़ा फैसला लिया है। सूत्रों के अनुसार, सोमवार की रात प्रफुल्ल पटेल के आवास पर पार्टी की कोर कमेटी की हुई बैठक में पार्थ पवार को राज्यसभा चुनाव में उतरने पर सहमति बनी है। बैठक में प्रफुल्ल पटेल के अलावा उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल थे। 26 फरवरी को होने वाली बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पर मुहर लग सकती है, जहां सुनेत्रा पवार का नाम सबसे आगे माना जा रहा है।

दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) भी अपने उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में जुटी हुई है। पार्टी इस बार राज्यसभा की चार सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। इसमें रामदास अठावले का नाम करीब तय है, जबकि विनोद तावड़े, विजया रहाटकर और धैर्यशील पाटिल के नामों पर अंतिम निर्णय होना बाकी है।

बात दें कि महाराष्ट्र में इस बार राज्यसभा की 7 सीटें खाली हैं और 286 विधायकों के आधार पर एक उम्मीदवार को जीत के लिए 37 वोटों की जरूरत होगी। आंकड़ों के अनुसार, सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के पास स्पष्ट बढ़त है। सिर्फ बीजेपी के पास एक निर्दलीय को मिलाकर कुल (131+1) यानी 132 विधायकों का समर्थन है, इस संख्याबल के दम पर 3 से 4 सांसद आसानी से भेज सकती है। वहीं शिवसेना (शिंदे गुट) अपने 58 विधायकों के साथ एक सीट सुरक्षित कर सकती है, जबकि एनसीपी (अजित पवार गुट) भी एक सीट जीतने की स्थिति में है, क्योंकि अजित पवार की मौत के बाद उसके पास 40 विधायक हैं।

इसके मुकाबले महाविकास अघाड़ी (एमवीए), जिसमें कांग्रेस, एनसीपी (शरद पवार गुट) और शिवसेना (ठाकरे गुट) शामिल हैं, के पास कुल मिलाकर करीब 49 विधायकों का समर्थन है। इस संख्या के आधार पर एमवीए केवल एक सीट ही सुरक्षित कर सकती है। राजनीतिक समीकरणों के हिसाब से महायुति गठबंधन 6 सीटों पर मजबूत दिख रहा है, जबकि विपक्षी गठबंधन को सीमित सफलता मिलने की संभावना है।

उड़ान भरते ही विमान इंजन हुआ फेल, दिल्ली एसरपोर्ट पर कराई आपात लैंडिंग

-कॉकपिट में नहीं मिला फायर वार्निंग संकेत, विमान में सवार थे 150 यात्री

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली से लेह जा रहे स्पाइस जेट विमान की मंगलवार उड़ान भरने के तुरंत बाद ही विमान में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण लेह जाने के बजाय दिल्ली एयरपोर्ट पर इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। विमान में करीब 150 यात्री सवार थे। इस घटना में किसी को नुकसान नहीं हुआ है। मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इंजन नंबर-2 फेल होने से इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। लैंडिंग के बाद यात्रियों के लिए यात्रा की वैकल्पिक व्यवस्था की उम्मीद है। स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने बताया कि तकनीकी खराबी के चलते दिल्ली से लेह जा रहे विमान को वापस बुलाना पड़ा। विमान की सुरक्षित लैंडिंग हुई और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। कॉकपिट में फायर वार्निंग का कोई संकेत नहीं मिला।

रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि फ्लाइट एसजी121 दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से निकली थी। टेक ऑफ के तुरंत बाद ही क्रू मेंबर्स को तकनीकी खराबी का पता चला। सावधानी बरतते हुए पायलटों ने विमान को दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करने का फैसला लिया। विमान की पूरे प्रोटोकॉल के साथ लैंडिंग करवाने के बाद सुरक्षा एजेंसियों के साथ मेडिकल टीम और फायर सर्विस भी वहां मौजूद थी।

बता दें इससे पहले असम के डिब्रूगढ़ से कोलकाता के लिए उड़ान भरने वाली इंडिगो एयरलाइन के एक विमान में 14 फरवरी को बम होने की धमकी मिली थी जिसके बाद विमान की तुरंत ही इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। वहीं बीते साल 2 दिसंबर को कुवैत से हैदराबाद आ रही इंडिगो के एक विमान में बम की धमकी के बाद मुंबई में उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई थी। विमान में बम की चेतावनी की धमकी ई-मेल से मिली थी जो कि बाद में फर्जी निकली। वहीं बीते साल ही 12 नवंबर को एयर इंडिया एक्सप्रेस के मुंबई से वाराणसी जा रहे विमान के टॉयलेट में कागज पर बम लिखा मिलने के बाद वाराणसी में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई थी।

कांग्रेस गुटबाजी, अविश्वास और सहयोगी दलों के साथ तालमेल की कमी से हाशिये पर!

नई दिल्ली (एजेंसी)। असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा के इस्तीफा देने के बाद पार्टी की लगातार गिरती राजनीतिक स्थिति और केंद्रीय नेतृत्व की भूमिका पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। बोरा ने चुनाव से ठीक पहले पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है, जिससे संगठनात्मक कमजोरी और आंतरिक कलह तेज हो गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कई राज्यों में कांग्रेस की इकाइयां अंदरूनी गुटबाजी, आपसी अविश्वास और सहयोगी दलों के साथ तालमेल की कमी के कारण हाशिये पर आ रही है। आलोचकों के मुताबिक शीर्ष नेतृत्व की निर्णय प्रक्रिया में कथित 'सुस्ती' और समय पर हस्तक्षेप न कर पाने की प्रवृत्ति पार्टी के लगातार क्षरण का कारण बन रही है।

कर्नाटक में सीएम सिद्दारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच सत्ता संतुलन को लेकर लंबे समय से खींचतान चल रही है। बताया जाता है कि राहुल गांधी की मुलाकातों के बावजूद मतभेद खत्म नहीं हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रतिभा सिंह गुटों के बीच प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर संघर्ष जारी है। पार्टी ने राज्य इकाई भंग कर संतुलन साधने की कोशिश की, लेकिन असंतोष बना रहा। दिल्ली में जहां कभी शीला दीक्षित के नेतृत्व में 15 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, पार्टी आज एकजुट चेहरा पेश करने में नाकाम है।

वहीं हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा के बीच मतभेदों ने 2025 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाया। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच टकराव ने पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया। बाद में चरणजीत सिंह चन्नी को जिम्मेदारी दी गई, लेकिन तब तक काफी क्षति हो चुकी थी। यूपी में संगठन भंग करने के बावजूद कांग्रेस पुनर्जीवित नहीं हो पाई। पूर्वोत्तर राज्यों, खासकर असम और अरुणाचल प्रदेश में भी पार्टी अव्यवस्था का सामना कर रही है। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी ने कांग्रेस से दूरी बना ली है। झारखंड में हेमंत सोरेन की पार्टी के साथ गठबंधन भी अपेक्षित परिणाम नहीं दे सका।

बिहार में राजद के साथ गठबंधन के बावजूद कांग्रेस को 'बोझ' के रूप में देखा गया। ओडिशा में संगठन लगातार कमजोर हो रहा है। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच टकराव को 2023 में सत्ता गंवाने की बड़ी वजह माना गया। गुजरात और महाराष्ट्र में भी पार्टी दो दशक से ज्यादा समय से बीजेपी को चुनौती देने में विफल रही है। तमिलनाडु में द्रमुक के साथ गठबंधन के बावजूद सीट बंटवारे को लेकर मतभेद उभरे हैं, जिससे आगामी चुनावों से पहले असहज स्थिति बन रही है। कुल मिलाकर कई राज्यों में लगातार गुटबाजी, नेतृत्व संकट और सहयोगियों के साथ तालमेल की कमी ने कांग्रेस की स्थिति को कमजोर किया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या चुनौतियों के लिए शीर्ष नेतृत्व जिम्मेदार है।

स्वामी, प्रकाशक, अनीता शर्मा द्वारा मुद्रक, रजनी कुमारी- मैसर्स साई प्रिंटिंग प्रेस D-85 सेक्टर-6 नोएडा, गौतमबुद्धनगर से मुद्रित एवं जी-271 एचआईजी, प्रताप विहार, सेक्टर-11, गाजियाबाद (उ०प्र०) से प्रकाशित। संपादक -अतुल शर्मा *
ईमेल-rashtriyashikhar@gmail.com (समस्त विवादों का क्षेत्र गाजियाबाद न्यायालय रहेगा) (* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों हेतु उत्तरदायी)
समाचार संपादक-आरव शर्मा (एडवोकेट) 9310230557, 9625163807
(PRGI No. - UPHIN/25/A0086)